



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23]
No. 23]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 6, 1998/ज्येष्ठ 16, 1920
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6, 1998/JYAISTHA 16, 1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

स्टाम्प

का.आ. 1085 --- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमि० नई दिल्ली को मात्र चौदह लाख रु. का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति देती है, जो कि उक्त निगम द्वारा 20 मार्च, 1997 को प्रार्थित किया गया मात्र पैंतीस करोड़ रु. के कुल मूल्य के 1 से 35000 तक की विविध संख्या वाले दस-दस हजार रु. के प्रोमिसरी नोटों के स्वल्प वाले एन एस आई सी सुरक्षित बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रयोज्य है।

[सं. 20 /98-स्टाम्प-फा.सं. 15/13/98-वि.क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 19th May, 1998

STAMPS

S.O. 1085.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the National Small Industries Corporation Limited, New Delhi to pay consolidated stamp duty of rupees fourteen lakhs only chargeable on account of the stamp duty on NSIC Secured Bonds in the form of Promissory notes of rupees ten thousand each bearing distinctive numbers from 1 to 35000 aggregating to rupees thirty five crores only allotted on 20th March, 1997, by the said corporation.

[No. 20/98-STAMPS-F.No. 15/13/98-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 25 मई, 1998

का. आ. 1086.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार मैसर्स ग्लोबल हाउसिंग फाईनेंस कारपोरेशन लि., ए. विंग, 307, मिटल टावर्स नरीमन प्वाइंट्स मुम्बई-21 को कर-निधारण वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के प्रयोजनार्थ एवं आवास वित्त कम्पनी के रूप में अनुमोदित करती है।

यह अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के उपबन्धों के अनुरूप होगी तथा उनका अनुपालन करेगी।

[अधिसूचना सं. 10616 फा. सं. 204/21/96-आयकर नि.-II]

मालती आर. श्रीधरन, अवर सचिव

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 25th May, 1998

S.O. 1086.—It is notified for general information that M/s. Global Housing Finance Corporation Ltd., A-Wing, 307, Mittal Towers Nariman Points, Mumbai-21 have been approved by the Central Government as a Housing Finance Company for the purposes of section 36 (1)(viii) of the Income-tax Act, 1961, for the assessment years 1997-98 to 1999-2000.

The Approval is subject to the condition that the company will conform to and comply with

the provisions of Section 36 (1) (viii) of the Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 10616/F. No. 204/21/96-ITA-II]

MALATHI R. SRIDHARAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 मई, 1998

का. आ. 1087.—सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार बेरार हाउसिंग फाईनेंस लि. जे. पी. चैम्बर्स, साउथ अम्बाजरी रोड, श्रद्धानन्द पीठ, नागपुर का कर निर्धारण वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के प्रयोजनार्थ एक आवास वित्त कम्पनी के रूप में अनुमोदित करती है।

यह अनुमोदन इस शर्त पर किया जाता है कि कंपनी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के उपबन्धों के अनुरूप होगी और उनका अनुपालन करेगी।

[अधिसूचना सं. 10617 फा. सं. 204/31/96-आयकर नि. II]

मालती आर. श्रीधरन, अवर सचिव

New Delhi, the 25th May, 1998

S.O. 1087.—It is notified for general information that Berar Housing Finance Limited, J.P. Chambers, South Ambazari Road, Shradhdhanand-peth, Nagpur has been approved by the Central Government as a Housing Finance Company for the purposes of Section 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961, for the assessment years 1997-98, 1998-99 & 1999-2000.

The Approval is subject to the condition that the company will conform to and comply with the provisions of Section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961.

[Notification No. 10617/F.No. 204/31/96-ITA-II]

MALATHI R. SRIDHARAN, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1998

का. आ. 1088.—भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ड) के उपखण्ड (घ) के अन्तर्गण में केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री एम. दामोदरन, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली को श्री डी. आर. एस. चौधरी के स्थान पर भारतीय निर्यात-आयात बैंक में निदेशक के रूप में नामित करती है।

[एफ. सं. 9/9/98-बी. ओ. I (i)]

सुधीर श्रीवास्तव, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 22nd May, 1998

S.O. 1088.—In pursuance of sub-clause (i) of clause (e) of sub-clause (1) of section 6 of the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government hereby nominates Shri M. Damodaran, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi as a director of Export-Import Bank of India vice Shri D. R. S. Chaudhary.

[F. No. 9/9/98-B.O.I(i)]

SUDHIR SHRIVASTAVA, Director

नई दिल्ली, 22 मई, 1998

का. आ. 1089.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 उपखण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली के निदेशक, डा. के. बी. एल. माथुर को श्री डी. आर. एस. चौधरी के स्थान पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक नामित करती है।

[एफ. सं. 9/9/98-बी. ओ. I (ii)]

सुधीर श्रीवास्तव, निदेशक

New Delhi, the 22nd May, 1998

S.O. 1089.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with sub-clause (i) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Dr. K.

B. L. Mathur, Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi as a Director of Central Bank of India vice Shri D. R. S. Chaudhary.

[F. No. 9/9/98-B.O. I(ii)]

SUDHIR SHRIVASTAVA, Director

नई दिल्ली, 22 मई, 1998

का. आ. 1090.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली के वित्तीय सलाहकार, श्री एम. आर. रायलू को श्री डी. के. त्यागी के स्थान पर सिंडिकेट बैंक का निदेशक नामित करती है।

[एफ. सं. 9/9/98-बी. ओ. I (iii)]

सुधीर श्रीवास्तव, निदेशक

New Delhi, the 22nd May, 1998

S.O. 1090.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with sub-clause (i) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri N. R. Rayalu, Financial Adviser, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi as a Director of Syndicate Bank vice Shri D. K. Tyagi.

[F. No. 9/9/98-B.O.I(iii)]

SUDHIR SHRIVASTAVA, Director

नई दिल्ली, 22 मई, 1998

का. आ. 1091.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली के निदेशक, श्री डी. के. त्यागी को युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक नामित करती है।

[एफ. सं. 9/9/98-बी. ओ. I (iv)]

सुधीर श्रीवास्तव, निदेशक

New Delhi, the 22nd May, 1998

S.O. 1091.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with sub-clause (i) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Shri D. K. Tyagi, Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi as a Director of United Bank of India.

[F. N. 9/9/98-B.O.I(iv)]

SUDHIR SHRIVASTAVA, Director

नई दिल्ली, 22 मई, 1998

का. आ. 1092.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रवृत्त और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1980 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के साथ पठित बैंककारी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव, श्री बी. एस. मीणा को डा. के. बी. एल. माथुर के स्थान पर आन्ध्रा बैंक के निदेशक के रूप में नामित करती है।

[एफ. सं. 9/9/98—बी. ओ. I (v)]

सुधीर श्रीवास्तव, निदेशक

New Delhi, the 22nd May, 1998

S.O. 1092.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section 3 of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with sub-clause (1) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby nominates Shri B. S. Meena, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, New Delhi as a Director of Andhra Bank vice Dr. K. B. L. Mathur.

[F. No. 9/9/98-B.O.I(v)]

SUDHIR SHRIVASTAVA, Director

नई दिल्ली, 21 मई, 1998

मां०आं० 1093—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर एतद्वारा, घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन (सहकारी समितियाँ) नियम, 1966 के नियम 10 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 31 के उपबन्ध दि फार्मर्स सहकारी बैंक लि०, नई दिल्ली पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के उनके तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखे एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट समाचार-पत्र में प्रकाशित करने से है।

[सं० 1(13)/98-प. सी]

एस०के० ठाकुर, अवसर सचिव

New Delhi, the 21st May, 1998

S.O. 1093.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of Section 31 of the said Act read with Rule 10 of the Banking Regulation (Co-operative Societies)

Rules, 1966 shall not apply to the Farmer's Co-operative Bank Ltd., New Delhi in so far as they relate to the publication of their balance sheet and profit and loss account for the year ended 31st March, 1997 with the auditor's report in the newspaper.

[No. 1(13)/98-AC]

S. K. THAKUR, Under Secy.

कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क

इन्दौर, 15 मई, 1998

का. आ. 1094.—श्री वार्ह. एल. गजभिरे, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय इन्दौर-II, निवर्तन आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31-03-1998 को अपराह्न में शासकीय सेवा से निवृत्त हुए।

[स. 11 (3) 4—गोप/98/389]

शोभा राम, उप आयुक्त (आर्थिक एवं सतर्कता)

OFFICE OF THE COMMISSIONER, CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Indore, the 15th May, 1998

S.O. 1094.—Shri Y. L. Gajbiye, Superintendent, Central Excise of Indore-II Commissionerate having attained the age of Superannuation retired from Government service on 31-3-1998 in the afternoon.

[F. No. 11(3) 4-Con/98/389]

SHOBHA RAM, Dy. Commissioner (P&V)

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय
(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1998

का. आ. 1095.—केन्द्रीय सरकार वायुयान नियम, 1937, के नियम 3क के उपनियम, 2 के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 6 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन नागर विमानन और पर्यटन विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 726 (अ) तारीख 4 अक्टूबर, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, :—

(क) प्रथम अनुसूची के स्तम्भ (1) में, “अध्यक्ष राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण और अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का अधिकारी” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“अध्यक्ष भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का अधिकारी”

(ख) दूसरी अनुसूची में क्रम संख्यांक 61 के सामने स्तंभ (3) में—“एयरमैन की सूचना जारी करना” शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“एयरमैन और विमानिक जानकारी प्रकाशन की सूचनाएं जारी करना”

[सं. ए. बी.-11012/17/97-ए]

वी. जे. मेनन, अव. सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर 1994 के का.आ. संख्या 726(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गयी थी।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM
(Department of Civil Aviation)

New Delhi, the 25th May, 1998

S.O. 1095.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 3-A of the Aircraft Rules, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the then Ministry of Civil

Aviation and Tourism No. S.O. 726(E), dated the 4th October, 1994, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th October, 1994, namely :—

In the said notification,—

(a) in the First Schedule, in column (1), for the entry “Chairman National Airports Authority and officer of National Airports Authority Authorised by the Chairman” the following shall be substituted namely :—

“Chairman, Airports Authority of India and officer of the Airports Authority of India authorised by the Chairman” ;

(b) in the Second Schedule, against serial No. 61, in column (3) for the words and brackets “to issue NOTAMS (Notices to Air Men)”, the following shall be substituted, namely :—

“to issue Notices to Airmen (NOTAMS) and Aeronautical Information Publication.”

[No. AV-11012/17/97-A]

V. J. MENON, Under Secy.

Footnote.—The principal notification was published in the Gazette of India vide S.O. No. 726(E) dated 4th October, 1994.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का.आ. 1096.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात राज्य में बिछाई दहेज से गंधार होकर बड़ोदा तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि पाइप लाइन के बिछाए जाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया जाए,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है,

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जससे भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इसकीस दिन के भीतर भूमि में के उपयोग के अधिकार के अर्जन या भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने के प्रति लिखित रूप से आपत्ति श्री एस. के. पटेल, सक्षम अधिकारी, दहेज-गंधार-बड़ोदा पाइप लाइन परियोजना, इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, (गंधार काम्पलैक्स) बड़ोदा 391345 को कर सकता है।

अनुसूची

तालुका (तहसील) : वागरा

जिला : भरुच

राज्य : गुजरात

ग्राम का नाम	सर्वे नं./सब डिविजन/ ब्लाक नं.	क्षेत्रफल			
		हेक्टेयर	आरे	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
दहेज	225/ए-2 भाग	00	04	00	--
दहेज	1026-भाग	00	12	00	--
दहेज	1195-भाग	00	03	02	--
दहेज	1208-भाग	00	17	00	--
कडोदरा	174-भाग	00	00	18	--

1	2	3	4	5	6
कडोदरा	572-भाग	00	33	25	---
कडोदरा	709-भाग	00	00	25	---
पदरिया	18-भाग	00	07	00	---
पनियादरा	377-भाग	00	07	75	---
पनियादरा	199-भाग	00	00	50	---
पनियादरा	197-भाग	00	01	05	---
पनियादरा	195-भाग	00	00	70	---
चांचवल	1267-भाग	00	20	60	---
चांचवल	1110-भाग	00	00	58	---

[एफ नं. आर-31015/24/97-ओ.आर.-II]

के.सो. केटाच, अवर सचिव

Ministry of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1096 .—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum products from Dahej to Baroda, via Gandhar, in the Gujarat State through Dahes-Gandhar-Baroda, pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri S.K. Patel, competent Authority, Dahej-Gandhar-Baroda Pipeline Project, India Petrochemicals Corporation Limited (Gandhar Complex), Baroda-391 345.

SCHEDULE

Taluka (Tehsil) : Vagra

District : Bharuch

State : Gujarat

Name of Village	Survey/Sub-Division or Block No.	Area			
		Hectares	Ares	Acre	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dahej	225/A-2 Part	00	04	00	---
Dahej	1026-Part	00	12	00	---
Dahej	1195-Part	00	03	20	---
Dahej	1203-Part	00	17	00	---
Kadodara	174-Part	00	00	18	---
Kadodara	572-Part	00	33	25	---
Kadodara	709-Part	00	00	25	---
Padaria	18-Part	00	07	00	---
Paniyadara	377-Part	00	07	75	---
Paniyadara	199-Part	00	00	50	---
Paniyadara	197-Part	00	01	05	---
Paniyadara	195-Part	00	00	70	---
Chanchwel	1110-Part	00	00	58	---
Chanchwel	1267-Part	00	20	60	---

[F. No. R-31015/24/97-O. R.-11]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली 19 मई, 1998

फा.आ. 1097--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज से गंधार होकर बड़ोदा तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि पाइप लाइन के बिछाए जाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिसूचना के उद्देश्य अन्तर्गामी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन कर लिया जाए।

अतः सब केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है,

उक्त अन्तर्गामी में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिससे भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि में के उपयोग के अधिकार के अर्जन या भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने के प्रति लिखित रूप से आपत्ति, श्री एस.के. पटेल, सक्षम अधिकारी, दहेज-गंधार-बड़ोदा पाइप लाइन परियोजना इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, (गंधार कॉम्प्लेक्स) बड़ोदा 391345 की कर सकते हैं।

अनुसूची

तालुका : (तहसील) अमोड

जिला : भरुच

राज्य : गुजरात

ग्राम का नाम	सर्वे नं. सब डिवीजन ब्लॉक नं.	क्षेत्रफल			
		हेक्टेयर	आरे	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
रोजा-तनकारिया	630-भाग	00	20	30	—
रोजा-तनकारिया	745-भाग	00	19	00	—
रोजा-तनकारिया	800-भाग	00	01	55	—

[एफ नं. आर-31015/24/97-ओ.आर-II]
के.सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, 19th May, 1998

S.O. 1097.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum products from Dahej to Baroda, via Gandhar, in the Gujarat State through Dahej-Gandhar-Baroda, pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interest in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri S.K. Patel, Competent Authority, Dahej-Gandhar-Baroda Pipeline Project, Indian Petrochemicals Corporation Limited (Gandhar Complex), Baroda-391 345.

SCHEDULE

Taluka (Tehsil) : Amod

District : Bharuch

State : Gujarat

Name of Village

Survey/Sub-Division or
Block No.

Area

Hectare

Ares

Acre

Cents

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Roza-Tankaria

630-Part

00

20

30

—

Roza-Tankaria

745-Part

00

19

00

—

Roza-Tankaria

800-Part

00

01

55

—

[F. No. R-31015/24/97-O.R. II]

K.C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का.आ. 1098--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज से गंधार होकर बड़ोदा तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि पाइप लाइन के बिछाए जाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अने आशय की घोषणा करती है,

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हिनवद्ध कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिसमें भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रत्यासाधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि में के उपयोग के अधिकार अर्जन के या भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने के प्रति लिखित रूप से आपत्ति, श्री एस.के. पटेल, सक्षम अधिकारी, दहेज-गंधार पाइप लाइन परियोजना, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (गंधार काम्प्लेक्स), बड़ोदा, 391 345 को कर सकता है।

अनुसूची

तालुका (तहसील) : जंबुसर

जिला : भरुच

राज्य : गुजरात

ग्राम का नाम	सर्वे नं./सब डिवीजन/ ब्लॉक नं.	क्षेत्रफल			
		हेक्टेयर	आरे	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
मराणाद	27-भाग	00	02	00	—
मराणाद	1211-भाग	00	06	20	—
मराणाद	1240-भाग	00	12	00	—
मराणाद	1266-भाग	00	00	75	—
मराणाद	1267-भाग	00	14	70	—
मराणाद	1254-भाग	00	12	00	—
मराणाद	1358-भाग	00	00	65	—
मराणाद	1367-भाग	00	04	00	—
मराणाद	1336-भाग	00	06	00	—
मराणाद	1373-भाग	00	03	06	—

1	2	3	4	5	6
मगणाद	कार्ट ट्रैक	00	00	06	—
मगणाद	1377-भाग	00	00	60	—
मगणाद	1378-भाग	00	00	70	—
मगणाद	1478-भाग	00	08	20	—
मगणाद	1479-भाग	00	00	60	—
मगणाद	1481-भाग	00	05	60	—
मगणाद	1467-भाग	00	20	80	—
अणखी	1052-भाग	00	02	40	—
उच्छद	991-भाग	00	02	70	—
उच्छद	1111-भाग	00	00	10	—
गजेरा	1501-भाग	00	00	15	—
गजेरा	1509-भाग	00	00	15	—
गजेरा	1617-भाग	00	00	15	—
गजेरा	1896-भाग	00	00	25	—
खानपुर-देह	124-भाग	00	01	12	—
खानपुर-देह	126-भाग	00	00	64	—
खानपुर-देह	135-भाग	00	01	60	—
खानपुर-देह	258-भाग	00	01	92	—
खानपुर-देह	257-भाग	00	01	12	—
खानपुर-देह	312-भाग	00	07	60	—
खानपुर-देह	408-भाग	00	04	80	—
खानपुर-देह	765-भाग	00	04	40	—
खानपुर-देह	837-भाग	00	02	00	—
खानपुर-देह	838-भाग	00	01	76	—
खानपुर-देह	841-भाग	00	01	76	—
खानपुर-देह	958-भाग	00	01	00	—
खानपुर-देह	1037/ए-भाग	00	02	20	—

[एफ. सं. आर-31015/24/97-प्रो.आर.-II]
के.सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1098.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum products from Dahej to Baroda, via Gandhar, in the Gujarat State through Dahej-Gandhar-Baroda, pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interest in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public object, in writing to the acquisition of the right of user there in or laying of the pipeline under the land to Shri S.K. Patel, Competent Authority, Dahej-Gandhar-Baroda Pipeline Project, Indian Petrochemicals Corporation Limited (Gandhar Complex), Baroda-391 345.

SCHEDULE

Taluka (Tehsil) : Jambusar

District : Bharuch

State : Gujarat

Name of Village	Survey/Sub-Division or Block No.	Area			
		Hectare	Ares	Acre	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Magnad	27-Part	00	02	00	—
Magnad	1211-Part	00	06	20	—
Magnad	1240-Part	00	12	00	—
Magnad	1266-Part	00	00	75	—
Magnad	1267-Part	00	14	70	—
Magnad	1254-Part	00	12	00	—
Magnad	1358-Part	00	00	65	—
Magnad	1367-Part	00	04	00	—
Magnad	1336-Part	00	06	00	—
Magnad	1373-Part	00	03	00	—
Magnad	Cart-track	00	00	06	—
Magnad	1377-Part	00	00	60	—
Magnad	1378-Part	00	00	70	—
Magnad	1478-Part	00	08	20	—
Magnad	1479-Part	00	00	60	—
Magnad	1481-Part	00	05	60	—
Magnad	1487-Part	00	20	80	—
Ankhi	1052-Part	00	02	40	—
Uchhad	991-Part	00	02	70	—
Uchhad	1111-Part	00	00	10	—
Gajera	1501-Part	00	00	15	—
Gajera	1509-Part	00	00	15	—
Gajera	1617-Part	00	00	15	—
Gajera	1896-Part	00	00	25	—
Khanpur-deh	124-Part	00	01	12	—
Khanpur-deh	126-Part	00	00	64	—
Khanpur-deh	135-Part	00	01	60	—
Khanpur-deh	258-Part	00	01	92	—
Khanpur-deh	257-Part	00	01	12	—
Khanpur-deh	312-Part	00	07	60	—
Khanpur-deh	408-Part	00	04	80	—
Khanpur-deh	765-Part	00	04	40	—
Khanpur-deh	837-Part	00	02	00	—
Khanpur-deh	838-Part	00	01	76	—
Khanpur-deh	841-Part	00	01	76	—
Khanpur-deh	958-Part	00	01	00	—
Khanpur-deh	1037/A-Part	00	02	20	—

[F. No. R-31015/24/97-O.R.II]
K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का. आ. 1099.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज से गंधार होकर बड़ौदा तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि पाइप लाइन के बिछाए जाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिसूचना के उपबंध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया जाए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें के उपयोग का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिससे भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि में के उपयोग के अधिकार के अर्जन या भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने के प्रति लिखित रूप से आपत्ति, श्री एस के. पटेल, सक्षम अधिकारी, दहेज-घार--बड़ौदा पाइप लाइन परियोजना, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (गंधार कॉम्प्लेक्स), बड़ौदा--391345 को कर सकता है।

अनुसूची

तालुका (तहसील) : पादरा

जिला : बड़ौदा

राज्य : गुजरात

ग्राम का नाम	सर्वे नं. सब अधिजन ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	क्षेत्रफल आरे	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
चौकारी	298/भाग	00	08	20	---
चौकारी	336/भाग	00	00	75	---
चौकारी	332 भाग	00	01	50	---
चौकारी	337/बी--भाग	00	00	82	---
चौकारी	306 भाग	00	01	50	---
चौकारी	214 भाग	00	00	20	---
चौकारी	880 भाग	00	00	10	---
चौकारी	905 भाग	00	01	00	---
चौकारी	724 भाग	00	00	20	---
चौकारी	710 भाग	00	00	25	---
डबका	193 भाग	00	00	20	---
नरसिंहपुरा	175 भाग	00	01	50	---
नरसिंहपुरा	348 भाग	00	12	39	---
मुजपुर	395 भाग	00	00	50	---
मुजपुर	397 भाग	00	00	25	---
मुजपुर	653 भाग	00	00	60	---
मुजपुर	657 भाग	00	00	40	---
एकलबारा	235 भाग	00	00	05	---
एकलबारा	241 भाग	00	01	36	---
एकलबारा	558 भाग	00	00	92	---
लूना	513 भाग	00	00	40	---
जासपुर	519 भाग	00	00	50	---
जासपुर	539 भाग	00	00	97	---
जासपुर	537 भाग	00	00	70	---
उमराया	610 भाग	00	01	92	---
उमराया	611 भाग	00	19	08	---
उमराया	611 भाग	00	00	90	---
उमराया	612 भाग	00	12	80	---
उमराया	625 भाग	00	12	40	---
उमराया	622 भाग	00	03	05	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमराया	400 भाग	00	12	25	—
उमराया	400 भाग	00	13	20	—
उमराया	400 भाग	00	00	80	—
उमराया	624 भाग	00	05	10	—
उमराया	623 भाग	00	03	32	—
उमराया	662 भाग	00	07	30	—
उमराया	658 भाग	00	01	00	—
उमराया	660 भाग	50	03	00	—
उमराया	661 भाग	00	01	80	—
उमराया	759 भाग	00	03	04	—
करखड़ी	836 भाग	00	09	00	—
करखड़ी	432 भाग	00	00	62	—
बाजणवसी	95 भाग	00	00	40	—

[एफ. नं. आर-31015/24/97—आर. आर.-II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1099.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum products from Dahej to Baroda, via Gandhar, in the Gujarat State through Dahej-Gandhar-Baroda, pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user there in or laying of the pipeline under the land to Shri S.K. Patel, Competent Authority, Dahej-Gandhar-Baroda Pipeline Project, Indian Petrochemicals Corporation Limited (Gandhar Complex), Baroda-391 345.

SCHEDULE

Taluka (Tehsil) : Padra
State : Gujarat

District : Baroda

Name of Village	Survey/Sub-Division or Block No.	Area			
		Hectare	Ares	Aere	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chokari	298-Part	00	08	20	—
Chokari	336-Part	00	00	75	—
Chokari	332-Part	00	01	50	—
Chokari	337/B-Part	00	00	82	—
Chokari	306-Part	00	01	50	—
Chokari	214-Part	00	00	20	—
Cholari	880-Part	00	00	10	—
Chokari	905-Part	00	01	00	—
Chokari	724-Part	00	00	20	—
Chokari	710-Part	00	00	25	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dabka	193-Part	00	00	20	—
Narsinhapura	175-Part	00	01	50	—
Narsinhapura	348-Part	00	12	39	—
Mujpur	395-Part	00	00	50	—
Mujpur	397-Part	00	00	25	—
Mujpur	653-Part	00	00	60	—
Mujpur	657-Part	00	00	40	—
Ekalbara	235-Part	00	00	05	—
Ekalbara	241-Part	00	01	36	—
Ekalbara	558-Part	00	00	92	—
Luna	513-Part	00	00	40	—
Jaspur	519-Part	00	00	50	—
Jaspur	539-Part	00	00	97	—
Jaspur	537-Part	00	00	70	—
Umaraya	610-Part	00	01	92	—
Umaraya	611-Part	00	19	08	—
Umaraya	611-Part	00	00	90	—
Umaraya	612-Part	00	12	80	—
Umaraya	625-Part	00	12	40	—
Umaraya	622-Part	00	03	05	—
Umaraya	400-Part	00	12	25	—
Umaraya	400-Part	00	13	20	—
Umaraya	400-Part	00	00	80	—
Umaraya	624-Part	00	05	10	—
Umaraya	623-Part	00	03	32	—
Umaraya	662-Part	00	07	30	—
Umaraya	658-Part	00	01	00	—
Umaraya	660-Part	00	03	00	—
Umaraya	661-Part	00	01	80	—
Umaraya	759-Part	00	03	04	—
Karkhadi	836-Part	00	09	00	—
Karkhadi	432-Part	00	00	62	—
Brahmanvasi	95-Part	00	00	40	—

[F. No. R-31015/24/97-O. R. II]

K.C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का.आ. 1100.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज से गंधार होकर बड़ौदा तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यह प्रतीत होता है कि पाइप लाइन के बिछाये जाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि इस अधिसूचना के उपा-बद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया जाए,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसमें के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है,

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस तारीख से, जिससे भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि में के उपयोग के अधिकार के अर्जन या भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाएं जाने के प्रति लिखित रूप से आपत्ति, श्री एस०के० पटेल, सहाय अधिकारी, दहेज—गंधार—बड़ौदा पाइप लाइन परियोजना, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (गंधार कॉम्प्लेक्स), बड़ौदा 391 345 को कर सकता है।

अनुसूची

तालुका (तहसील) : बड़ोदरा
राज्य : गुजरात

जिला : बड़ोदरा

ग्राम का नाम	सर्वे नं./ सब डिविजन/ ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	क्षेत्रफल आर	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
अंपाड	163/भाग	00	01	00	--
शेरखी	501/5—भाग	00	01	00	--
शेरखी	369/3—भाग	00	00	80	--
शेरखी	494/1—भाग	00	20	00	--
शेरखी	496/1—भाग	00	21	60	--
शेरखी	549/4—भाग	00	18	80	--
शेरखी	549/3—भाग	00	07	80	--
शेरखी	368/1—भाग	00	01	00	--
कोयली	1017/4—भाग	00	04	00	--
कोयली	718/2—भाग	00	15	70	--
कोयली	942/1—भाग	00	10	60	--

[एफ नं. आर.-31015/24/97-प्रो.आर.-II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1100.— Where as it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum Products from Dahej to Baroda, Via Gandhar, in the Gujarat State through Debej-Gandhar-Baroda, pipeline should be laid by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of the section 3 of the petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri S.K. Patel, Competent Authority, Dahej-Gandhar-Baroda Pipeline Project, Indian Petrochemicals Corporation Limited (Gandhar Complex), Baroda-391 345.

SCHEDULE

Taluka (Teshil) : Baroda
State : Gujarat

District : Baroda

Name of Village	Survey/ Sub-Division or Block No.	AREA			
		Hectare	Ares	Acre	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ampad	163-Part	00	01	00	—
Sherkhi	501/5-Part	00	01	00	—
Sherkhi	369/3-Part	00	00	80	—
Sherkhi	494/1-Part	00	20	00	—
Sherkhi	496/1-Part	00	21	60	—
Sherkhi	549/4-Part	00	18	80	—
Sherkhi	549/3-Part	00	07	80	—
Sherkhi	368/1-Part	00	01	00	—
Koyali	1017/4-Part	00	04	00	—
Koyali	718/2-Part	00	15	70	—
Koyali	942/1-Part	00	10	60	—

[F.No. : R-31015/24/97-OR-II]
K.C. Katoch Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का०आ० 1101 :—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचनाओं संख्या का०आ० 2959 तारीख 31 अक्तूबर, 1995 द्वारा दहेज से गंधार होकर पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ौदा को करने के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विलंबनों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तालुका (तहसील) : वागरा

जिला: भरुच

राज्य: गुजरात

ग्राम का नाम	सर्वे नं०/सब डिवीजन/ ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	आर	क्षेत्रफल सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
दहेज	1198/भाग	00	14	50	—
दहेज	1030/भाग	00	02	50	—
दहेज	208/भाग	00	01	50	—

[फाइल सं०: आर०-31015/24/97-ओ०आर०-II]

के०सी० कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O.1101 Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 2959, dated the 31st October, 1995 issued under sub Section (1) of Section-3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of User in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda Via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, Copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section-6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section-6 of said Act, the Central Government hereby declares that the right of User in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section(4) of section-6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of User in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemical Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State:	Gujarat	District:	Bharuch	Tehsil/Taluka:	Vagra
Name of the Village	Survey/Sub Divn or Block No	Hectare	Are	Area Centare	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dahej	1198-Part	00	14	50	—
Dahej	1030-Part	00	02	50	—
Dahej	208-Part	00	01	50	—

[F No : R-31015/24/97-OR II]

K.C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का०ग्रा० 1102 :—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचनाओं संख्या का०ग्रा० 2960 तारीख 31 अक्तूबर, 1995 द्वारा दहेज से गंधार होकर पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ौदा को करने के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने साथ की घोषणा की थी,

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ;

यह और कि, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विभागों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

राज्य : गुजरात

जिला : भरुच

तालुका/तहसील : बागरा

ग्राम का नाम	सर्वे नं. / सब डिविजन/ ब्लॉक नं.	क्षेत्रफल		क्षेत्रफल	
		हेक्टेयर	आर	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
कडोदरा	846/भाग	00	14	30	—
कडोदरा	845/भाग	00	14	10	—
कडोदरा	844/भाग	00	24	00	—
कडोदरा	792/भाग	00	02	25	—
कडोदरा	794/भाग	00	02	25	—
कडोदरा	685/भाग	00	15	30	—
कडोदरा	569/भाग	00	34	65	—
कडोदरा	570/भाग	00	08	35	—

[एक सं. आर—31015/24/97-ओ. आर. —II]

के. सी. कटोक, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1102—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No S.O. 2960, dated the 31st October, 1995 issued under sub-section(1) of Section-3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of User in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda Via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of section-6 of the said Act submitted his report to the Central Govt.

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of Section-6 of said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of section-6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State : Gujarat

District : Bharuch

Tehsil/Taluka : Vagra

Name of the Village	Survey/Sub.Divn. or Block No.	Area			
		Hectare	Acre	Centare	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kadodara	846-Part	00	14	30	—
Kadodara	845-Part	00	14	10	—
Kadodara	844-Part	00	24	00	—
Kadodara	792-Part	00	02	25	—
Kadodara	794-Part	00	02	25	—
Kadodara	685-Part	00	15	30	—
Kadodara	569-Part	00	34	65	—
Kadodara	570-Part	00	08	35	—

[F. No. : 31015/24/97-OR. II]

K. C. KATOCH Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का.आ. 1103 —केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचनाओं संख्या का.आ. 2961 तारीख 31 अक्टूबर, 1995 द्वारा दहेज से गंधार होकर पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ोदा को करने के लिये इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी,

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाय ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये उपयोग का अधिकार अर्जन करने की घोषणा करती है ;

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सभी विलेखनों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तालुका : (तहसील) : वागरा

जिला : भरुच

राज्य : गुजरात

का नाम	सर्वे नं /सब डिवीजन/ ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	क्षेत्रफल आर.	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
पाणीयादरा	204 भाग	00	09	00	—

[फा. सं. : आर-31015/24/97-ओ.आर. II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O.1103.—Where as by a notification the of the Government of India in the Ministry of chemicals and fertilizers No. S. O. 2961, dated the 31st October, 1995 issued under Sub Section(1) of Section-3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition) of Right of User in Land) Act, 1992 (50 of 1962) (herein after referred to as the said Act, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda Via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section-6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-6 of said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section-6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State : Gujarat		District : Bharuch		Tehsil/Taluka : Vagra		
Name of the Village	Survey/Sub. Divn. or Block No.	Hectare	Area			
			Are	Centiare	Cents	
1	2	3	4	5	6	
Paniyadra	204-Part	00	09	00	—	

[F. No. : R-31015/24/97-OR.II]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का.आ. 1104—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचनाओं संख्या का.आ. 2962 तारीख 31 अक्टूबर, 1995 द्वारा दहेज से गंधार होकर पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ोदा को करने के लिये इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थीं।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है।

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाईन बिछाने के लिये उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ;

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सभी विलंबनों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तालुका (तहसील) : वागरा

जिला : भरुच

राज्य : गुजरात

ग्राम का नाम	सर्वे नं. / सब डिवीजन/ ब्लाक नं.	क्षेत्रफल			
		हेक्टेयर	आर	सेन्टर	सेन्टर
1	2	3	4	5	6
गोलादरा	359 भाग	00	05	18	—

[फा० संख्या : आर-31015/24/97-प्रो आर-II]

के.सी. कटोच, अवसर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S. O. 1104.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 2962, dated the 31st October, 1995 issued under sub-section (1) of Section-3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section-6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-6 of said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section-6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State : Gujarat		District : Bharuch		Tehsil/Taluka : Vagra	
Name of the Village	Survey/Sub. Divn. or Block No.	Area			
		Hectare	Arc	Centare	Cents
1	2	3	4	5	6
Goladara-	359-Part	00	05	18	—

[F.No. : R-31015/24/97-OR.II]

K.C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का. आ. 1105—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2963 तारीख 31 अक्टूबर, 1995 द्वारा दहेज से गंधार होकर पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ोदा को करने के लिये इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है।

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिये उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है।

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी बिलंबनों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तालुका (तहसील) : वागरा

जिला भरुच

राज्य : गुजरात

ग्राम का नाम	सर्वे नं. /सब डिवीजन/ ब्लाक नं.	हैक्टेयर	क्षेत्रफल		
			आर	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
अलादर	361 भाग	00	00	50	—

[फा० सं० : आर-31015/24/97-प्रो. आर.-II]
के.सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1105 .—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 2963, dated the 31st October, 1995 issued under sub-section (1) of section-3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification) or the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section-6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-6 of said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section-6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State : Gujarat		District : Bharuch		Tehsil/Taluka : Vagra	
Name of the Village	Survey/Sub. Divn. or Block No.	Area			
		Hectare	Acre	Centare	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aladar	361-Part	00	00	50	—

[F. No. : R-31015/24/97-O.R. II]
K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का.आ. 1106 —केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2964 तारीख 31 अक्टूबर, 1995 द्वारा दहेज से न्धारहोकर पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ोदा को करने के लिये इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने प्रायण की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह संवाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिये उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ;

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजाय सभी क्लैमों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तालुका (तहसील) : वागरा

जिला : भरुच

राज्य : गुजरात

क्षेत्रफल

ग्राम का नाम	सर्वे नं./सब डिवीजन/ ब्लॉक नं.	हैक्टेयर	आर	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
तांकल	129/पी-भाग	00	08	00	—

[फा सं. : आर-31015/24/97-ओ आर.-II].

के.सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S. O. 1106 .—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S. O. 2964, dated the 31st October, 1995 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-6 of said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State : Gujarat

District : Bharuch

Tehsil/Taluka : Vagra

Name of Village	Survey/Sub. Divn. or Block No.	Area			
		Hectare	Are	Centare	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Trankal	129/P-Part	00	08	00	—

[F. No. : R-31015/24/97-O.R. II]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का.आ 1107. —केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2965 तारीख 31 अक्तूबर, 1995 द्वारा दहेज से गंधार होकर पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ीदा को करने के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिये उपयोग का अधिकार अर्जन करने की घोषणा करती है ;

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय सभी विलंबनों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ;

अनुसूची

तालुका (तहसील) : वागरा

राज्य : गुजरात

जिला : भरुच

क्षेत्रफल

ग्राम का नाम	सर्वे नं. / सब डिवीजन/ ब्लॉक नं.	हैक्टेयर	आर	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
पालडी	24 भाग	00	00	20	—
पालडी	172 भाग	00	00	62	—

[फा. सं. : आर-31015/24/97-ओं.आर.-II]

के.सी. कटोच, अवसर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O.1107.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 2965, dated the 31st October, 1995 issued under sub-section (1) of Section-3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section-6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State : Gujarat

District : Bharuch

Tehsil/Taluka : Vagra

Name of the Village	Survey/Sub. Divn. or Block No.	Area			
		Hectare	Are	Centare	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paladi	24-Part	00	00	20	—
Paladi	172-Part	00	00	62	—

[F.No. R-31015/24/97-O.R.II]
K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का.प्रा.1108—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. प्रा. 2966 तारीख 31 अक्टूबर, 1995 द्वारा दहेज से गंधार होकर पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ौदा को करने के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है।

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिये उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है।

यह और कि, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की अधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजाएँ सभी निम्नलिखितों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तालुका (तहसील) : जंबुसर

जिला : भारुच

राज्य : गुजरात

क्षेत्रफल					
ग्राम का नाम	सर्वे नं. /सब डिवीजन/ ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेक्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
कुंडल	271/अ-ब भाग	00	01	26	—

[फा० सं० : आर-31015/24/97-प्रो.आर. II-]

के.सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

O. 1108.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and fertilizers No. S. O. 2966, dated the 31st October, 1995 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section-6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State : Gujarat

District: Bharuch

Tehsil/Taluka : Jambusar

Name of the Village	Survey/Sub. Divn. or Block No.	Area			
		Hectare	Acre	Centare	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kundhal	271/A & B-Part	00	01	26	—

[F. No. : R-31015/24/97-OR-II]
K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

क्र. आ. 1109 :—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जमीन की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2967 तारीख 31 अक्टूबर, 1995 द्वारा दहेज में गंधार होकर पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ोदा को करने के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र की अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 9 मार्च, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और राज्य प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ;

यह और कि, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विलंबनों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लिहित होगा।

अनुसूची

राज्य : गुजरात

जिला : भरुच

तालुका/तहसील : जंबुसर

ग्राम का नाम	सर्वे नं०/सब-डिविजन/ ब्लॉक नं०	क्षेत्रफल			
		हेक्टेयर	आर	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
मगनाद	1490 भाग	00	15	10	—
मगनाद	61 भाग	00	13	42	—
मगनाद	62 भाग	00	04	00	—

[एफ. सं. आर-31015/24/97-ओ. आर. -II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1109 :—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 2967, dated the 31st October, 1995 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda Via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquire for laying the pipelines;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

Schedule

State : Gujarat		District : Bharuch		Tehsil/Taluka : Janbasar	
Name of the Village	Survey/Sub. Divn. or Block No.	Area			
		Hectare	Are	Centare	Cents
1	2	3	4	5	6
Magnad	1490-Part	00	15	10	—
Magnad	61-Part	00	13	42	—
Magnad	62-Part	00	04	00	—

[F. No. R-31015/24/97-OR-II]
K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का. आ. 1110:—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक संस्थान की अधिसूचना भण्डा का. आ. 2968 तारीख 31 अक्तूबर, 1995 द्वारा दहेज से गंवारा होकर, पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ौदा को करने के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अनेकानेक की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र की अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जन करने की घोषणा करती है।

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की वजह से सभी विधेयनों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तालुका (तहसील) : पादरा

जिला : बड़ोदरा

राज्य : गुजरात

ग्राम का नाम	सर्वे नं. / सब डिवीजन/ ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	अर	क्षेत्रफल मैटर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
दूधवाडा	ग्रामनजीमी डबल्यू बी एम रोड	00	04	00	—

[फा० सं० : आर-31015/24/97-आ०. आर-II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1110.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 2968, dated the 31st October, 1995 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Scheduled appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the notification of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

Schedule

State - Gujarat

District : Baroda

Tehsil/Taluka : Padra

Name of the Village	Survey/Sub. Divn. or Block No.	Area			
		Hectare	Arc	Centare	Cents
1	2	3	4	5	6
Dudhwada	ONGC WBM Road	00	04	00	—

[F. No. R-31015/24/97-OR-II]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का. अ. 1111.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलेियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक संवहन की अधिसूचनाओं संख्या का. अ. 2969 तारीख 31 अक्टूबर, 1995 द्वारा दहेज मेसंधार हाकर पेट्रोलेियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बढ़ावा को करने के लिए इंडियन, पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अधिनियम की प्रवण धारा की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह सन्निधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अधिनियम अधिनियम करने की घोषणा करती है ;

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी वजाय सभी बिलबनों में मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होंगी।

अनुसूची

राज्य : गुजरात

जिला : वडोदरा

तहसील/तहसील : वडोदरा

ग्राम का नाम	सर्वे नं. / सब डिविजन/ ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	क्षेत्रफल		
			आर	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
चीकारी	707/भाग	00	00	10	—
चौकारी	233/भाग	00	13	54	—
	बी + सी				

[एफ० सं० आर-31015/24/97-प्र. प्रार.-II]

के. सी. कटोव, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1111.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 2969, dated 31st October, 1995 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of Petroleum products from Dahaj to Baroda via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited ;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines ;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEEULE

State : Gujarat

District : Baroda

Tehsil/Taluka : Padra

Name of the Village	Survey/Sub. Divn. or Block No.	Area			
		Hectare	Are	Centare	Cents
1	2	3	4	5	6
Chokari	707-Part	00	00	10	—
Chokari	233/B+C-Part	00	13	54	—

[F. No. R-31015/24/97-OR-II]

K. C. KATOCH, Under Secy

नई दिल्ली, 19 मई, 1998.

का. शा. 1112:—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलिएम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचनाओं संख्या का. शा. 2970 तारीख 31 अक्तूबर, 1995 द्वारा दहेज सेगंधार होकर पेट्रोलिएम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ौदा को करने के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ;

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी विलंबनों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तालुका (तहसील) पादरा

राज्य : गुजरात

जिला : बड़ोदरा

क्षेत्रफल

ग्राम का नाम	सर्वे नं०/सब डिविजन/ ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	आर	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
एकलबारा	ओएनसीजी गैस लाइन	00	04	00	—

[फाइल संख्या: आर०-31015/24/97-ओ०आर-II]

के०सी० कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1112:—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 2970 dated the 31st October, 1995 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State : Gujarat

District : Baroda

Tehsil/Taluka : Padra

Name of the Village	Survey/Sub. Divn. or Block No.	Area			
		Hectare	Are	Centare	Cents
1	2	3	4	5	6
Ekalbara	ONGC Gas Line	00	04	00	—

[F. No. R-31015/24/97-OR-II]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का.भा. 1113 :—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब से इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचनाओं संख्या का.भा. 2971 तारीख 31 अक्टूबर 1995 द्वारा वहेज से गंधार होकर से पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ोदा को करने के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं में संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट की है,

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी बिलंबनों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

राज्य : गुजरात

जिला : बड़ोदा

तालुका/तहसील : बड़ोदा

ग्राम का नाम	सर्वे नं०/ सब डिविजन/ ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	क्षेत्रफल		
			घा.र.	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
शेरखी	127 भाग	00	00	60	—
शेरखी	161/1 भाग	00	19	20	—
शेरखी	562/भाग	00	01	25	—

[एफ. सं. आर.—31015/24/97—ओ. आर.—II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1113.—Whereas by a notification of the Government of India in the 'Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 2971, dated the 31st October, 1995 issued under sub-section (1) of Section-3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section-6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-6 of said Act, the Central Government hereby declares the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section-6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State : Gujarat		District : Baroda		Tehsil/Taluka : Baroda	
Name of the Village	Survey/Sub. Divn. or Block No.	Area			
		Hectare	Are	Centare	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sherkhi	127-Part	00	00	60	..
Sherkhi	161/1-Part	00	19	20	..
Sherkhi	562-Part	00	01	25	..

[F.No. R-31015/24/97-OR-II]

K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का. भा. 1114 :—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (अब इसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचनाओं संख्या का. भा. 2972 तारीख 31 अक्तूबर, 1995 द्वारा दहेज से गंधार होकर पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन गुजरात राज्य में बड़ोदा को करने के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 9 मार्च, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है;

यह और कि, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विलंबनों से मुक्त होकर इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

तालुका (तहसील) : बड़ोदरा		राज्य : गुजरात		जिला : बड़ोदरा	
ग्राम का नाम	सर्वे नं./ सब डिविजन/ ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टर	सेन्ट
1	2	3	4	5	6
कोयली	968 भाग	00	01	00	—

[फा० सं० : भार-31015/24/97-ओ. भार-II]

के. सी. कटोच, असर सचिव

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1114.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 2972, dated the 31st October, 1995 issued under sub-section (1) of Section-3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for transport of petroleum products from Dahej to Baroda via Gandhar in the State of Gujarat by the Indian Petrochemicals Corporation Limited;

And whereas, copies of the said Gazette Notification were made available to the public on 9th March, 1996;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section-6 of the said Act submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section-6 of said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipelines;

And, further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section-6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Indian Petrochemicals Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State : Gujarat		District : Baroda		Tehsil/Taluka : Baroda	
Name of the Village	Survey/Sub. Divn. or Block No.	Area			
		Hectare	Are	Centare	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Koyali	968-Part	00	01	00	..

[F. No. : R-31015/24/97-OR.II]

K. C. KATOCH, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
नई दिल्ली, 22 मई, 1998

का. भा. 1115:—केन्द्रीय सरकार ने राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कार्यालय, आई बी पी-बामर लारी की समूह कंपनियाँ (लखनऊ समन्वय कार्यालय) 1/45 वजीर हुसन रोड, लखनऊ को, जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अधिसूचना सं. 11011/1/93—हिन्दी दिनांक 10 मई, 1993 के जरिए अधिसूचित किया था।

2. अब उपर्युक्त कार्यालय चूँकि बंद कर दिया गया है इसलिए केन्द्रीय सरकार इस कार्यालय को अनधिसूचित करती है।

[संख्या 11011/1/97—98—हिन्दी]

कृष्ण कान्त झा, उप निदेशक (रा. भा.)

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd May, 1998

S.O.1115.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the official Language (use for official purposes of the union) Rules, 1976, the Central Government had notified "I.B.P. Co. Ltd. Business Group of companies (Lucknow, Co-ordination office), 1/45 Wazir Hassan Road, Lucknow, an office of the Public Sector undertaking under the control of the Ministry of Petroleum and Natural Gas the Staff where-of had acquired 80 percent working Knowledge of Hindi vide notification No. 11011/1/93-Hindi Dated 10 May, 1993.

2. Now, as the aforesaid office has since been closed, the Central Government, therefore, denotifies this office.

[No. 11011/1/97-98-Hindi]

K. K. JHA, Dy. Director (OL)

नई दिल्ली, 22 मई, 1998

का.आ. 1116:—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

आई.बी.पी. कं. लि.

1. आई बी पी कं. लि.

(व्यापार समूह-रसायन) 265-अ,
बजाज नगर, दक्षिण अंबाहरी मार्ग,
नागपुर-440022

2. आई बी पी कं. लि.

एस एम एस सहायक संयंत्र
पोस्ट लालमटिया, जिला गोड्डा (बिहार),
राजमहल

3. आई बी पी कं. लि.

एम एम एस सहायक संयंत्र
गांव कुसरालोई, डाक अधा पाड़ा
जिला झारसुगुड़ा (उड़ीसा), ईब-वैली

कोचीन रिफाइनरी लि.

4. कोचीन रिफाइनरीज लि.

दिल्ली समन्वय कार्यालय, नई दिल्ली ।

5. कोचीन रिफाइनरीज लि.

विपणन एवं समन्वय कार्यालय, मुम्बई ।
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.

6. अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय

मेमनगर, फायर स्टेशन के सामने
विजय चार रास्ता के पास, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद-380009

7. खडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय

6-ए, तेल भवन, मध्य मार्ग,
सेक्टर 19-बी, खडीगढ़-160019

8. एल पी जी भराई संयंत्र

सिडको इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, बाही ब्राह्मणा
जम्मू (जम्मू कश्मीर)

9. पी ओ एल डिपो

नजदीक रेलवे स्टेशन,
जम्मू (जम्मू काश्मीर)

10. एल पी जी भराई संयंत्र

गांव डाहा, पो.आ. मंडियाला
आलंधर रोड, होशियारपुर (पंजाब)

11. अम्बाला डिपो

12, क्रास रोड, रेलवे स्टेशन के समीप,
अम्बाला कैंट (हरियाणा)

12. पेट्रोल डिपो
रेलवे स्टेशन के समीप, हिसार (हरियाणा)
 13. ओधी डिपो
गवर्नमेंट हाई स्कूल के समीप
हेड पोस्ट आफिस ओधी,
जिला शिमला (हि. प्र.)
 14. पेट्रोल डिपो,
रेलवे स्टेशन के पास,
पटियाला-147001
 15. जालंधर ल्यूब डिपो एवं टाप,
द्वारा इंडियन आयल कार्पो. लि,
मार्केटिंग डिवीजन, पाइप लाइन टर्मिनल,
सूचि पिंड, जालंधर-144009 (पंजाब)
 16. पेट्रोल डिपो,
रेलवे स्टेशन के पास,
कोटकपूरा (पंजाब)
 17. संगरूर डिपो
द्वारा इंडियन आयल कार्पो. लि..
(मार्केटिंग डिवीजन) के बी पी एल टॉप,
जींद रोड, संगरूर (पंजाब)
 18. भटिन्डा टॉप
द्वारा डिपो इंचार्ज
मकान नं. 19218, स्ट्रीट नं. 10, गुरु तेग बहादुर नगर,
बी बी वाला रोड: भटिन्डा-151001 (पंजाब)
 19. पानीपत डिपो
द्वारा डिपो प्रबन्धक
202-एल. माडल टाउन, रामलाल चौक के समीप,
पानीपत (हरियाणा)
 20. आगरा क्षेत्रीय कार्यालय
85/4 इस्पात भवन, तृतीय मंजिल
संजय प्लेस, आगरा-282002 (उ. प्र.)
- इंजीनियर्स इंडिया लि.
21. इंजीनियर्स इंडिया लि.
पानीपत रिफाइनरी, ग्राम बहोली, पोस्ट बाक्स 159,
पानीपत-132103
 22. इंजीनियर्स इंडिया लि.
मथुरा रिफाइनरी,
मथुरा-281004
 23. इंजीनियर्स इंडिया लि.
क्षेत्रीय कार्यालय, सूर्या हॉटल पैलेस,
10वां तल, सायाजीगंज, बड़ौदा-390005
 24. इंजीनियर्स इंडिया लि.
एल पी जी रिकवरी परियोजना,
जिला सिवसागर, लाकवा-785688 (असम)

New Delhi, the 22nd May, 1998

S.O. 1116.—In pursuance of Sub Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Public Sector Undertakings under the control of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, the 80 per cent staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :—

I. B. P. Company Limited

1. I. B. P. Co. Ltd.,
(Business Group Chemicals)
265-A, Bazaj Nagar, South Ambajhari Marg,
Nagpur-440022
2. I. B. P. Co. Ltd.,
S. M. S. Support Plant, Post—Lalmatia
Distt—Godda (Bihar), Rajmahal.
3. I. B. P. Co. Ltd.,
S. M. S. Support Plant
Village—Kusraloi, PO. Adhapara
Distt. Jharsuguda (Orissa), Ebe-Valley

Cochin Refineries Limited

4. Cochin Refineries Ltd.,
Delhi Co-ordination office,
New Delhi
5. Cochin Refineries Ltd.,
Marketing & Co-ordination Office,
Mumbai
Hindustan Petroleum Corporation Limited

6. Ahmedabad Regional Office,
Memnagar, Opposite Fire Station,
Near Vijai char Rasta, Navrangpura,
Ahmedabad-380009
7. Chandigarh Regional Office
6-A, Tel Bhavan, Madhya Marg
Sector-19-B, Chandigarh-160019
8. LPG Bottling Plant,
Sidco Industrial Complex,
Badibrahmana, Jammu (Jammu-Kashmir)
9. POL Depot,
Near Railway Station,
Jammu (Jammu-Kashmir)
10. LPG Bottling Plant,
Vill. Daha, PO. Mandiyala,
Jalandhar Road, Hoshiarpur (Punjab)

11. Ambala Depot,
12, Cross Road, Near Railway Station,
Ambala Cantt. (Haryana)
12. Petrol Depot,
Near Railway Station,
Hissar (Haryana)
13. Shoghi Depot,
Near Government High School,
Head Post Office Shoghi,
Distt. Simla (HP)
14. Petrol Depot,
Near Railway Station
Patiala-147001
15. Jallundhar Lube Depot & TOP,
C/o IOC Ltd. Marketing Division
Pipeline Terminal, Suchi Pind,
Jallundhar (Punjab)
16. Petrol Depot,
Near Railway Station,
Kotkapura (Punjab)
17. Sangrur Depot,
C/o IOC Ltd., (Marketing Division),
KBPL Top, Jind Road, Sangrur (Punjab)
18. Bhatinda Top,
C/o Depot Incharge, H. No. 19218,
Street No. 10, Guru Teg Bahadur Nagar,
Bibi Wala Road,
Bhatinda-151001 (Punjab)
19. Panipat Depot,
C/o Depot Manager, 202-L, Model Town,
Near Ramlal Chowk, Panipat (Haryana)
20. Agra Regional Office,
85/4, Ispat Bhawan, 3rd Floor,
Sanjay Place, Agra-282002 (UP)

Engineers India Limited

21. Engineers India Ltd.,
Panipat Refinery, Vill. Baholi, Post Box-159
Panipat-132103
22. Engineers India Ltd.,
Mathura Refinery, Mathura-281004
23. Engineers India Ltd.,
Regional office, Surya Hotel Palace,
10th Floor, Sayajiganj, Baroda-390005
24. Engineers India Ltd.,
LPG Recovery Project,
Distt. Sivsagar, Lakwa-785688 (ASSAM)

[No. 11011/1/97-98-Hindi]
K. K. JHA, Dy. Director (OL)

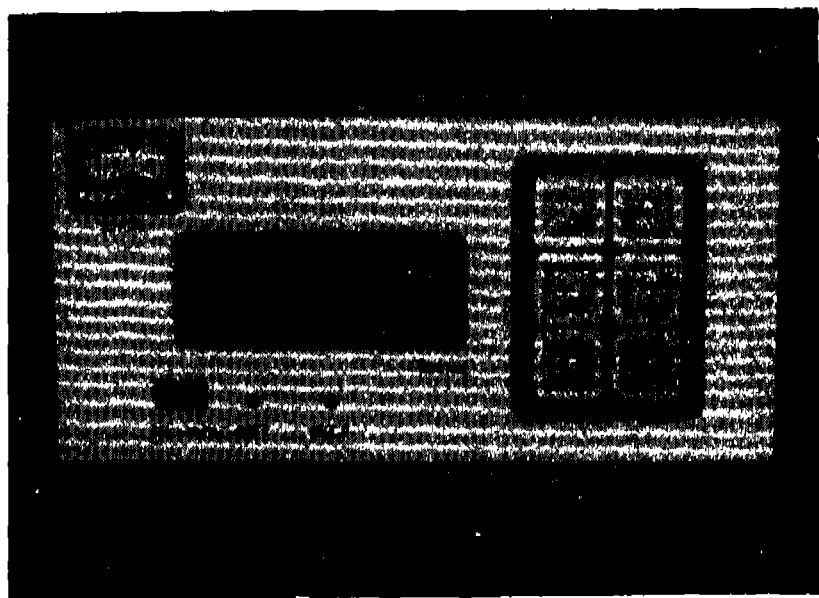
खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1998

का. आ. 1117 .—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए) पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप, मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबन्धों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह अखिरत उपयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “एस डब्ल्यू एस—600” शृंखला टाइप के स्वसूची स्वचालित इलैक्ट्रॉनिक हापर तोल प्रणाली के माडल का जिसका ब्रांड नाम “आई पी ए” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स आई पी ए प्रा. लि. बंगलोर—560058 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन.डी./09/97/50 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ।



यह माडल (आकृति देखिए) स्वचालित तोल यंत्र है जो “लोड सेल” के सिद्धान्त पर कार्य करता है जिसकी अधिकतम क्षमता 500 कि.ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल 100 ग्राम है । इसमें एक अधियतुलन युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यकलनात्मक धारित प्रभाव है । विशेष औद्योगिक अपेक्षाओं के लिए उपयुक्त आकृति के हापर आकार उदभारग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं हैं । स्थटिक संप्रदर्शन तुलन परिणाम उपदर्शित करता है। यंत्र 230 बोल्ट और 50 हर्टज पर प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है ।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त माडल के अनुमोदित प्रमाण पत्र के अन्तर्गत इसी विनिर्माता द्वारा इसी सिद्धान्त, डिजाइन और सामग्री जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, के अनुसार विनिर्मित इसी शृंखला के समरूप मेक, शुद्धता और निष्पादन वाले 1:5000 वियोजन वाले 100 कि. ग्रा. से 1000 कि. ग्रा. अधिकतम क्षमता वाले तुलन यूप भी हैं ।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम. 21 (86)/95]

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

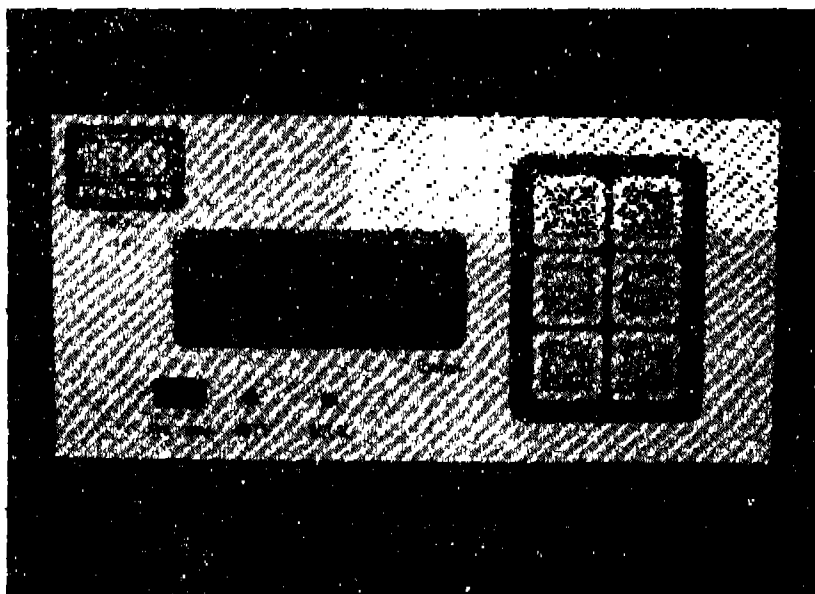
MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS**(Department of Consumer Affairs)**

New Delhi, the 25th May, 1998

S.O. 1117 .—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions .

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the self-indicating automatic electronic Hopper Weighing System of type "HWS-600" series and with brand name "IPA" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s IPA Private Limited, 472/B2, 12th Cross, IV Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-560058, and which is assigned the approval mark IND/09/97/50 ;

The model (see figure) is a automatic weighing instrument working on the principle of "Load Cell". with a maximum capacity of 500 kg. The verification scale interval (e) is 100 g. The load receptor is of Hopper shape of different sizes to suit the particular industrial requirements. The LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 Hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 100 kg to 1000 tonnes with a resolution of 1 : 5000, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.

[F. No. WM 21(86)/95]

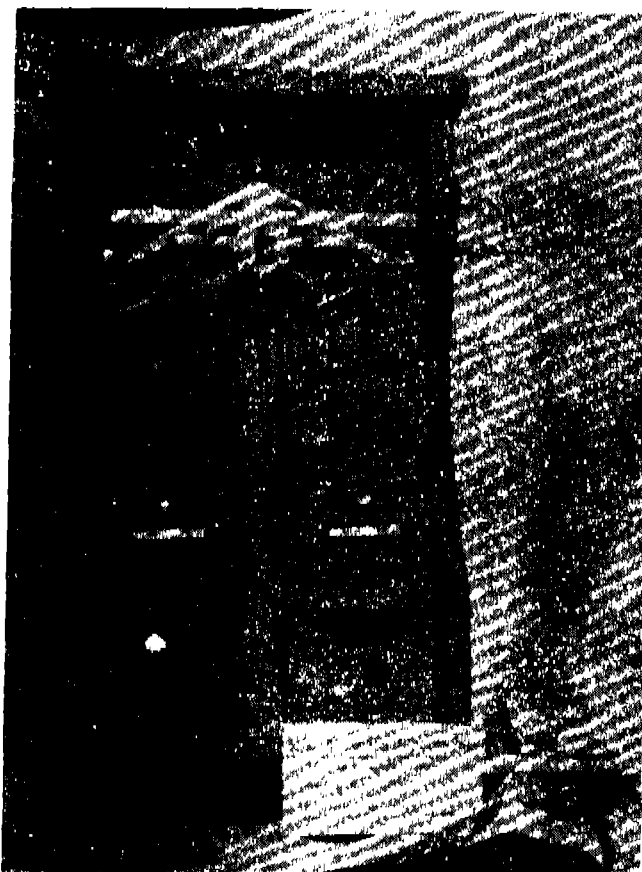
RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 25 मई 1998

का. आ. 1118.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखिए) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "यथार्थता" सोरिज टाईप के और "यथार्थता" ब्रांड नाम वाले सम बाहु यांत्रिक कार्यकारी मानक तुलाओं के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स एक्स्युरेसी इक्वपमेंट्स, 8, मधुसूदन पाल चौधरी लेन, हाथड़ा-1 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन.डी./09/97/100 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ।

उक्त माडल एक यांत्रिक सम बाहु कार्यकारी मानक तुला है जिसकी अधिकतम क्षमता 200 ग्राम है । दंड की प्रभावी लम्बाई 180 मि. मीटर है और तुला का सुग्राहिता अंक 1 मि. ग्राम है/भाग है । मापित मूल्य दंड से संलग्न और सूचक प्लेट पर गतिमान एक सूर द्वारा उपदर्शित किया जाता है ।



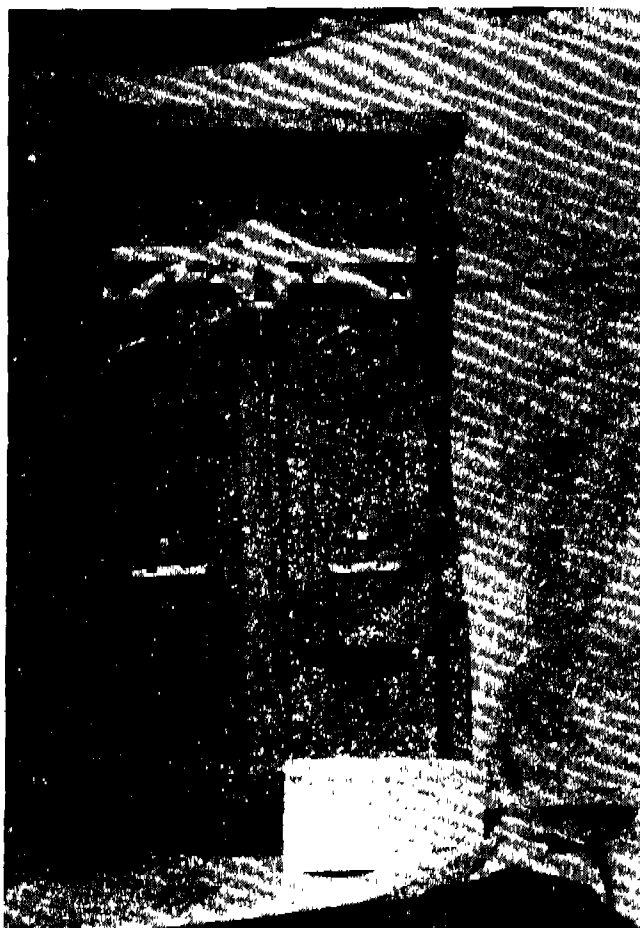
आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित 130 मिली मीटर की दंड लम्बाई और 0.02 मि. ग्राम/भाग की सुग्राहित अंक वाले 2 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समरूप मेक, यथार्थता और उसी मिरीज के कार्यकरण वाले कार्यकारी मानक तुला भी हैं ।

New Delhi, the 25th May, 1998

S.O.1118 .—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of the equi-arm mechanical Working Standard balances of type "Accuracy" series, and with the brand name "Accuracy" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s Accuracy Equipments, 8, Madhu Sudan Pal Chowdhry Lane, Howrah-1, and which is assigned the approval mark IND/09/97/100 ;

The said Model is a mechanical equi-arm working standard balance with maximum capacity of 200 g. The effective length of the beam is 180 millimetre and the sensitivity figure of the balance is 1 mg/division. The measured value is indicated by a pointer attached to the beam and moving over index plate.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the working standard balance of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 2 g, beam length of 130 millimetre and with a sensitivity figure of 0.02 mg/division, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved model has been manufactured.

[F. No. WM 21(92)/94]

RAJIV SRIVASTAVA. Addl. Secy.

नई दिल्ली, 25 मई, 1998

का. आ. 1119 .—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखिए) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा ;

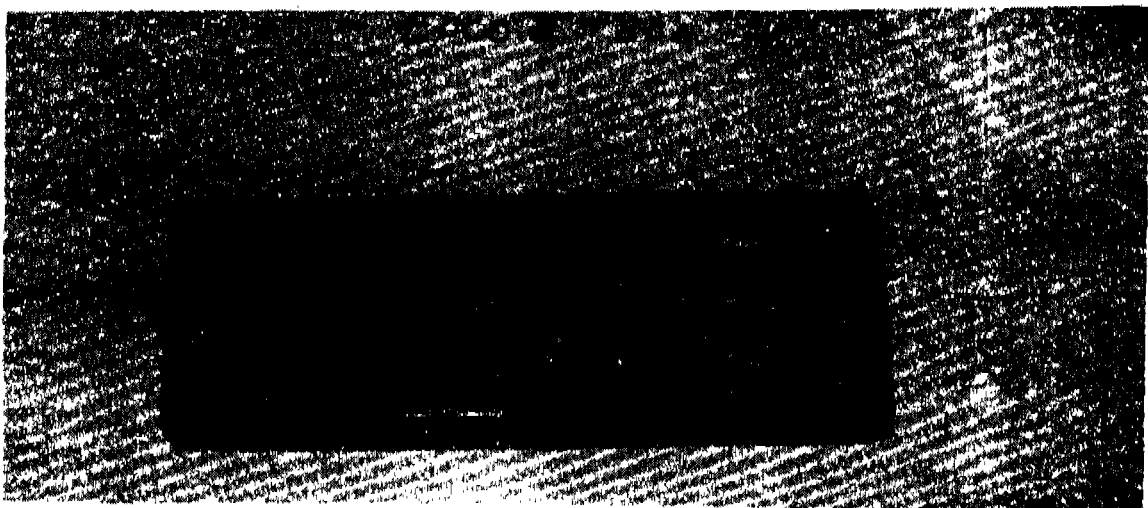
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "ई डी सी ओ ई टी 806" मिर्रीज टाइप के और "ई डी सी ओ" ब्रांड नाम वाले अंकीय संप्रदर्श वाले इलेक्ट्रानिक टैक्सी मीटर के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स आर. सी. एडवर्ड्स एण्ड कम्पनी प्रा. लि. 16, आर्थर बन्दर रोड, कोलाबा, मुम्बई-400005 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी./10/97/78 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रकाशित करती है।

माडल (आकृति नीचे दी गई है) एक इलेक्ट्रानिक टैक्सी मीटर है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं :—

उपकरण का नाम	अंकीय संप्रदर्श वाला इलेक्ट्रानिक टैक्सी मीटर
टाइप :	ई डी सी ओ ई टी 806 मिर्रीज
संप्रदर्श व्यौरा :	यह निम्नलिखित उपदर्शित करता है :—
	(1) कुल ट्रिप
	(2) कुल यूनिट
	(3) भाड़े का किलोमीटर
	(4) कुल किलोमीटर
	(5) कुल अतिरिक्त प्रभार

मीटर का व्यौरा :

यह युक्ति दूरी और समय संबंधी माप के सिद्धान्त पर आधारित है। मीटर में टैरिफ आदि के कार्यक्रम की और तत्पश्चात् उसमें गड़बड़ी रोकने के लिए सीलबंद करने की व्यवस्था है। यह मीटर 10 वोल्ट से 30 वोल्ट तक की विद्युत शक्ति।



New Delhi, the 25th May, 1998

SO. 1119 .—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions :

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the electronic taxi meter with digital display type “EDCO ET 806” series and with brand name “EDCO” (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s R.C. Edwards and Co. Pvt. Ltd., 16, Arthur Bunder Road, Colaba, Mumbai-400 005, and which is assigned the approval mark IND/10/97/78 ;

The Model (figure given below) is a Electronic taxi meter with the following characteristics :

Name of the instrument	Electronic taxi meter with digital display.
Type :	EDCO ET 806 series
Display details :	Indicates the following : (1) total trips, (2) total Units (3) kilometre hired (4) total kilometre (5) total extra charges

Details of the meter :

The device is based on the principle of distance and time measurement. The meter has provision for programming the tariffs etc. and then sealed, to prevent tampering. The meter works on power 10 volt to 30 volt



[F. No. WM 21 (94)/96]

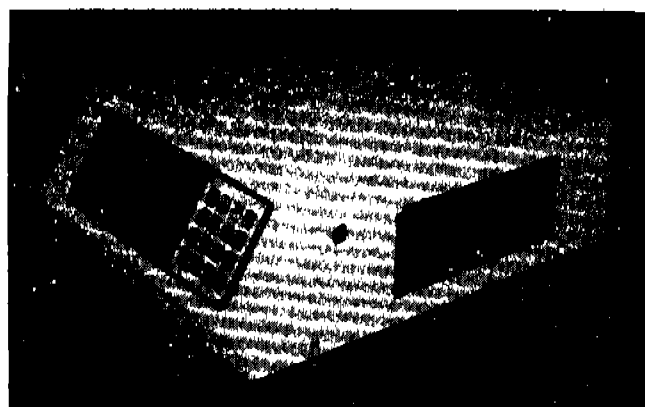
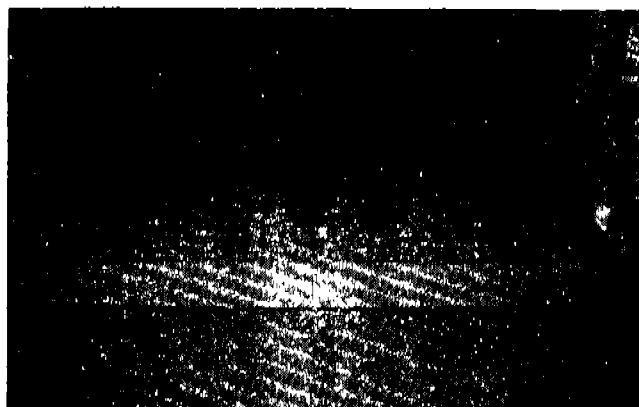
RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1998

का. आ. 1120 .—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखिए) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपरोक्त सेवा देता रहेगा ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (मध्यम) यथार्थता वर्ग 3 की "ली" सिरिज के "लिब्राबोम्बे" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर-स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक तुला-चोकी के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स लिब्रा इंडस्ट्रीज, 5वां तल, जीवन सहकार, सर पी. एम्. रोड, बम्बई-400001 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी./09/97/26 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;

माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग 3) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 40000 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 कि. ग्रा. है। स्थापन मापमान अन्तर (ई) 10 कि. ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। आधार और प्लेटफार्म मृदु इस्पात के हैं। भारग्राही आयताकार सैक्शन का है जिसका आकार 10×3 मीटर है। प्रकाश उत्सर्जन संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होगा;



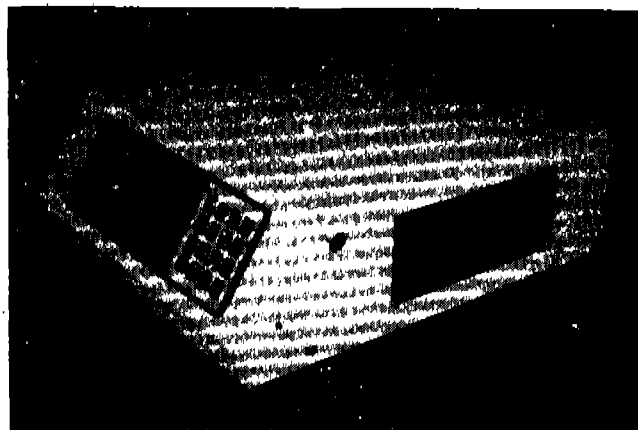
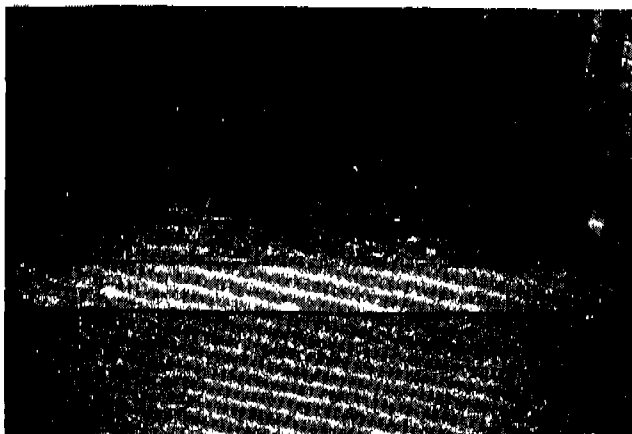
आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण दिया गया है विनिर्मित 5ट/2 कि. ग्रा., 10ट/5 कि. ग्रा., 20ट/5 कि. ग्रा., 25ट/5 कि. ग्रा., 30ट/5 कि. ग्रा., 50ट/10 कि. ग्रा., 60ट/10 कि. ग्रा. 80ट/20 कि. ग्रा. और 100ट/20 कि. ग्रा. की अधिकतम क्षमता वाले समरूप मेक, यथार्थता और उसी सिरिज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी हैं।

New Delhi, the 26th May, 1998

SO.1120 .—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating non-automatic electronic weighbridge of “LI” series of class III (Medium) accuracy with brand name “LIBRA Bombay” (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Libra Industries, 5th Floor, Jeevan Sahakar, Sir P. M. Road, Bombay-400 001, and which is assigned the approval mark IND/09/97/26 ;

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 40000 kg and minimum capacity of 200 kg. The verification scale interval (e) is 10 kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of size 10×3 metre. The LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 Hertz alternate current power supply ;



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 5t/2kg, 10t/5kg, 20t/5kg, 25t/5kg, 30t/5kg, 50t/10kg, 60t/10kg, 80t/20kg and 100t/20kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21 (54)/95]

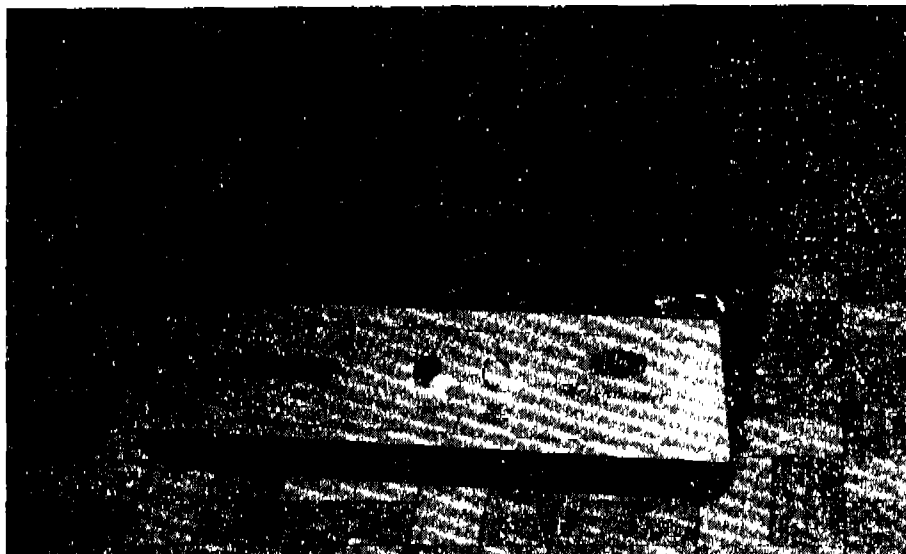
RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1998

का.आ. 1121.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखिए) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (मध्यम) यथार्थता वर्ग III की "रोमन पी.एस." सिरीज के रोमन ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर-स्वचालित इलेक्ट्रानिक टेबल टाप तोलन मशीन के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स रोमन इलेक्ट्रानिक्स, सोमनवे, जे.बी. नगर, अंधेरी (पू.) मुम्बई—400059 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी./09/97/25 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

माडल (आकृति में दिया गया) एम मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 10 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 40 ग्राम है। सत्यापन मापमान अन्तर (ई) 2 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यवहारात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है। भारग्राही आयताकार सैक्शन का है जिसका आकार 285×330 मि.मी. है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है।



आगे, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 500 ग्रा./0.1 ग्रा., 1 कि.ग्रा./0.5 ग्रा., 2 कि.ग्रा./0.5 ग्रा., 5 कि.ग्रा./2 ग्रा., 20 कि.ग्रा./5 ग्रा., 25 कि.ग्रा./5 ग्रा., 30 कि.ग्रा./10 ग्रा., 35 कि.ग्रा./10 ग्रा., 40 कि.ग्रा./10 ग्रा., 45 कि.ग्रा./10 ग्रा. और 50 कि.ग्रा./10 ग्रा. की अधिकतम क्षमता वाले समरूप मैक, यथार्थता और उसकी सिरीज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी हैं।

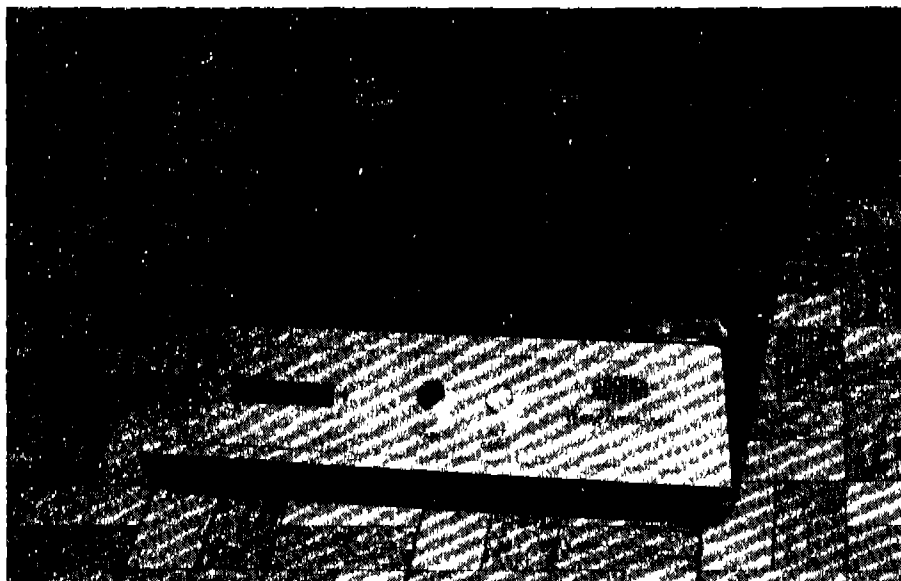
[फा. सं. डब्ल्यू एम 21 (83)/96]

New Delhi, the 26th May, 1998

S.O. 1121 .—Whereas, the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating non-automatic electronic table top weighing machine of "ROMAN P.S." series of class III (Medium) accuracy with brand name "ROMAN" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s Roman Electronics, Romanway, J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai-400059, and which is assigned the approval mark IND/09/97/25;

The Model (given in the figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 10kg and minimum capacity of 40g. The verification scale interval (E) is 2 g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of size 285 x 330 millimetre. The LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 Hertz alternate current power supply;



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of that section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 500g/0.1g, 1kg/0.5g, 2kg/0.5g, 5kg/2g, 20kg/5g, 25kg/5g, 30kg/10g, 35kg/10g, 40kg/10g, 45kg/10g and 50kg/10g, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F. No. WM 21(83)/96]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1998

का.आ.1122 :—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त माडल अविरत उपयोग की अवधि में भी यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यांत्रिक तुलना चौकी की वर्ग 3 यथार्थता (मध्यम यथार्थता) के "एल.सी.एस." शृंखला टाइप के अंक संप्रदर्शन वाले यंत्रों में संपरिवर्तित करने के लिए स्वतः सूचक गैर-स्वचालित संपरिवर्तित किट के माडल का जिसका ब्रांड नाम "तुला—100" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स एल. सी. एस. कंट्रोल प्रा. लि. 62 ए. आर. के. शम्भुगम रोड, के. के. नगर, चेन्नई-600073 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी. /09/97/53 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



यह माडल (आकृति देखें) मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग 3) का तुलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 300 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 2 कि. ग्राम है। स्थापन मापमान अन्तराल 100 ग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका सततप्रतिशत व्यक्तनात्मक धारित प्रभाव है : उद्भार याही आयताकार है जिसकी भुजाएं 600×400 मि.मी. हैं। द्रव्य स्फुटिक संप्रदर्शन तुलन परिणाम उपदर्शित करता है। यंत्र 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त माडल के अनुमोदन प्रमाणपत्र के अंतर्गत इसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित इसी शृंखला के समरूप मेक, यथार्थता और निष्पादन वाले 100 कि. ग्रा./20 ग्रा, 500 कि.ग्रा./100 ग्रा, 1 टन/200 ग्रा. और 2 टन/500 ग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तुलन उपकरण भी हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम. 21/91/96]

राजीव श्रीवास्तव, अपर सचिव

New Delhi, 26th May, 1998

S.O.1122 .—Whereas, the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic conversion kit for converting mechanical platform weighing machine into machine with digital display of type "LCS" series of class III accuracy (Medium accuracy) and with brand name "WEIGH-100" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s LCS Controls Private Limited, 62A, R. K. Shanmugam Road, K. K. Nagar, Chennai-600078, and which is assigned the approval mark IND/09/97/53;

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 300 kg and minimum capacity of 2 kg. The verification scale interval (e) is 100g. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of sides 600 × 400 millimetre. The LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 Hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 100kg/20g, 500kg/100g, 1 tonne/200g and 2 tonne/ 500g, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

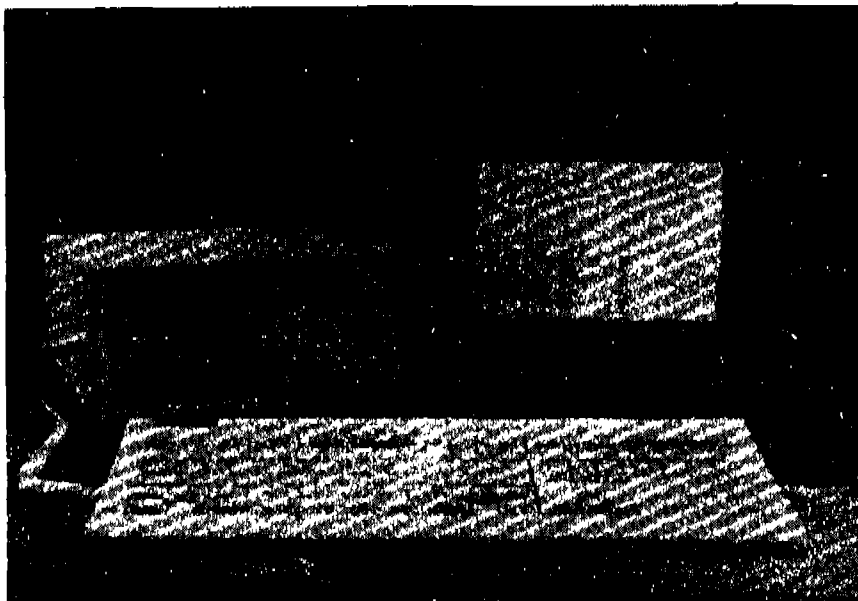
[F. No. WM-21 (91)/96]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1998

का. आ.1123.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक माडलों का अनुमोदन (नियम, 1987) के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त माडल अविरत उपयोग की अवधि में भी यथार्थता बनाए रखेगा और परिवर्तित दशाओं में उपयुक्त सेवा देता रहेगा :

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यांत्रिक तुला चौकी की वर्ग 3 यथार्थता (मध्यम यथार्थता) के "एल. सी. एस." शृंखला टाइप के अंक संप्रदर्शन वाले यंत्रों में संपरिवर्तित करने के लिए स्वतः सूचक गैर-स्वचालित संपरिवर्तित किट के माडल का जिसका ब्रांड नाम "तुला—100" है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) और जिसका विनिर्माण मैसर्स एल. सी. एस. कंट्रोल प्रा. लि., 62 ए. आर. के. शम्भुगम रोड, के. के. नगर चेन्नई—600078 द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई० एन० डी०/09/97/54 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रकाशित करती है।



यह माडल (आकृति देखें) (मध्यम यथार्थता) यथार्थता वर्ग 3 का तुलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 30000 कि. ग्रा. और न्यूनतम क्षमता 100 कि. ग्रा. है। सत्यापन मापमान अन्तराल 5 कि. ग्रा. है। इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका शतप्रतिशत व्यक्तेनात्मक धारित प्रभाव है। उद्धार ग्राही आयताकार है जिसकी भुजाएं 12 × 3 मीटर है। द्रव्य स्फटिक रू० श्री० संप्रदर्शन तुलन परिणाम उपदर्शित करता है। यंत्र 230 वोल्ट और 50 हर्टज आवृत्ति पर प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

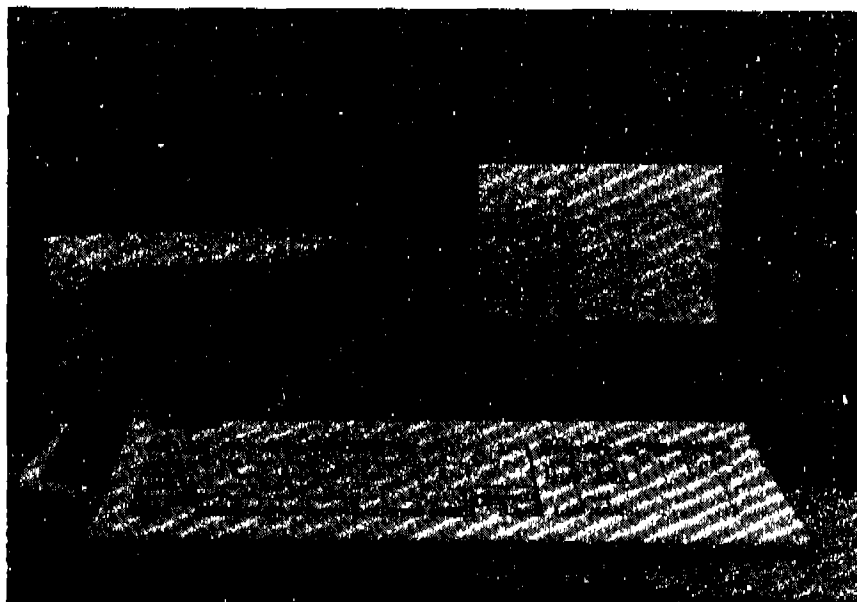
इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करती है कि उक्त माडल के अनुमोदन प्रमाण पत्र के अन्तर्गत इसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित इसी शृंखला के समरूप मेक, यथार्थता और निष्पादन वाले 10 टन/2 कि. ग्रा., 20 टन/5 कि. ग्रा., 40 टन/10 कि. ग्रा. और 60 टन/20 कि. ग्रा. की अधिकतम क्षमता वाले तुलन उपकरण भी हैं।

New Delhi, the 26th May, 1998

S. O. 1123 — Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 56 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic conversion kit for converting mechanical weighbridges into machines with digital display of type "LCS" series of class III accuracy (Medium accuracy) and with brand name "WEIGH-100" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s LCS Controls Private Limited, 62A, R. K. Shanmugam Road, K. K. Nagar, Chennai—600078, and which is assigned the approval mark IND/09/97/54;

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 30000 kg and minimum capacity of 100 kg. The verification scale interval (e) is 5 kg. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of sides 12 × 3 metre. The LED display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts and frequency 50 Hertz, alternate current power supply.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 10t/2 kg, 20t/5 kg, 40t/10 kg and 60t/20 kg, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[F No. WM 21 (91)/96]

RAJIV SRIVASTAVA, Addl. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मई, 1998

का.सं.1124.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकॉम डिपार्टमेंट, विशाखापट्टनम के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, विशाखापट्टनम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/214/93-आई.आर. (डी. यू.)]

के.वी.बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 14th May, 1998

S.O. 1124.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Visakhapatnam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Department, Visakhapatnam and their workman, which was received by the Central Government on 14-5-1998.

[No. L-40012/214/93-IR (DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-
LABOUR COURT, VISHAKHAPATNAM

PRESENT :

Sri K. Satyanand, B.Sc., LL.M., Chairman and Presiding Officer.

Monday, the 30th day of March, 1998

I. T. I. D. No. (C) 4/95

BETWEEN

P. Narayana Rao,
D. No. D-1, Burma Colony,
Malkapuram,
Visakhapatnam-530011.

.. Workman

AND

Telecom District Manager,
Office of the Telecommunications,
Visakhapatnam-20

.. Management

This dispute coming on for final hearing before me in the presence of Sri M. Ramkoti, Advocate for management and the workman in person, upon hearing the arguments of both sides and on perusing the entire material on record, the court, passed the following :

AWARD

1. This is an industrial dispute that came to this court on reference by the Government of India which formulated the terms of reference as under :

"Whether the action of the management of Telecom Department, Visakhapatnam in terminating the services of Sri P. Narayana Rao, Ex-driver is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. The facts of the case are briefly as follows :

The workman claimed to have worked under the management as a lorry driver-cum-van driver for a period of 288 days upto 15th October, 1991 but he complained that he was removed from service all of a sudden without any notice. His representations to reinstate him did not bear any fruit. He also

complained that the rule of last come first go was not observed. Thus, prayed the court for the relief of reinstatement with back wages and continuity of service.

3. The management resisted the claim saying that the workman was engaged merely as a casual labour from 2-1-91 to 15-10-91 that too by a field officer and that the management did not appoint him. The management maintained that his engagement was merely on a contingent basis that too as a contract for service and that therefore he was not entitled to any relief.

4. In support of his case the workman examined himself as WW-1. He marked Exs. W-1 to W-3. The management examined the Sub-divisional engineer as MW-1. Heard both sides.

5. The points that arise for consideration are :

- (1) Whether the retrenchment of the service of the workman is valid?
- (2) To what relief.

6. Point No. 1.—In this case the basic facts are not in dispute. The management admitted that the workman worked from 2nd January, 1991 to 15th October, 1991. In the statement of the management it clearly stated as follows :

"The claimant was engaged on contingent basis on a contract for service casually on daily wage basis and his engagement if any is not a contract of service in law"

But strangely the management never appointed him happened to be their case. It is also not the case of the management that he was duly discharged from service by following the conditions under Section 25-F, however in the evidence the management came up with the theory that the workman was specifically appointed only for the specific period and his appointment was not renewed that period. If really that is the case then the management ought to have produced the appointment letter showing that the contract of employment that the management entered into with the workman was only for a fixed period. The record of the management did not disclose anywhere that the workman came to be appointed expressly for a certain period and his employment expired with the expiry of that period. The management did not mark any documents to show that the workman was appointed specifically for that period. The management failed to prove a contract stipulating the duration of the employment so that could have urged successfully that the discharge of the workman was merely co-terminus with the expiry of the contract period. In fact, there was no such specific pleading, much less proof. Thus, the facts are very clear that the workman had worked for more than 240 days and the management retrenched him without following the provisions of the I. D. Act. This makes the retrenchment illegal. The learned counsel for the management, however, contended that the telecom department was not an industry. That is no more a tenable argument. In ATR 1998 (SC) 656 the Supreme Court categorically held that telecom department of the union of India is an industry. Thus, there are no grounds to hold that the workman is not entitled to the relief prayed.

7. Point No. 2.—Once the retrenchment is found to be illegal it naturally follows that the workman should be given the benefits due to him as per law settled by the higher courts but here is a case where the workman considerably delayed moving the court for his relief. There may be various reasons but still such kind of delay will have some adverse effect on the measure of back wages though it cannot disentitle him from getting the main relief as such. In these circumstances, an award is passed directing the management to reinstate the workman with 50% back wages and continuity of service. He is also entitled for costs in a sum of Rs. 500 (Rupees five hundred only).

Dictated to stenographer by her given under my hand and seal of the court this 30th day of March, 1998.

K. SATYANAND, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 मई, 1998

का०आ० 1125 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकॉम डिपार्टमेंट विशाखापटनम के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, विशाखापटनम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/178/93-आई.आर. (डी यू)]
के०वी०वी० उष्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1998

S.O. 1125.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Visakhapatnam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Department, Visakhapatnam and their workman, which was received by the Central Government on 14-5-1998.

[No. L-40012/178/93-IR (DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM- LABOUR COURT VISAKHAPATNAM

PRESENT :

Sri K. Satyanand, B.Sc., LL.M., Chairman and Presiding Officer.

Monday, the 30th day of March, 1998

I T. I. D. No. (C) 2/95

BETWEEN

R. Katcheeru,
C/o Reddy Sanyas,
Purushottampuram Village and P.O.
Yellamanchili Mandal,
Visakhapatnam Distt-531055 ...Workman

AND

Divisional Engineer,
Co-axial Maintenance,
Telecom Department,
Visakhapatnam-530001 ...Management

This dispute coming on for final hearing before me in the presence of Sri M. Ramakrishna Raju, Advocate for workman and Sri M. Ramakoti, Advocate for management, upon hearing the arguments of both sides and on perusing the entire material on record, the court passed the following :

AWARD

1. This is an industrial dispute that came upto this court on reference by the Government of India casting the terms of reference as under :

"Whether the action of the management of Divisional Engineer Coaxial, Visakhapatnam in terminating the services of Sri R. Katchooru is justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. The facts of the case as called out from the statements of the workman and the management are briefly as follows :

The workman claimed to have joined the service of the management in question on 8-3-84 as an office assistant in the Coaxial Maintenance, Tuni, East Godavari Dist. A.P. he claimed to have worked at Tuni upto 31-3-86 continuously for a total period of 610 days. While so the management without any reasonable cause terminated the service of the workman on 31-3-86 without following the procedure laid down in the provisions of the Industrial Disputes Act. According to workman the termination was, therefore, illegal.

He also complained that his juniors were retained in service in violation of the provisions of Section 25-G of the I. D. Act.

3. The management on the other hand, contested the claim saying that the workman came to be appointed only for a short period to safeguard the coaxial Cables. It also contended that the workman was appointed merely on casual basis and without any regular procedure of employment. The management contended that the services of the workman were terminated with the completion of the work. The management also commented that the workman kept quiet for 7 years, as such he cannot get back wages.

4. In support of his case the workman examined one of his co-workers who was made permanent as WW-1. He examined himself as WW-2. He also exhibited 3 documents. The muster book is marked as Ex. W-1. Statement of muster particulars is marked as Ex. W-2. He also marked papers showing his employment particulars as Ex. W-3. The management on the other hand, examined the sub-divisional engineer, Tuni as MW-1. It marked Exs. M-1 to M-9. Heard both sides.

4. The points that arise for consideration are :

(1) Whether the retrenchment of the service of the workman is valid?

(2) To what relief?

5. Point No. 1.—In this case the basic facts are not in dispute. The management admitted that the workman worked from 8-3-84 to 31-1-86. In the statement of the management is clearly stated as follows :

"In such a situation the claimant had been engaged on casual basis by the JEs only during the period from 12-3-84 to 31-1-86."

It is not the case of the management that he was duly discharged from service by following the conditions in Section 25-F. However, in the evidence, the management came up with the theory that the workman was specifically appointed only for the period from 8-3-84 to 31-1-86 and his appointment was not renewed beyond 31-1-86. If really that is the case then the management ought to have produced the appointment letter showing that the contract of employment that the management entered into with the workman was only for a fixed period. The record of the management did not disclose anywhere that the workman came to be appointed expressly for a certain period and his employment expired with the expiry of that period. The management marked as many as 9 documents. None of these documents shows that the workman was appointed specifically for the period upto 31-1-86. Ex. M-1 and M-2 clearly show the work particulars and the work orders. They do not show that the workman was categorically appointed upto 31-1-86 only. Exs. M-3 to M-9 are totally silent of this aspect and on the other hand, they were filed to show that his man and another workman were not appointed against the cadre strength. We are not concerned with all these niceties. The management made a foolish attempt to take advantage of the exception in Section 2(bb) to Section 2(cc) defining retrenchment. But it miserably failed in as much as it failed to prove a contract stipulating the duration of the employment that it could have urged successfully that the discharge of the workman was merely coincident with the expiry of the contract period. In fact there was no such specific pleadings much less proof. Thus, the facts are very clear that the workman had worked for more than 240 days and the management retrenched him without following the provisions of the I. D. Act. This makes the retrenchment illegal. The learned

counsel for the management, however, contended that the telecom department was not an industry. That is no more a tenable argument. In AIR 1998 (SC) 656 the Supreme Court categorically hold that telecom department of the union of India is an industry. Thus, there are no grounds to hold that the workman is not entitled to the relief prayed.

6. Point No 2.—Once the retrenchment is found to be illegal it naturally follows that the workman should be given the benefits due to him as per law settled by the higher courts. But here is a case where the workman delayed as many as 7 years for moving the court for his relief. There may be various reasons but still such kind of delay will have some adverse effect on the measure of back wages though it cannot disentitle him from getting the main relief as such. In these circumstances, an award is passed directing the management to reinstate the workman with 50% back wages and continuity of service. He is also entitled for costs in a sum of Rs. 500 (Rupees five hundred only).

Dictated to and transcribed by her given under my hand and seal of this court this the 30th day of March, 1998.

K. SATYANAND, Presiding Officer

APPENDIX OF EVIDENCE IN I.T. I. D. No. 2/95 (C) WITNESSES EXAMINED

For Workman :

WW-1—P. B. Rama Raju.

WW-2—R. Kacheru.

For Management :

MW-1—B. Sudershan Rao.

DOCUMENTS MARKED

For Workman :

Ex. W-1—Muster book for the period from 8-3-84 to 31-8-88.

Ex. W-2—Statement of Muster particulars from 8-3-84 to 31-1-86.

Ex. W-3/19-3-88—Documents showing the date of appointment and termination of the workman.

For Management :

Ex. M-1—Register the work particulars of Mazdoors.

Ex. M-2—Work Order Book from 1-1-83 to 6-7-90 (book).

Ex. M-3/10-1-84—Sanction orders for employment casual mazdoors for a period of 6 months.

Ex. M-4/30-4-84—Approval for extension of employing 2 casual Mazdoors for a period of 4 months w.e.f. 2-4-84.

Ex. M-5/28-8-84—Approval for extension of casual mazdoors for 6 months w.e.f. 2-8-84.

Ex. M-6/8-1-85—Approval of extension of 2 casual mazdoors for 6 months w.e.f. 2-2-85.

Ex. M-7/15-7-85—Approval for extension of employing 2 casual Mazdoors for further period of 6 months w.e.f. 2-8-85.

Ex. M-8/19-9-85—Refusal order for request for extension of employment of 2 Mazdoors in VM Town limits.

Ex. M-9/23-6-89—Documents showing the sanction Mazdoors for the year 1989-90.

नई दिल्ली, 14 मई, 1998

का०आ० 1126 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकॉम डिपार्टमेंट, विशाखापटनम के प्रत्यक्ष के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध

में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, विशाखापटनम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/177/93-आई आर (डी यू)]

के०वी०बी० उष्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1998

S.O. 1126.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Visakhapatnam as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Department, Visakhapatnam and their workman, which was received by the Central Government on 14-5-98.

[No. L-40012/177/93-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL, CUM-
LABOUR COURT VISAKHAPATNAM

PRESENT :

Sri K. Satyanand, B. Sc., LL., M., Chairman & Presiding
Officer

Monday, the 30th day of March, 1998

I.T. I.D. (C) 3/95

BETWEEN :

K. Nageswara Rao,
C/o. Chinna Satyam,
Kondanarapeta,
TUNI-533 401 E.G. Dist.

.. Workman.

AND

The Divisional Engineer,
Coaxial Maintenance,
Telecom Department,
Visakhapatnam-530 001.

.. Management.

This dispute coming on for final hearing before me in the presence of Sri M. Ramakrishna Raju, advocate for workman and Sri M. Ramakoti, advocate for management upon hearing the arguments of both sides and on perusing the entire material on record, the court passed the following :

AWARD

1. This is an industrial dispute that came up to this court on reference by the Government of India casting the terms of reference as under :

"Whether the action of the management of Divisional Engineer Coaxial, Vishapatnam in terminating the services of Sri K. Nageswara Rao is justified "

"If not to what relief the workman is entitled to ?"

2. The facts of the case as culled out from the statements of the workman and the management are briefly as follows : The workman claimed to have joined the service of the management in question on 4-3-84 as an Office Asst. in the Coaxial Maintenance, Tuni, East Godavari Dist., A.P. He claimed to have worked at Tuni upto 31-1-86 continuously for a total period of 610 days. While so the management without any reasonable cause terminated the services of the workman on 31-3-86 without following the procedure laid down in the provisions of the Industrial Disputes Act. According to workman the termination was, therefore, illegal. He also complained that his juniors were retained in service in violation of the provisions of Sec. 25G of the I.D. Act.

3. The management on the other hand, contested the claim saying that the workman came to be appointed only for a short period of safeguard the coaxial Cables. It also con-

tended that the workman was appointed merely on casual basis and without any regular procedure of employment. The management contended that the services of the workman were terminated with the completion of the work. The management also commented that the workman kept quit for 7 years, as such he cannot get back wages.

4. In support of his case the workman examined one of his Co-workers who was made permanent as WW1. He examined himself as WW2. He also exhibited one document the muster book marked as Ex. W1. The management on the other hand, examined the sub-divisional engineer, Tuni as MW1. It marked Exs. M1 to M8. Heard both sides.

5. The points that arise for consideration are :

1. Whether the retrenchment of the service of the workman is valid ?
2. To what relief ?

6. Point No. 1.—In this case the basis facts are not in dispute. The management admitted that the workman worked from 4-3-84 to 31-1-88. In the statement of the management it clearly stated as follows :

"In such a situation the claimant has been engaged on casual basis by the JSs only during the period from 4-3-84 to 31-1-86."

It is not case of the management that he was duly discharged from service by following the conditions under Sec. 25F. However, in the evidence the management came up with the theory that the workman was specifically appointed only for the period from 4-3-84 to 31-1-86 and his appointment was not renewed beyond 31-1-86. If really that is the case then the management ought to have produced the appointment letter showing that the contract of employment that the management entered into with the workman was only for a fixed period. The record of the management did not disclose anywhere that the workman came to be appointed expressly for a certain period and his employment expired with the expiry of that period. The management marked as many as 8 documents. None of these documents shows that the workman was appointed specifically for the period upto 31-1-86. Exs. M1 and M2 clearly show the work particulars and the work orders. They do not show that the workman was categorically appointed upto 31-1-86 only. Exs. M3 to M8 are totally silent of this aspect and on the other hand, they were filed to show that this man and another workman were not appointed against the cadre strength. We are not concerned with all those necessities. The management made a feable attempt to take advantage of the exception in Sec. 2 (bb) to Sec. 2(oo) defining retrenchment, but miserably failed in as much as it failed to prove a contract stipulating the duration of the employment so that it could have urged successfully that the discharge of the workman, was merely co-terminus with the expiry of his contract period. In fact, there was no such specific pleadings much less proof. Thus, the facts are very clear that the workman had worked for more than 240 days and the management retrenched him without following the provisions of the I.D. Act. This makes the retrenchment illegal. The learned counsel for the management, however, contended that the telecom department was not an industry. That is no more a tenable argument. In AIR 1998 (SC) 656 the Supreme Court categorically held that telecom department of the Union of India is an industry. Thus, there are no grounds to hold that the workman is not entitled to the relief prayed.

7. Point No. 2.—Once the retrenchment is found to be illegal it naturally follows that the workman should be given the benefits due to him as per law settled by the higher courts. But here is a case where the workman delayed as many as 7 years for moving the court for his relief. There may be various reasons but still such kind of delay will have some adverse effect on the measure of back wages, though it cannot disentitle him from getting the main relief as such. In these circumstances, an award is passed directing the management to reinstate the workman with 50 per cent back wages and continuity of service. He is also entitled for costs in a sum of Rs. 500/- (Rupees five hundred only).

Dictated to steno transcribed by her given under my hand and seal of the court this the 30th day of March, 1998.

K. SATYANAND, Presiding Officer.

APPENDIX OF EVIDENCE IN I.D. No. 3/95 (C) WITNESSES EXAMINED

For Workman :

MW1 B. Sudershan Rao.
WM2 K. Nageswar Rao.

For Workman :

WM1 P. B. Rama Raju
WM2 Nageswar Rao.

For Workman :

MW1 B. Sudershan Rao.

DOCUMENTS MARKED

For Management :

Ex. W1—Muster book for the period 13-2-84 to 6-12-85.

For Management :

Ex. M1—Documents showing the work particulars of the mazdoors.

Ex. M2—Work Order book from 1-3-84 to 21-3-86.

Ex. M3 10-1-94—Sanction orders for employing 2 casual Mazdoors for a period of 6 months.

Ex. M4 30-4-84—Approval for extension of employing 2 casual Mazdoors for a period of 4 months, w.e.f. 2-4-84.

Ex. M6 28-8-84—Approval for extension of employing 2 casual Mazdoors for 6 months w.e.f. 2-8-84.

Ex. M6 8-1-85—Approval for extension of employing 2 casual Mazdoors for further period of 6 months, w.e.f. 2-2-86.

Ex. M7 15-7-85—Approval for extension of employing 2 casual Mazdoors for further period of 6 months w.e.f. 2-8-85.

Ex. M8 19-9-85—Refusal Order for request for extension of employment of 2 mazdoors in VM Town limits.

नई दिल्ली, 15 मई, 1998

कां० अ० 1127 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ए.स.डी.ओ. टेलीग्राफ छत्तरपुर (म०प्र०) के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/109/90-आई आर (डी यू)]

के०वी०बी० उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th May, 1998

S.O. 1127.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.D.O. Telegraph, Chhattarpur (M.P.) and their workman, which was received by the Central Government on 15-5-98.

[No. L-40012/109/90/TR (DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

New Delhi, the 15th May, 1998

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जबलपुर म०प्र०

डी०एन० दीक्षित

पीठासीन अधिकारी

प्र०क्र० सीजीआईटी/एलसी/आर/11/91

श्री नंदीलाल कुशवाहा

आत्मज श्री मोहनलाल कुशवाहा

ग्राम मुकरबा पोस्ट मउमहानियां

जिला-छतरपुर-471001 (म०प्र०)

---प्रार्थी

विरुद्ध

सब-डिवीजनल आफिसर,

दूरसंचार विभाग, छतरपुर (म.प्र.)

---प्रतिप्रार्थी

अवार्ड

दिनांकित : 4-3-1998

1. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने आदेश सं० एल-40012/109/90-आई०आर० (डीयू) दिनांकित 31-1-91 के द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस अधिकरण को भेजा है:—

अनुसूची

"Whether the action of Management of S.D.O. Telegraph, Chhatarpur (M.P.) in terminating the services of Shri Nandilal Kushwaha w.e.f. January, 1990 is justified? If not, what relief he is entitled to?"

2. श्रमिक श्री नंदीलाल कुशवाहा इस प्रकरण में दिनांक 27-8-97 को उपस्थित हुआ। अगली पेशी दिनांक 29-9-97 को श्रमिक और उसके अभिभाषक दोनों उपस्थित हो गए। इसके पश्चात् दिनांक 24-10-97, दिनांक 25-11-97, दिनांक 20-1-98 और दिनांक 3-3-98 को श्रमिक और उसके अभिभाषक दोनों अनुपस्थित रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रमिक को कोई रुचि वर्तमान विवाद के निराकरण की नहीं है। वर्तमान विवाद में अवार्ड प्रबंधन के पक्ष में दिया जाता है। दोनों पक्ष इस प्रकरण का अपना-अपना व्यय वहन करें।

3. नियमानुसार अवार्ड की प्रतियां भारत-सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

डी०एन० दीक्षित, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 15 मई, 1998

का०आ० 1128:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विद्यालय, मुम्बई के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मुम्बई, नं० 2 के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-42012/197/94-आई०आर० (डीयू.)]

के०वी०बी० उण्णी, डैस्क अधिकारी

S.O. 1128.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Mumbai, No. 2 as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kendriya Vidyalaya, Kamptee and their workman, which was received by the Central Government on 15-5-98.

[No. L-42012/197/94-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II, MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/2 of 1997

Employers in relation to the Management of Kendriya Vidyalaya, Kamptee.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer.—Mr. R. S. Sundram, Advocate.

For the Workmen.—Miss Sulekha Kumbhare, Advocate,

Mumbai, dated 21st April, 1998

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-42012/197/94-IR(DU) dated 6-1-1997, had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of Kendriya Vidyalaya, Kamptee (Maharashtra) in terminating the services of Shri Subhan M. Gajbe is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. Subhan M. Gajbe, the workman filed a statement of claim at Exhibit-2. He contended that as per the order dtd. 12-4-89 he continued to work as a 'Peon' in category 'D' of Kendriya Vidyalaya the employer. He continuously worked without break in service till his service was orally terminated on 15-9-93. It is averred that while terminating his service no notice was given nor any retrenchment compensation. The employer did not follow the necessary provisions of the Industrial Disputes Act of 1947 for the termination.

3. The workman pleaded that after the first appointment in 1992 he was removed from service and again was reappointed as his name was sponsored by the employment exchange. When he was appointed he was within the prescribed age limit for getting the employment. He was given an appointment only on selection basis at the rate of Rs. 4 per day and was asked to work upto September, 1993. He was not paid wages as applicable to Group 'D' employee. He was given oral assurances that he would be paid the wages as per the rules and he will be absorbed on permanent basis. It is submitted that as the employer did not employ him permanently he raised an Industrial Dispute. He prayed that he may be reinstated in service with full back wages and other reliefs.

4. The management resisted the claim by the written statement (Exhibit-6). It is averred that the workman was appointed as a peon on adhoc basis by an order dtd. 12-4-98. He was appointed for the period of six months. Thereafter his services automatically came to an end. It is denied that he was sponsored by the employment exchange and he was selected on a regular basis. It is submitted that he was appointed for same period on a daily wages at the rate of Rs. 10.

5. The employer denied that it ever assured the workman to be absorbed on a regular basis. It is pleaded that at no time the name of the worker was sponsored by the employment exchange and he was selected. It is denied that the workman continuously worked from 12-4-89 till the alleged date of termination. It is asserted that the workman had no qualification as required as per the rules and was not eligible for appointment as per the Kendriya Vidyalaya Sanghatana recruitment rules. It is asserted that even as per the law the workman cannot acquire any right of regular employment. It is submitted that under such circumstances the reference may be answered accordingly.

6. The workman filed a rejoinder at Exhibit-8. He reiterated the contentions taken by him in the statement of claim and denied the contentions of the employer which are appearing in the written statement.

7. The issues and my findings there on are as follows :—

Issues	Findings
--------	----------

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Whether the Tribunal had jurisdiction to decide the reference ? | Yes. |
| 2. Whether Gajbe was appointed as an ad-hoc, peon ? | Yes. |
| 3. Whether the action of the management of Kendriya Vidyalaya, Kamptee in terminating the services of Gajbe is legal and justified | Yes. |
| 4. If not, to what relief the workman is entitled to | Does not survive. |

REASONS

8. At the outset I must say that so far as the point of jurisdiction is concerned none of the parties submitted any argument in respect of the same. It appears that the parties submitted to the jurisdiction of this Tribunal. Under such circumstances I come to the conclusion that the Tribunal had jurisdiction to decide the reference.

9. Subhang Mahadeo Gajbe (Exhibit-10) the workman affirmed that he was first appointed by an order dated 12-4-98 (Exhibit-7/1). After perusal of that Memorandum it is very clear that his appointment was on ad-hoc basis for six months from the date of the joining in the Vidyalaya. The workman accepted the offer of appointment (Exhibit-7/2.) He also accepts that he was relieved from service by an order dtd. 12-10-89 (Exhibit-7/3). From the documents on the record which I have referred above it is very clear that the workman was not selected on a regular basis nor his appointment was in a regular cadre. He was appointed on ad-hoc basis and for a period of six months and thereafter he was terminated.

10. Much of the argument on behalf of the worker was that he was appointed on the basis of the recommendation by Employment Exchange. After perusal of the Memorandum (Exhibit-7/1) it does not reveal that his selection is on that basis. No doubt in that memorandum there is a mention of employment exchange registration No. 19483/80 at Nagpur. If really he would have been selected on the basis of the recommendations of the names by Employment Exchange then the order would not have been for the period of six months on ad-hoc basis but it would have been on a regular appointment on probation. It can be further seen that Exhibit-7/4 is the names of candidates sponsored by Employment Exchange for Group 'D' employment to the Principal Kendriya Vidyalaya. Gajbe admits the position that in the said list the name of Subhash is mentioned and his name is Subhan. According to him he is same man. If that would have been the position he should have got his name corrected in that list through employment exchange but it appears that he had not taken any steps to that effect.

11. The workman had produced Memorandum at Exhibit-9/1 dtd. 25-3-89, 10-11-89, 8-8-92 and 22-12-92. It relates to one Subhash M. Gajbir and he was called for an interview because his name was sponsored by the employment exchange, Nagpur. Ratna Gangully (Exhibit-14/A) Principal of the Kendriya Vidyalaya affirmed that the workman's name was never recommended by Employment Exchange and it was of one Subhash. On the basis of the record her testimony has to be accepted.

12. Mrs. Gangully admits the position that the workman was employed on casual basis also. But that does not give him any right to absorption on a permanent basis. There rules of recruitment so far as Kendriya Vidyalaya is concerned. Exhibit-16/1 is the written submissions of Kendriya Vidyalaya before the Assistant Labour Commissioner. The working days are mentioned on page, 3. After perusal of the same it also cannot be said that the worker continuously worked for more than 240 days in a year preceding his termination. It is very clear from the testimony of Gangully that the ad-hoc appointment of the daily wages appointment are carried out till the regular person is appointed. It is because it takes time for doing so and the Vidyalaya should not suffer for the same. There is no reason to reject her testimony.

13. In the written argument submitted on behalf of the workman it is tried to submit that the person is appointed on a regular basis and the workman was entitled for that post. I am not inclined to accept it because of the explanation given by the Principal.

14. Gangully the Principal affirmed that there are two types of work available and the work allotted to the workman was of a gardener and that too on daily wages. So far as the person engaged on daily wages no appointment letter was given and there is no order of termination. It is therefore no notice was given to the workman for termination nor any retrenchment compensation. In other words her case appears to be that his service is terminated automatically after the allotment of casual work is over. There is no illegality in it. The action appears to be legal and justified. In the result I record my findings on the issues accordingly and pass the following order :

ORDER

The action of the management of Kendriya Vidyalaya Kamptee (Maharashtra) in terminating the services of Shri Subhan M. Gajbe is legal and justified.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 मई, 1998

कां०आ०:1129—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार किरीबुरु आयर्न ओर माईन के [प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-26012/14/86-डी-3(बी)डी-4(बी)]
के०बी०बी० उष्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th May, 1998

S.O. 1129.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Kiriburu Iron Ore Mine and their workman, which was received by the Central Government on 15-5-98.

[No. L-26012/14/86-D-III(B)|D.IV(B)]
K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

New Delhi, the 15th May, 1998

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT
DHANBAD

PRESENT :

Shri B. B. Chatterjee, Presiding Officer,
In the matter of an Industrial Dispute under
Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

REFERENCE NO. 59 OF 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of
Kiriburu Iron Ore Mine and their work-
man.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen : None.

On behalf of the employers : None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad, the 30th April, 1998

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-26012/14/86-D.III.B/DIVB dated, the 16th February, 1988.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Kiriburu Iron Ore Mine in treating the period of absence from 17-2-67 to 3-7-70 of Shri G. C. Sharma, now Assistant Gr. II as leave without wages, is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. In this case neither of the parties turned up nor took any steps. Several adjournments were granted to them and again notices were issued to them. But in spite of the issuance of notices to them they neither appeared nor took any steps. It therefore leads me to an inference that no dispute is existing between the parties presently. In the circumstances, I have no other alternative but to pass a 'No dispute' Award in the reference.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 15 मई, 1998

कां०आ० 1130:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के प्रबन्धन के संबंध में निम्नलिखित और उनके कर्मचारियों के बीच, अन्तर्गत में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशन करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[नं० एन-22012/9/89-आई आर (विधि)]
के०वी०बी० उण्णी, डेस्क अधिकारी

S.O. 1130.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust and their workman, which was received by the Central Government on the 15-5-98.

[No. L-32012/9/89-IR(Misc.)]

K.V.B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 29 of 1989

Parties :

Employers in relation to the management of
Calcutta Port Trust

AND

Their workmen

Present :

Mr. Justice A. K. Chakravarty, Presiding Officer.

Appearance :

On behalf of Management : Mr. G. Mukhopadhyay, Senior Labour Officer (IR).

On behalf of Workmen : Mr. S. Chatterjee, Joint Secretary of the union.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Port

AWARD

By Order No. L-32012/9/89-IR(Misc.) dated 22nd September, 1989 the Central Government in exercise of its powers under section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of Calcutta Port Trust Calcutta is justified in treating the period from 29-7-83 to 16-5-84 as on suspension in respect of Sri Changur Jadav, Porter No. 2-61-SB. If not, what relief is the workman entitled to?"

2. Union's case, in so far as it appears from its written statement and the rejoinder, is that the concerned workman Changur Jadav, Porter No. 2, Gang No. 61-SB was caught red handed on 22-7-1983 while committing a criminal offence by a person from Central Industrial Security Force and handed over to the Police. A criminal case was accordingly started against him. It, however, ended in the acquittal of the concerned workman. During the pendency of the criminal case, the concerned workman was suspended and he remained so from 19-7-1983 till 16-5-1984. Such suspension order was lifted on the

representation of the concerned workman. Provision for placing an employee under suspension from pay and duty is laid down in Rule 8 of the Calcutta Port Commissioners' Employees' (Discipline and Appeal) Rules, 1964 and the trustee generally adopts Fundamental Rules for regulating service conditions of its employees. After the concerned workman was allowed to join his duties, the management initiated a departmental enquiry against him and the decision in regard to his period of suspension was kept reserved. The union has alleged that in other similar cases where employees were suspended from pay and duty pending criminal cases, the period of suspension is treated to be on duty while employees were acquitted from the charges in the criminal case. The union has alleged that discriminatory treatment was meted out to the workman. The union has further alleged that the instant reference has no relevance to the memorandum of chargesheet, departmental proceedings and subsequent action taken in the matter. The union has accordingly prayed that the period of suspension of the concerned workman from 29-7-1983 to 16-5-1984 be considered as spent on duty and direction be issued upon the management for payment of all wages alongwith other benefits given to his colleagues.

3. The management in its written statement has alleged that Shri Jadav, the concerned workman while trying to go out of dock with 70 pieces of plastic toys was caught red-handed and was handed over to the police. He was placed under suspension by the Deputy Chairman of the Calcutta Port Trust, pending criminal proceeding started against him. After his acquittal by the court, on his prayer for resumption of duty, he was allowed to resume his duty with effect from 17-5-1984. The management, thereafter, started a disciplinary proceeding and on enquiry, he was found guilty of the charges by the Enquiry Officer. The Deputy Chairman of the Calcutta Port Trust upon consideration of the enquiry report, passed order for his removal from service with effect from 20-10-1985. An appeal was preferred to the Chairman of the Calcutta Port Trust and after giving a personal hearing to the concerned workman, he changed the punishment of dismissal from service to reduction of his pay by three stages for two years with cumulative effect. The said order was passed on compassionate ground and the period of his suspension remained to be treated as on suspension. The management also alleged that it was empowered under Rule 8(ii) of the Calcutta Port Trust Employees' (Discipline & Appeal) Rules, 1964 to suspend an employees' on his retention in custody on criminal charge. The management also alleged that it has every right to initiate a departmental enquiry against any employee even though he is exonerated of the criminal charge levelled against him. The management has further alleged that under the Fundamental Rules it has right to treat the suspension period as on suspension.

4. Heard the representatives of both sides.

5. The scope of the reference seems to be very limited in the sense that this Tribunal is called upon to consider whether the period from 29-7-1983 to 16-5-1984 during which period the workman was admittedly under suspension, is to be treated as on

suspension. It is very difficult, if not impossible, to understand the scope of the reference in the manner in which the schedule is framed. If the reference relates to justification of the order of suspension for the period stated above, the workman virtually has no case what-so-ever in as much as the legality and the validity of the suspension order was not under challenge either in the written statement filed by the union or in the evidence of the concerned workman adduced before the Tribunal.

6. The representative of the union, however, tried to impress upon this Tribunal that the subsequent enquiry proceeding which was initiated against the workman after his acquittal from the criminal case was bad. I am afraid that the said submission has nothing to do in this reference, or in other words, the validity of the proceeding which was initiated subsequently after his acquittal was never challenged in the written statement of the union. Moreover, it is an established law that the acquittal of any workman in any criminal case does not bar the management from proceeding against its workman departmentally. Representative of the union also wanted to challenge the legality and validity of the enquiry proceeding. The said matters may be subject matter of a different reference, but so far as the present reference is concerned that has nothing to do with the legality and validity of the enquiry proceeding. The union in its written statement has also admitted the said position and accordingly that was not challenged. Further, the enquiry proceeding having started at a later date after the concerned workman resumed his duty on his acquittal in the criminal case, the legality and validity of the enquiry has got nothing to do with the legality and validity of the suspension order or the treatment of such period of suspension by the management.

7. Though, as I have stated earlier that it is extremely difficult to understand the scope of the reference in view of the language in which its schedule has been framed, still then, it appears from the written statement of the parties that the main grievance of the concerned workman is that the management was wrong in considering the period of his suspension as on suspension and it, on the other hand, ought to have considered said period of suspension as on duty. Before proceeding to discuss this aspect of the matter, I am to refer to Rule 8 of the Calcutta Port Commissioners' Employees' (Discipline & Appeal) Rules, 1964 that the management has right to suspend an employee against whom a disciplinary proceeding is contemplated or pending or against whom a case in respect of any criminal case is under investigation or trial or when such employee is retained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding 48 hours. The workman having been taken in custody and the alleged criminal offence being under investigation or trial, the management exercised its right of suspension.

8. Regarding the consequence of such order of suspension, my attention was drawn to the Rule 54(1) of the Fundamental Rules which admittedly applies to the employees of the Calcutta Port Trust making it obligatory for the management to make a specific order whether or not the said period is to be

treated as period spent on duty. In the instant case, the workman was found guilty of the charges in the enquiry proceeding and the Deputy Chairman issued orders for his dismissal from service. An appeal was preferred by the concerned workman against the said order to the Chairman and the Chairman set aside the order of dismissal and reinstated him in service after awarding some minor punishment. It appears from the letter of the Secretary to the Traffic Manager dated 23rd August, 1985 (vide Ext. M-21) that the Deputy Chairman considered the matter and directed that the period in question, i. e., from 29-7-83 to 16-5-1984 was to be treated as on suspension, meaning thereby that the workman shall be entitled to get subsistence allowance for the said period. It thus appears that specific order was passed disentitling the workman to get his full pay during the period of his suspension. In sub-rule (2) of Rule 54 of the Fundamental Rules it is provided that if the government servant is fully exonerated, he shall be paid full pay and allowance to which he would have been entitled. As stated above, the workman was not fully exonerated of the charges in the departmental proceeding and he was ordered to be dismissed from service. On appeal, the appellate authority changed the dismissal order to reduction of increments on compassionate ground. That being so, no question of treating the suspension period as on duty cannot arise. In sub-rule (5) of Rule 54 of the Fundamental Rules it is stated that in all other cases the period of suspension shall not be treated as on duty. In the aforesaid circumstances, no wrong was committed by the management of Calcutta Port Trust in treating the period of suspension of the concerned workman as on suspension.

9. The schedule of the order of reference, as stated above, being not free from ambiguity and even upon consideration of the case as understood by the parties to this proceeding, I do not find any justification for the claim of the union for treating the suspension of the concerned workman as on duty. The management, therefore, was fully justified in rejecting the claim of the workman in that matter and considering the said period as on suspension. The concerned workman accordingly shall not be entitled to any relief in this case.

This is my Award.

A. K. CHAKRAVARTY, Presiding Officer

Dated, Calcutta,

The 4th May, 1998.

नई दिल्ली, 21 मई, 1998

का.आ. 1131 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार एम. डी. ओ., टेलीकॉम वारंगल डिस्ट्रिक्ट के प्रबन्धन के संबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/204/95-आई आर (डी यू)]

के.वी.बी. उण्णी, डैक अधिकारी

1403 GI/98—11.

New Delhi, the 21st May, 1998

S.O. 1131.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.D.O., Telecom, Warangal District and their workman, which was received by the Central Government on the 21-5-1998.

[No. L-40012/204/95-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL-I AT HYDERABAD

PRESENT :

Shri V. V. Raghavan, B.A., LL.B.,
Industrial Tribunal-I.
Dated : 25th day of April, 1998.
Industrial Dispute No. 38 of 1997.

BETWEEN :

Shri P. Lakshminarayana,
S/o. Shri P. Narasiah,
Nandanam—506 313,
Warangal District. .Petitioner

AND

The Sub-Divisional Officer,
Telecom Mahabubabad,
Warangal District. .Respondent.

APPEARANCES :

Shri C. Suryanarayana, Advocate for Petitioner.
Shri P. Damodar Reddy, Assistant Government pleader filed memo of appearance for the respondent.

Subsequently respondent set exparte on 26-3-1998.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by its order No. L-40012/204/95-IR (DU), dated 10-7-1997 referred the following industrial dispute u/s. 10(1)(d) and 2-A of Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication to this Tribunal :—

"Whether the action of Sub-Divisional Officer, Telecom, Mahabubabad, Warangal District in terminating the services of Shri P. Lakshminarayana Ex. Casual Mazdoor w.e.f. 1-10-1995 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled for?"

2. The petitioner-workman filed a claim statement on 26-12-1997. Though the Assistant Government Pleader filed memo of appearance on

15-10-1997 and though time was granted for filing counter from 26-12-1997 to 28-1-1998, 27-2-1998, 16-3-1998 and 26-3-1998, the counter is not filed. There was no representation on 26-3-1998 and so the respondent is set *ex parte*. The workman's evidence was recorded on 10-4-1998. The arguments are heard on 15-4-1998. No petition is filed for setting aside *ex parte* order till now. Hence an Award is passed on the material available on record.

3. The averments in the claim statement are as follows :

The petitioner belongs to a Scheduled Caste. The petitioner was appointed as casual mazdoor on 1-3-1986 by the Sub-Divisional Officer, Telecom, Mahabubabad to work in the working party of Shri M. Anantharamulu, Sub-Inspector Telegraphs, Mahabubabad. The petitioner got himself registered in the Employment Exchange on 23-3-1986. The petitioner was retrenched from service on 1-10-1988 on the ground that the Director General imposed a ban on 30-3-1985 and prohibited the fresh recruitment. The said order was set aside by the Central Administrative Tribunal dated 4-5-1988 in D.A. No. 529/88. The petitioner worked for more than 240 days and so he cannot be retrenched without following the procedure prescribed U/s. 25-F of the I. D. Act. The Supreme Court declared that no distinction can be drawn between workmen recruited before a cut off date like the said date 30-3-1985 and those that were recruited subsequently and that all workmen in employment for a year or more should be regularised. So the termination of the petitioner is *ab initio* void. He is entitled to reinstatement.

4. The petitioner examined himself as WW-1. He filed Exs.W-1 to W-5.

5. The point for consideration is whether the petitioner, is entitled to reinstatement with back wages and other benefits ?

6. POINT : The petitioner was appointed as casual labour on 1-3-1986 and he worked as such upto 30-9-1988 as evidenced by Ex. W-2 Book in which Sub-Divisional Officer Telecom Mahabubabad signed. Thus he worked more than 240 days. He cannot be retrenched without following section 25-F of the I. D. Act. In this case the retrenchment notice was not given and retrenchment compensation was not paid. So the retrenchment is invalid and the petitioner is entitled to reinstatement as casual labour. So far as the backwages are concerned, the petitioner relied upon the decision of Supreme Court in the case of Narotam Chopra vs. Presiding Officer Labour Court and Others [1989 Supreme Court Cases (L & S) 565] in which it was held that the termination without following the provisions U/s. 25-F of I. D. Act is *ab initio* void and the employee would be entitled to continuity of service alongwith back wages.

7. In view of the above decision, an Award is passed by directing the respondent to reinstate the petitioner P. Lakshminarayana into service with backwages and other benefits as casual labour.

Dictated to the stenotypist, transcribed by him, corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal this the 25th day of April, 1998.

V. V. RAGHAVAN, Industrial Tribunal.
Appendix of Evidence

Witness examined for Petitioner	Witness examined for Respondent.
------------------------------------	-------------------------------------

WW-1 : P. Lakshminarayana	NIL
---------------------------	-----

Documents marked for the petitioner :

- Ex. W-1 : Xerox copy of employment registration certificate of petitioner.
- Ex. W-2 : Note Book containing the working days particulars of the petitioner.
- Ex. W-3 : Complaint dated 8-12-1993 made to the Assistant Labour Commissioner (C) II Hyderabad by WW-1.
- Ex. W-4 : Minutes of conciliation.
- Ex. W-5 : Failure report submitted by the ALC-II to Government of India.

Documents marked for the respondent :
NIL.

नई दिल्ली, 21 मई, 1998

का.आ. 1132 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार लेफ्टीनेन्ट कोलोनल, ओ आई सी गार्डन 'ए', मैसे हेड क्वार्टर, 12 इन्फेन्ट्री, डिब्रीजन, C/O 56 ए.पी.ओ., जोधपुर के प्रबन्धकों के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जोधपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42011/139/96-आई आर (डी यू)]
के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 21st May, 1998

S.O. 1132.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jodhpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Lt. Colonel OIC Garden 'A' Mess Head Qtr., 12 Infantry Divn., C/O 56 APO, Jodhpur and their workman which was received by the Central Government on 21-5-98.

[No. L-42011/139/96-IR(DU)]
K. V. B UNNY, Desk Officer

अनुबन्ध

औद्योगिक न्यायाधिकरण जोधपुर।

पीठाधीन्य अधिकारी :—श्री चांदमल नांतला, आर.एच. जे.एस. औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय कैस) नं. 14/97 श्री चोथाराम पुत्र श्री मंगजाराम, निवासी ग्राम एकता नगर, चूना, ताका के पीछे, बनाइ रोड, जोधपुर।

...प्रार्थी

वनाम

लेफ्टीनेंट कर्नल, श्री.सी.सी. गार्डन 'ए' मैसे हेड-क्वार्टर, इन्फेन्ट्री डिबिजन मार्फत 56 ए.पी.आ. जोधपुर।

...अप्राथी

उपस्थिति :—

दोनों पक्षों की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

अधिनियम

दिनांक 27-4-1998

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. 42011/139/96 दिनांक 31-7-96 से श्रमिक तथा उसके नियोजक के मध्य उत्पन्न हुआ निम्नांकित विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत अधिनियमित हेतु इस औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रेषित किया जो दिनांक 4-12-1997 को नियमित औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) सं. 14/97 पंजीबद्ध हुआ :—

“Whether the action of the management of Lt. Colonel OIC Garden ‘A’ Mess Head Quarter 12 Infantry Division C/o. 56 APO Jodhpur in terminating the service of Shri Chowdharam Civil Garden is legal and justified? If not, to what relief he is entitled to”

उक्त रेफरेंस दर्ज होने पर सूचना पत्र दोनों पक्ष-कारान को भेजे गये प्रार्थी की तरफ से दिनांक 6-1-1998 को प्रतिनिधि खेमराम उपस्थित आये तथा वकालतनामा पेश किया तथा मांग सूचि पेश करने के लिए श्रवसर चार्ज, विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 6-1-1998 के पश्चात् तारीख 2-2-98 को सुनिश्चित की गई, उस रोज भी प्रार्थी की तरफ से मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तत्पश्चात् लगातार दो पेशियों पर प्रार्थी प्रतिनिधि ने मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया आज प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है तथा स्वयं प्रार्थी भी हाजिर नहीं है जिससे यही प्रतीत होता है कि प्रार्थी इस विवाद को आगे चलाने में रुचि नहीं रखता है तथा पक्षकारों के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अतः न्याय तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में “नोटिस्सप्युट एवार्ड” पारित किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अधिनियम

प्रार्थी प्रतिनिधि को लगातार मांग सूचि प्रस्तुत करने के लिए कई श्रवसर दिये जाने के बावजूद मांग-पत्र प्रस्तुत नहीं करने व आज स्वयं प्रार्थी या उसके प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने से यही प्रतीत होता है कि श्रमिक इस विवाद को आगे चलाने का इच्छुक नहीं है। अतः इस प्रकरण में “कोई विवाद नहीं रह जाने का अधिनियम (नोटिस्सप्युट एवार्ड) पारित किया जाता है”। इस अधिनियम की प्रति श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को प्रकाशन हेतु प्रेषित की जावे।

चांदमल नांतला, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 14 मई, 1998

का.शा. 1133:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ई.सी.एल. के प्रबन्ध तंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.-19011/4/85-डी. IV (बी.)]

लौली माऊ, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1998

S.O. 1133.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of E.C. Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 12-5-98.

[No. L-19011/4/85/DIV(B)]

LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 41 of 1986

PARTIES:

Employers in relation to the management of Paracole Colliery of M/s Eastern Coal-fields Limited.

AND

Their workman

PRESENT:

Mr. Justice A. K. Chakravarty ..Presiding Officer

APPEARANCE:

On behalf of Management—Mr. P. Banerjee, Advocate.

On behalf of Workmen—Mr. B. Paul, Advocate.
STATE : West Bengal. INDUSTRY : Coal.

AWARD

By Order No. L-19011(4)85-D.IV(B) dated 14-5-1986, the Central Government in exercise of its powers under section 10(1)(d) and (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether the Management of Parascole Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P. O.

Kajoragram, Distt. Burdwan (WB).

- (a) in not placing the workmen numbering 43 of the Colliery Workshop in Category V and Sh. Shankar Chatterjee, Machinist-cum-Driller in Cat. VI instead of Cat. IV;
- (b) in not granting pay protection and other service benefits to Sh. Basudeo, Electrician who came on transfer from Mukundapur Colliery of Kajora Area to the Workshop in 1985, and other employees who came to Workshop on transfer from different collieries in Kajora Area;
- (c) in not (i) regularising Sh. Bejoy Kumar Mishra working as Welder from 1984, (ii) designating Sh. Kanchan Mondal Latheman Helper as a Latheman, instead of a Machinist place in Cat. IV and (iii) paying subsistence allowance to Shri Birbal Bouri. Latheman suspended w.e.f. 26-6-1985 is justified? If not, to what relief the workmen concerned are entitled?”

2. The union has filed as many as four written statements in this case. The first is in respect of one workman in the name of Shri Harijan. It is alleged that the management of Parascole Colliery (M/s. Eastern Coalfields Ltd.) through its arbitrary action and unfair labour practice refused his promotion in Category VI. It was accordingly prayed that the workman should get his legitimate dues. In the second written statement, which is in respect of Shri Shankar Chatterjee, it is alleged that the management has deprived him of his promotion in Category VI by placing him in Category IV from 1978. It is alleged that on 1-3-1978 he was placed in Category IV as Machinist/Driller and the said workman was entitled to be promoted to Category VI. The same relief for his placement in Category VI is accordingly prayed for in his case. The third written statement is in respect of one Gauri Shankar Kuiri whose grievance is that he should have been placed in Category II instead of Category IV. It is alleged that the management having illegally and through unfair labour practice stopped his promotion the management should be directed to give the said promotion and to pay him his legitimate dues. The last written statement on

behalf of the union is in respect of Shri Kanchan Mondal who was promoted to Category IV as Lather Helper from 1978. His grievance is that he was entitled to be promoted to Category VI instead of Category IV. He, however, got his promotion in Category VI in 1988. He has alleged that Parascole Colliery which was merged in M/s. Eastern Coalfields Ltd. illegally and through unfair labour practice deprived him promotion to Category VI from 1978. He accordingly prayed for suitable orders in the matter and payment of his legitimate dues.

3. Four different written statements are also filed by the management to counter the allegations made in the written statements of the concerned workman. The management's case in respect of these employees is denial of the allegations of unfair labour practice or any illegality or arbitrariness in respect of the concerned workmen. The management has also alleged that the workmen of the cases in respect of whom the written statements were filed were not entitled to any further wage or allowance apart from what had been paid to them as their wages. The management also has given certain particulars regarding the date of appointment and the date of the last promotion of these workmen. Management accordingly prayed for dismissal of the claims made on behalf of the concerned workmen.

4. Two rejoinders, one on behalf of Shankar Chatterjee and the other on behalf of Kanchan Mondal were also filed by the union. The allegations in these rejoinders are more or less the same. In both the rejoinders they reiterated that they ought to have been placed in Category VI instead of Category IV from the date of their first promotion. They also claimed that juniors obtained the promotion before them.

5. Heard Mr. P. Banerjee, learned Advocate appearing for the management, Mr. B. Paul, learned Advocate appeared for the union and conducted the case of the concerned workmen till the evidence of the parties was concluded. The argument, however was heard in his absence as he did not appear. The matter being old and no useful purpose will be served by granting any further adjournment as the evidence is already there on record that I am disposing of the matter on the aforesaid basis.

6. Before I proceed to discuss the matter, it must be noted that the reference itself is a cumbrous one asking for disposal of number of disparate matters having no connection with each other for consideration of different claims of different workmen having no common link with each other, excepting that they were all employees of erstwhile Parascole Colliery. As each of the aforesaid matters may form subject matter of different reference it is not possible to consider all the claims in course of a single reference. Mr. B. Paul, learned Advocate appearing for the union obviously found this difficulty and having submitted before this Tribunal that he shall not press any other case excepting that of Shri Shankar Chatterjee, this Tribunal by its order dated 25-9-1996 recorded as follows :—

“Mr. Paul states that he has been authorised by the union to appear and has no instruction

in respect of the workmen excepting Mr. Chatterjee and gives up the case of others and he only wants to put question in respect of Mr. Chatterjee."

Obviously, this Mr. Chatterjee means Shri Shankar Chatterjee, Machinist-cum-Driller whose name appears in Item (a) of the schedule to reference. Item (a) of the schedule is for consideration of the matter concerning non-placement of the workmen numbering 43 of the Colliery Workshop in Category—V and Shri Shankar Chatterjee, Machinist-cum-Driller in Category—IV instead of Category—IV. Since the case is contested on behalf of Shankar Chatterjee alone, the other items concerned in the reference need not be answered for the present.

7. The case of Shankar Chatterjee is that he joined the colliery on 17-5-1963 in Category—III as underground/Haulage Khalasi and that he was promoted from Category—III to Category—IV on 1-3-1978. His grievance is that instead of promoting him to Category—IV Machinist/Driller on 1-3-1978, he ought to have been promoted to Category—VI and his wage ought to have been fixed in wage-group VI from the financial year 1977. His further case in his rejoinder is that his juniors have been promoted to Category—VI from the date of their promotion to Category—IV.

8. The union examined Shankar Chatterjee as WW-1 in this case. No other witness was examined on behalf of the union. In justification of his claim for accelerated promotion to Category—VI instead of Category—IV from 1-3-1978 i.e. the date on which he was promoted to Category—IV, he stated in his evidence that since he was working as a Machinist-cum-Driller and since all the machinists belong to Category—IV from 1-3-1978 i.e. the date on which Drillers belong to Category IV, V and VI. In the written statement the management has alleged that he had been working as Machinist since his last promotion. It will further appear from his evidence that he does not know whether there is any post in the name of Machinist-cum-Driller and that he was not given any appointment letter. From the pay-slips produced by the concerned workman it will appear that he was designated as Mach. Driller. It is not the case of Shri Chatterjee that Mach. Drillers are Category VI employees. No reason was shown by the concerned workman why he shall be entitled to accelerated promotion to Category—VI straight-way from Category III to which he admittedly belonged prior to his promotion in 1978. Shri Chatterjee also stated in his evidence that Shri S. N. Dubey, Shri Rajendra Routh, Shri Baijov Mishra and Shri Baijov Bouri were Machinists in Category—VI. Obviously, he mentioned these names to show that they were his juniors in service. No, however, admitted in his evidence that before they were given Category—VI, they were given Category—V.

9. Two witnesses were examined by the management. MW-1. A. K. Roy, Personnel Manager of the Eastern Coalfields Ltd. stated in his evidence that Shankar Chatterjee was posted on promotional post

as Machinist in Category—VI in 1978 and subsequently he was promoted to Category—V Machinist in 1989. He further stated in his evidence that there are machinists in Category IV, V and VI. He further stated that under the channel of promotion, no one can be promoted to Machinist Category—VI directly and they are to travel from Category IV to V and from Category V to Category VI. He was not cross-examined regarding the channel of promotion as stated by him.

Mr. G. D. Karmakar was examined as MW-2 in this case. He was Engineering-in-charge of Paraske Colliery. He also reiterated the evidence of MW-1 Mr. Roy. He stated that there were three posts of Machinists, namely, Category IV, V and VI and that the promotions are obviously from Category IV to Category V and Category V to Category VI. He further stated that prior to nationalisation in 1973, there were instances of promotion of persons from Category—IV to Category—VI, but after nationalisation, there was no such occasion. Regarding the duties of the machinist, he stated that his duty is drilling, lathe work and welding and that there was no post of machinist-cum-driller after nationalisation. He further stated in his evidence that in 1985 a list of persons to be promoted in Category—V was notified which included the name of Shankar Chatterjee.

10. From the office order dated 9-3-1989, vide Ext. W-1 it appears that Personnel Manager, Kajora Area approved the promotion of Shri Chatterjee, Machinist, from Category—IV to Category—V with immediate effect. That was clearly wrong because from Ext. W-4, which is an office order dated 7-8-1985 it appears that the promotion of the concerned workman, Shankar Chatterjee took effect from 2-8-1985.

11. Be that as it may, from the evidence discussed above, it is clear that the concerned workman Shankar Chatterjee has hopelessly failed to prove by any evidence what-so-ever that there was any scope of promotion from Category—III to Category—VI directly. On the other hand, from the discussion of the evidence of the witnesses, discussed above, it will be clear that the promotional channel from Category—III to Category—VI passes through Category—IV and Category—V. The instances shown by the concerned workman in respect of certain persons could not be verified through their examination. But the concerned workman had admitted in his cross-examination that before their elevation to Category—VI, they became Category—V employees. It is therefore, clear that on 1-3-1978 the workman was rightly promoted to the position of Machinist in Category—IV, which forms the bottom of the categories of machinists promoted from Category—III where he was admittedly working as Underground/Haulage Khalasi. No reason being shown for the claimed accelerated promotion to Category—VI that the normal channel of promotion from Category—IV to Category—V and from Category—V to Category—VI remained open for the concerned workman. I have already stated on the basis of Ext. W-4 that date of promotion of the concerned workman to Category—V Machinist should have been on 2-8-1985 instead of 9-3-1989 as wrongly ordered in the office order. (vide Ext. W-1).

12. The workman having already retired from service, he shall only be entitled to get the balance of money which may be due to him on account of difference of pay for posting him in Category-V from 9-3-1989, instead of 2-8-1985 i.e. the date on which the promotion must be deemed to have actually taken place.

13. Save and except as stated above, the workman shall not be entitled to any other relief.

This is my Award.

A. K. CHAKRAVARTY, Presiding Officer
Dated, Calcutta,
The 6th April, 1998.

नई दिल्ली, 14 मई, 1998

का.आ. 1134.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एम.ई.सी.एल. के प्रबन्धकों के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 12-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.-22012/62/90-आई.आर. (सी.)]

लोली माऊ, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1998

S.O. 1134.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.E.C. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 12-5-1998.

[No. L-22012/62/90-IR(C-II)]

LOWLI MAO, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

डी.एन. दीक्षित

पीठासीन अधिकारी

प्र.क्र.सी.जी.आई.टी./एल.सी./आर./70/91

जनरल सेक्रेटरी

छत्तीसगढ़ खदान कारखाना

मजदूर यूनियन, बंकीमोंगरा

पो.-बंकीमोंगरा

जिला-बिलासपुर (म.प्र.) 495447 ... प्रार्थी

विव.

सब-एग्जि. मैनेजर

एम.ई.सी.एल. बांकी कालरी

पो. बांकीमोंगरा

जिला-बिलासपुर (म.प्र.) 495447 ... प्रतिप्राची

अवार्ड

दिनांक 03-04-98

1. भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने आदेश संख्या : एल-22012/62/90-आई.आर. (कोल-2) दिनांक 10-4-91 के द्वारा निम्नलिखित विवाद निराकरण हेतु इस अधिकरण को भेजा है :—

अनुसूची

"Whether the Chattisgarh Khadan Karkhana Mazdoor Union, Bankimongra, District Bilaspur justified in its demand against management of Bankimongra and Surakachhar Collieries for receiving benefits of the CGIT Award No. (GIT/LC(R)(25)/1983 published in the Gazette of India dated 22-4-1989 in respect of MSG workers w.e.f 1-1-1979? If not, from which date the workmen are entitled to benefits?"

2. श्रमिक यूनियन के अनुसार कोयला उद्योग में कोयला मजदूरों के लिए कोल वेज बोर्ड अवार्ड दिनांक 15-8-67 से लागू हुआ। इसमें कोयला मजदूरों को केटेगरी-I से केटेगरी-6 तक में विभाजित कर उनका वेतनमान बनाया गया। इस अवार्ड में यह व्यवस्था है कि जहां कहीं भी कोई कोयला मजदूर उपरोक्त 6 केटेगरी में विभाजित नहीं किए गए हों, उन्हें प्रबंधन म्यानीय स्तर पर अगामी बातचीत के द्वारा सहमति के आधार पर इन्हीं 6 केटेगरीयों में से किसी एक केटेगरी में फिट कर सकता है। कोयला उद्योग में एमएसजी वर्कर्स की मान्य केटेगरी 6 है। दिनांक 1-1-75 से नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट के द्वारा न्यूनतम वेतन में परिवर्तन किया गया। बांकी कालरी ने दिनांक 8-5-78 से और सूरकछार कालरी ने दिनांक 27-5-78 से अपने खदानों में एमएसजी वर्कर्स को नियुक्त किया। इन भूचलाओं में एमएसजी वर्कर्स के कार्य विवरण वेतन भत्ते और इन्सेंटिव आदि का विवरण है। इन दोनों कालरी ने एमएसजी वर्कर्स के लिए केटेगरी-5 और केटेगरी-6 के बीच का वेतनमान दिया। इन्हीं कालरी में गिट्टी कालरी से एमएसजी वर्कर्स को लाकर इनको केटेगरी-6 से ऊपर का वेतनमान दिया। इस प्रकार इन दोनों कालरियों ने एक समान काम के लिए अलग-अलग वेतनमान दिए। एमएसजी वर्कर्स को सभी कालरियों ने दिनांक 1-1-79 से नया वेतनमान दिया। कालरी बांकी और सूरकछार ने फिर भी इनमें नियुक्त एमएसजी वर्कर्स को साढ़े पांच केटेगरी का वेतनमान दिया। इस विवाद को श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने इस अधिकरण को निराकरण हेतु भेजा है। इसका केस नं. आर/25/93 है। इस अधिकरण ने अवार्ड दिनांकित 13-9-83 में यह पाया कि बांकी और सूरकछार कालरी के एमएसजी वर्कर्स को केटेगरी-6 में रखने की यूनियन की मांग उचित है और वे उसी के हकदार हैं। इसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 22-4-89 को हुआ। इस अवार्ड के अनुसार दिनांक 1-1-79 से एमएसजी वर्कर्स को साढ़े पांच केटेगरी का वेतनमान अस्वीकार कर दिया गया है तथा

उन्हें केटेगरी-6 वेतनमान में रखने की मांग स्वीकार की गई है। दिनांक 1-1-79 से बांकी और सूरकछार कालरी के एमएसजी वर्कर्स केटेगरी-6 में पाए गए और इसी वेतनमान को पाने के अधिकारी हैं। इस वेतनमान अधिकरण के अवार्ड के पश्चात् सूरकछार कालरी ने दिनांक 22-11-89 से और बांकी कालरी ने दिनांक 18-11-89 से यह स्केल एमएसजी वर्कर्स को दिया। यूनियन चाहती है कि इन दोनों कालरियों के एमएसजी वर्कर्स को केटेगरी-6 का वेतनमान दिनांक 1-1-79 से दिया जाए।

3. प्रबंधन के अनुसार इस विवाद का निराकरण प्र. अ. आर/25/83 में हो चुका था। ऐसी स्थिति में वर्तमान विवाद दूसरी बार इस अधिकरण को नहीं भेजा जा सकता। पूर्व प्रकरण में इस अधिकरण को यह अधिकार था कि वह केटेगरी-6 का स्केल किस दिनांक से दिया जाएगा, इसका निराकरण करें। अगर इस अधिकरण ने तिथि नहीं निर्धारित की तो यूनियन को उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करनी थी। वेतन निर्धारण के लिए प्रबंधन और भिन्न-भिन्न यूनियन के बीच मीटिंग दिनांक 23-11-79 और 7-6-78 को हुई और सभी विवादों में महसूस हो गई। ऐसी स्थिति में वर्तमान विवाद नहीं उठाया जा सकता। एम. एस. जी. वर्कर्स ने कभी केटेगरी-6 का काम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में उनको केटेगरी-6 का वेतन पाने की पात्रता नहीं है। प्रबंधन का यह कहना है कि 20 वर्ष बाद विवाद को पुनः उठाना श्रमिकों के हितों में नहीं है। प्रबंधन चाहता है कि रिफरेन्स को अवैधानिक और अव्यावहारिक घोषित किया जाए।

4. अवार्ड दिनांक 13-7-88 का अथलोकन किया गया। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी ने यह पाया है कि बांकी और सूरकछार कालरी के एमएसजी वर्कर्स को केटेगरी-6 का वेतन पाने की पात्रता है। इसी अवार्ड की कंडिका-17 में यह उल्लेख है कि यूनियन ने जिस दिनांक से एमएसजी वर्कर्स की ट्रेनिंग पूर्ण हुई थी, उसी दिनांक से इनको केटेगरी-6 का वेतनमान देने की मांग की थी। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी ने यह लिखा है कि चूंकि रिफरेन्स में यह उल्लेख नहीं है कि किस दिनांक से इन श्रमिकों को केटेगरी-6 के वेतनमान की पात्रता है, इसलिए यह तिथि का निर्धारण नहीं कर रहे हैं।

5. अवार्ड दिनांक 13-9-88 के द्वारा कालरी बांकी और सूरकछार के एमएसजी वर्कर्स को इस अधिकरण ने केटेगरी 6 के वेतनमान को पाने की पात्रता पाई है। किस दिनांक से वे वेतन पाने के अधिकारी हैं, इसका निर्धारण नहीं किया है। प्रबंधन का यह कहना गलत है कि रिफरेन्स आर/25/83 में विवाद का निराकरण हो चुका है, इस कारण दूसरा रिफरेन्स नहीं किया जा सकता। पूर्व अवार्ड में किस दिनांक से एमएसजी वर्कर्स केटेगरी-6 का वेतनमान पाने के अधिकारी हैं, इसका निराकरण नहीं हुआ है। पहली बार इस अधिकरण के सामने किस तिथि से वेतनमान

दिया जाए, यह प्रश्न उठा है। प्रथम रिफरेन्स वैधानिक है तथा नियमों के अनुसार है।

6. अवार्ड का प्रकाशन भारत सरकार के गजट में 22-4-89 को हुआ। यूनियन यह वेतनमान दिनांक 1-1-79 से चाहती है। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी ने प्र. अ. आर/25/83 अवार्ड दिनांक 13-9-88 में कंडिका-17 में पाया है कि केटेगरी-6 में एमएसजी वर्कर्स उस दिन से वेतन पाने के पात्र हैं, जिस दिन उनकी ट्रेनिंग पूर्ण हुई। यूनियन ने यह कहीं नहीं बताया कि किस दिन इन श्रमिकों की ट्रेनिंग पूर्ण हुई। यह न्यायोचित है कि जिस दिन यह अवार्ड भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ, उस दिनांक से केटेगरी-6 का वेतनमान इन श्रमिकों को दिया जाए।

7. अवार्ड दिया जाता है कि भारत सरकार के गजट में प्रकाशन दिनांक 22-4-89 से बांकी और सूरकछार में कार्यरत एम. एस. जी. वर्कर्स को केटेगरी-6 का वेतनमान दिया जाए। राशि का वितरण वर्तमान अवार्ड के प्रकाशन के तीन माह के अंदर किया जाए। अगर यह वितरण तीन माह के अंदर नहीं किया जाता तो प्रकाशन के तीन माह बाद से इस राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देय होगा। दोनों पक्ष इस प्रकरण का अपना-अपना व्यय वहन करें।

8. अवार्ड की प्रतियां निश्चयानुसार भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

डी. एन. दीक्षित, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 14 मई, 1998

का. आ. 1135:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूच में, केन्द्रीय सरकार एफसीआई के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/177/94—आई आर (सी - II)]

लोली माऊ, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1998

S.O. 1135.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 12-5-98.

[No. L-22012/177/94-IR (C-II)]

LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL,
NEW DELHI

I.D. No. 71/95

In the matter of dispute :
BETWEEN :
Shri

The General Secretary,
FCIEU, E-12/D(MIG) Mayapuri
New Delhi.

Versus

The Managing Director,
FCI, 16-20 Barakhamba Lane,
New Delhi.

APPEARANCES :

None—for the workman.

Shri P. K. Sharma—for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-22012(177)/94-IR. (C-II) dated 1-6-95 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the management of FCI was justified over their denial to consider the demands of pay structure, introduction of selection grade, facility of accommodation, car allowance, revision of out of pocket allowance and synchronisation of overtime allowance to Asstt. Managers? If not, to what relief these workmen are entitled to "

2. In the statement of claim the employees union of the workman of the FCI alleged that they were recognised in 23 states and 4 zones of the Management. The Assistant Managers were the primary members of the Union and the Management had been taking stand for the demands of the Assistant Managers. They have been held as workmen by different Tribunals in the country. According to the Union the permanent demands of the Assistant Managers are as follows :—

(i) Revision of pay structure of Assistant Managers w.e.f. 1-8-83, 1-8-87 and 1-2-92 on par with benefit of wage revision given to category IV/III employees on IDA pattern with provision to give the benefit of pay fixation on IDA pattern already given to Assistant Grade-I on IDA pattern while allowing them to be promoted to HPPC scales prescribed for Assistant Managers with CDA pattern of DA. This fixation benefit is required to be given to Asstt. Managers on CDA pattern as well as IDA pattern to remove the anomaly created due to unlike pay fixation formula prescribed for pay fixation of A.G.I. on IDA pattern on their promotion to AM Post during 1-8-83 to 31-12-1988 as in absence of this benefit even the Asstt. Managers belonging to years 1972 to 1982 are drawing lesser pay than the Asstt. Managers promoted during 1-8-84 to 31-12-1988 availing benefit if IDA pattern and still coming back to CDA pattern. This union has already submitted a proposal for wage revision of Asstt. Managers alongwith category-III/IV to the management w.e.f. 1-2-1992 through our letter dated 16-8-95.

(ii) Introduction of selection grades for Asstt. Managers also on the line selection grade scheme was introduced for category-III/IV w.e.f. 1-12-1987 treating next grade on promotion to be the selection grade.

(iii) Removal of imbalances between cadre to cadre in the matter of promotion of Asstt. Managers as at present the last promotee from Technical cadre

belongs to year 1971, from depot and General cadre belongs to 1976, from Engineering and Accounts cadre belongs to 1978-79 and Movement cadre belongs to 1988. This disparity in the matter of promotion is to be ended as growth of Corporation should have been/should be shared by all cadres generally equally.

(iv) Facility of self leased accommodation with proper rates as in case of rates/provisions already provided for category-I officers. At present, the provision for leased accommodation exists but not the provisions for self leased accommodation.

(v) Although Asstt. Managers are eligible to draw car advance but they are not eligible for car allowance and hence provision for car allowance is required to be made for A. Ms. also.

(vi) The out of pocket allowance being given to Asstt. Managers for coming on duty on Sundays/ holidays requires a scrap and being workmen their entitlement for over-time allowance and synchronisation allowance is to be introduced /ensured on par with workmen of Cat. III/IV.

(vii) Matters concerning transfer of Asstt. Managers in shape of victimisation should be discussed with the Unions."

The Union has, thus, claimed that they were entitled to this leave and be granted.

3. The Management in its reply alleged that the Assistant Managers were not workmen as defined in section 2(S) of the I.D. Act. They were in the scale of 650-1200 (pre-revised) and were drawing salary exceeding statutory limit of Rs. 1600/- PM. They were holding that the category second post and the demands made by the Union in this case was not justified and their justified demands have already been accepted by the management.

4. The workman did not appear on 19-3-96 and were proceeded against ex parte which was set aside on 20-5-96. The Management then absented on 9-9-96 and was ordered to be proceeded against ex parte.

5. The workmen filed their affidavit in support of their case on 19-12-96 and the case was adjourned for workman evidence to 11-2-97. Nodav appeared on behalf of the workman on that date not the witness whose affidavit was filed was present for the cross-examination. Nobody appeared even thereafter for getting the ex parte proceedings set aside. In view of the above situation there is no evidence on record produced by either of the parties to hold the justification or otherwise of the demands for which this reference has been made to this Tribunal. In view of no evidence produced by the parties, I am of the Opinion that since the parties have taken no interest in this dispute, I, therefore, pass a No dispute award in this case leaving the parties to bear their own costs.

27th April, 98

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 14 मई, 1998

का. आ. 1136:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सैसर्मे वी.सी.सी.एन. के प्रबन्धन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन—22012/480/94—आई आर (सी—II)]

लौली माऊ, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1998

S.O. 1136.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on the 12-5-1998.

[No. L-22012/480/94-IR(C-II)]

LOWLI MAO, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL.

Reference No. 24 of 1995.

PARTIES :

Employers in relation to the management of
Damagoria Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Shri R. S. Mishra,
Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri P. K. Mahapatra,
Senior Personnel Officer.

For the Workmen : Shri S. K. Singh,
Branch Secretary of the Union.

INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal.

Dated, the 2nd April, 1998.

AWARD

By Order No. L-22012/480/94-IR (C. II), dated the 1st June, 1995, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

“Whether the action of the management of Damagoria Colliery in not regularising Shri Madhu Das as line/Track Supervisor w.e.f. 1981 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled to?”

2. The Union's case :—

The concerned workman named Madhu Das has been employed as Line Mistry Category-IV in Damagoria Colliery. But he has been deployed by the management since September, 1981 to discharge the functions of Line/Track Supervisor from 1981 onwards. The post of Line/Track Supervisor is in Technical and Supervisory Grade 'B' level. Because

of such continued deployment since 1981 to discharge responsibilities of the higher level, the workman ought to be regularised in the said level. But the management refused the workman's prayer for such regularisation.

3. The management's case is as follows :—

The workman was initially appointed as Underground Mazdoor in Damagoria Colliery in 1973 and subsequently he was regularised against the post of Line Mistry in Category IV with effect from 1976 and since then he has been working in the said post. At no point of time he was deployed to work as Line/Track Supervisor and as a matter of fact there is absolutely no post having the job nomenclature “Line/Track Supervisor”.

4. The union has totally failed to show with reference to any record that a job having the nomenclature “Line/Track Supervisor” exists. Also on reference to the book-let concerning Nomenclature, Job Description and Categorisation of Coal Employees prepared and finalised by the Standardisation Committee constituted under N.C.W.A.-III, it is found that there is no such nomenclature or job description such as “Line/Track Supervisor”. The book-let reveals that above the level of Line/Mistry Category-IV, comes the post of Line Mistry Category-V, which is of skilled senior level. There is also no material at all to show that the workman was ever deployed to work in any supervisory grade. Therefore the dispute raised by the union must fail.

5. Award :—

The action of the management of Damagoria Colliery in not regularising the workman named Madhu Das as Line/Track Supervisor is justified.

Reference answered accordingly

R. S. MISHRA, Presiding Officer.

सई दिल्ली, 15 मई, 1998

का. आ. 1137 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार एल. आई. सी. ऑफ इंडिया के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (गं. 2) मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-17012/51/96-आई आर (बी-II)]

समानत. ईस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th May, 1998

S.O. 1137.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, (No. 2), Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dis-

pute between the employers in relation to the management of LIC of India and their workman, which was received by the Central Government on 15-5-98.

[No. L-17012/51/96-IR(B-II)]

SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II MUMBAI

PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/26 of 1997

Employers in relation to the management of
Life Insurance Corporation of India

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer : Ms. Naveen Koul, Representative.

For the Workmen : Mr. V. Y. Lotlikar, Mr.
D. S. Agate, Representatives.

Mumbai, dated 6th April, 1998

AWARD-PART-I

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-17012/51/96/IR(B-II), dated 22/23 July, 1997, had referred to the following Industrial Dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of L.I.C. of India in removing Shri Subhash Ghodke, Assistant from service vide order dated 21-10-95 is legal, justified, proper and proportionate to gravity of the guilt? If not, to what relief the said workman is entitled and from which date?"

2. The Aurangabad Divisional Insurance workers Organisation filed a Statement of Claim at Exhibit-6. Shri Subhash Ghodke, the workman was working as a cashier at Ambajogai Branch under the Aurangabad Division of the Corporation. He was served with two chargesheets dated 11-1-92 and 21-2-92. It was alleged by the chargesheet dated 11-1-92 that :

"While working as a cashier in Ambajogai Branch Offices (i). You have fraudulently signed the Renewal Premium Receipt for the quarterly premium of Rs. 409.70ps due on 28-4-91 under Pol. No. N-980416739 of Miss K. B. Kulkarni received in cash by you on 29-5-91, without showing the interest. Further, you have accounted the premium in the cash book on 28-6-91 after over-stamping the date stamp on the counterpart showing the date of Insurance of as 28-6-91 instead of 29-5-91 and the interest of Rs. 6.20. Thus you had misappropriated Rs. 409.70 ps. temporarily.

(2) Under Pol No. 21025948 of Shri B. S. Tapade you had received on 07.06.1991 the yearly premium of Rs. 531.20 due 28-05-1991 in cash. You had deliberately shown to have received it by cheque and entered in the cash book a post dated cheque No. 96624 dated 12-06-1991 drawn on Maharashtra Gramin Bank, which was in fact tendered towards premium due 12-06-1991 under Pol. No. 980402800 of Shri C. S. Kulkarni and had shown part cash payment of Rs. 36.20 as the cheque in question was for Rs. 495 only. Thus you have misappropriated Rs. 531.20ps. subsequently on 28-06-1991 you accounted this amount under Pol. No. 980402800 of Shri C. S. Kulkarni as of received in cash".

3. After receipt of the said chargesheet the workman gave an application to the management containing that he should be supplied with necessary documents, complaints on which basis the chargesheet was issued as that he will be in a position to take proper defence. It is asserted that he was not supplied with these documents till the inquiry was started.

4. The workman pleaded that he gave an application to the Disciplinary Authority that he should be allowed to be represented by a representative Shri Uday Patwardhan from Pune Division as defence representative. It is averred that the request was rejected without any valid reason and he was made to conduct the inquiry on his own. It is submitted that he brought to the notice of the authorities that in that particular region there is no co-worker who is ready to defend him and further capable of defending him. It is averred that the Inquiry Officer himself did not reject the prayer but got direction from the Disciplinary Authority which is improper and illegal. It was submitted that the charge which was levelled against the workman is vague and is not as per the regulation. It is pleaded that no procedure is prescribed in Staff Regulations to conduct the domestic inquiry. For all these reasons it is alleged that the inquiry which was conducted against the workman was against the Principles of Natural Justice. The workman averred that the Inquiry Officer did not consider the evidence before him properly and came to the wrong conclusion. He did not examine the material witnesses. It is submitted that the findings of the Inquiry Officer are perverse.

5. It is averred that on 10-7-91 the workman was suspended. His suspension was revoked after issue of two chargesheets on 9-5-1992. He joined the duties on 14-5-92. It is submitted that in that period he was called for an interview for promotional post and was actually selected in it. The Disciplinary Authority had not taken into consideration all these facts while awarding the punishment. It is submitted that the punishment which is awarded to the workman is disproportionate to the charges proved. For all these reasons it is proved that he may be reinstated in service with full back wages.

6. The Management resisted the claim by the Written Statement (Exhibit-8). It is averred that the Inquiry which was conducted against the workman

was as per the Principles of Natural Justice. He was supplied with all documents on which the management relied before the inquiry was started. It is pleaded that the workman was given an opportunity to bring a co-worker to defend his case. But he did not. He sought time for the same and at last decided to defend the case himself. Looking into the charges levelled against the workman and the Educational qualification of the workman no prejudice is caused to him by defending the case himself. It is submitted that the Inquiry which was conducted against the workman was as per the regulation and as per the Principles of Natural Justice. It is submitted that the findings of the Inquiry Officer are not perverse and are based on the evidence before him.

7. The management averred that the Disciplinary authority considered the Inquiry report and came to the proper conclusion that the charges are proved against the workman. The Appellate authority also considered the evidence and rightly rejected the appeal of the workman. It is submitted that the worker temporarily misappropriated the money. It is therefore, the punishment which was awarded to him is perfectly legal and proper. It is prayed that the reference may be answered accordingly.

8. The workman filed are joined at Exhibit-11 and reiterated the contention taken by him in his statement of claim. He denied the allegations which are against him in the written statement.

9. The issues are at Exhibit-12. Issues Nos. 1 and 2 are treated as preliminary issues. The issues and my findings there on are as follows :

Issues	Findings
1. Whether the domestic inquiry which was held against the workman was against the Principles of Natural Justice?	Yes.
2. Whether the findings of the inquiry officer are perverse?	Yes.

REASONS

10. The charge dated 11-1-92 (Ex-10|2) and the charge dated 21-2-92 (Ex-10|3) are clear in its terms. Actual and Factual position is given in the earlier paragraphs stating how the workman has alleged to have kept the premium amount paid by the Policy holders with him and later on deposited the same with the company. It is further averred that how this act amounts to violation of regulation. The regulations 21.24 read with regulations 39 are specifically mentioned which are alleged to be contravened. After perusal of these charges I do not find any ambiguity in it. On this ground it cannot be said that the inquiry which was conducted against the workman is against the Principles of Natural Justice.

11. Mr. Ghodke (Exhibit-11) affirmed that after receipt of the charge sheet he gave an application dated 5-8-92 to the Inquiry Officer that he should be supplied with documents such as copies of the complaints which were against him in the inquiry. He affirmed by his letter dated 6-2-92 and again my

reminders dated 10-2-92 he asked for relevant documents in respect of those charge sheets but they were not supplied to him, until the inquiry started. It is tried to argue on behalf of the workman that while denying the charges he could not take proper defence because of that. I am not inclined to accept it. After perusal of the chargesheet it can be seen that it is specifically mentioned that are the charges against him. He is to accept it or deny it. Therefore, not supplying documents at earlier stage had not caused any prejudice to the workman. Admittedly, these documents were given to him before the inquiry started.

12. The main and the foremost contention of the workman is that he was not allowed to be represented through a co-worker from Pune Division by name Mr. Uday Patwardhan whose consent was obtained by him and was sent to the Inquiry Officer. The Inquiry Officer asked direction from the Disciplinary Authority whether such a permission is to be given or not? The permission was not given. While arguing the matter no rule is quoted on behalf of the management why such a permission was not given. It is admitted position that workman submitted a letter informing the authority that in their division there is nobody to defend him in that inquiry and he became helpless.

13. It is tried to argue that the workman is well qualified. No doubt, he is well qualified. He is Graduate and a Master in Business Administration. But looking to the charges of misappropriation which are serious in nature it cannot be said that he is in a position to defend himself. It is not the case that the workman himself had helped his colleagues in a domestic inquiry. It is common knowledge that in an inquiry the person who is dealing with his own case is not in a position to defend his case properly. He loses the important aspect of the matter and swayed away by emotions.

14. It is tried to argue on behalf of the management that the Disciplinary Authority of Aurangabad Division was not in a position to give permission to be defended by a co-employee from the other division because leave of that representative and other things could not be controlled by him. It might be correct. But in that case the Disciplinary Authority or the Inquiry Officer who have informed the workman that the co-worker from any other division cannot be made available to represent his case and in that case he may engage an Advocate. That would have been a proper way. The Principle of Natural Justice demands that he should have an opportunity to defend himself properly. Here, in this case the circumstances compelled the workman to defend the case personally and proceed with the matter that has caused prejudice to him.

15. It is tried to argue on behalf of the management that the charges are not complicated or serious one. I am not inclined to accept this. The charge of misappropriation of money is a serious charge. That goes to show that it is a complicated one and for that an expert is required. Mr. Patwardhan appears to be an employee of the Corporation who helps the employees against whom the domestic inquiries are initiated. He is an experienced man. It is therefore,

the worker wanted him to engage him in his case. His demand was reasonable. I repeat if the rules do not permit on the basis of sanction of casual leave or other conditions, in that case permission should have been given to the workman to engage an advocate to defend him. As that is not done, the inquiry which was conducted against the workman is against the Principles of Natural Justice.

16. It is tried to argue that there is no procedure in the rules of the Corporation how the domestic inquiry is to be conducted. I have nothing to say about it. I have to see that whether the Principles of the Natural Justice are followed or not.

17. As I have come to the conclusion that the inquiry was against the Principles of Natural Justice, Naturally evidence which was before the inquiry officer cannot be said to be a proper evidence. His findings on that evidence are perverse one. Under such circumstances I record my findings accordingly and pass the following order :

ORDER

- (1) The inquiry which was conducted against the workman was against the Principles of Natural Justice.
- (2) The findings of the Inquiry officer are perverse.

S. B. FANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 18 मई, 1998

कांआ० 1138.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[स. एल-12012/422/87-डी 2 (ए)/आईआर (बी-II)]
सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th May, 1998

S.O. 1138.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 15-5-1998.

[No. L-12012/422/87-D.II (A)/IR (B-II)]
SANATAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर।

केस नं सी आई टी 44/91

केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली
की अधिसूचना सं. एल-12012/422/87-डी 2 ए दिनांक

24-6-91

राजेन्द्र सिंह पुत्र सर. अमर सिंह, 18 डी ब्लॉक, श्री गंगानगर
... प्रार्थी

बनाम

प्रबंधक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा
श्री गंगा नगर।

अप्रार्थी

उपस्थिति

पीठासीन अधिकारी : श्री एस. के. बंसल, आर. एच. के. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जे. एल. शाह

अप्रार्थी की ओर से : श्री पी. एल. अग्रवाल

अवाई दिनांक : 29-10-97

अवाई

1. यह अधिसूचना केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इस न्यायालय को निर्णय के लिए भेजी गई है। जो कि निम्नलिखित है :—

“Whether the action of the management of Central Bank of India, Sriganaganagar Branch, is justified in not continuing the services of the workman (Sh. Rajinder Singh) w.c.f. 28-2-1974? If not, to what relief the workman is entitled and from what date?”

2. प्रार्थी ने सट्टेमेंट आफ क्लेम पेश किया और उसका कथन है कि उसकी विपक्षी बैंक में 4-9-72 को क्लर्क के पद पर नियुक्ति हुई थी और वह बैंक में रोजाना चलने वाला काम करता था। प्रार्थी का यह भी कथन है कि उसको क्लर्क के पद का पूरा वेतन बेसिक 190/- रु. महंगाई भत्ता व अन्य सुविधाएं दी जाती थी प्रार्थी का यह भी प्रार्थना पत्र है कि उसकी सेवाएं 28-2-74 को मौखिक आदेश द्वारा समाप्त कर दी गई। प्रार्थी का यह भी कथन है कि विपक्षी ने उसकी सेवाएं लगातार न होने देने में उद्देश्य से उसकी सेवा में बीच-बीच में ब्रेक दिया। प्रार्थी का यह भी कथन है कि सेवा मुक्ति के बाद वह बैंक में उपस्थित होता रहा व सेवा में लेने की मांग करना रहना और उसे मार्च 74 में 6 दिन, अगस्त 74 में, एक दिन व दिसम्बर 74 में 2 दिन कार्य पर रखा गया और सेवा पुनर्कर दिया। इसके बाद भी प्रार्थी समय-समय पर विपक्षी बैंक में उपस्थित होकर सेवा में बहाल करने की मांग करता रहा लेकिन उसे सेवा में नहीं लिया गया।

3. प्रार्थी का यह भी क्लेम है कि उसकी सेवा मुक्ति के बाद विपक्षी बैंक में विनोद कुमार भल्ला, जोगन्द्र नाथ कौशिक, जसमेर सिंह भाटिया, दिलबाग राज भाटिया आदि कई कर्मचारियों को क्लर्क के पद पर स्थायी व अस्थायी तौर पर नियुक्ति दी गई है। लेकिन प्रार्थी द्वारा लगातार मांग करने के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं दी गई। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र है कि उसने विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष उठाया परन्तु समझौता नहीं हो सका इसलिये यह अधिसूचना न्यायालय के समक्ष पेश हुई है। प्रार्थी का यह भी प्रार्थना पत्र है कि उसकी सेवाएं धारा 25(जी) औद्योगिक विवाद

अधिनियम (जो बाद में अधिनियम कहलायेगा की उल्लंघना में धारा 25(एच) अधिनियम के प्रावधानों की उल्लंघना में समाप्त की गई है और सेवा मुक्ति बदनियति पूर्वक एवं न्याय में नैसर्गिक मित्रांतों के खिलाफ है। प्रार्थी का यह भी प्रार्थना पत्र है कि उसने अपनी सेवा अवधि में 240 दिन से अधिक कार्य किया है परन्तु सेवा मुक्त करने से पूर्व एक माह का नोटिस अथवा उसकी एज में एक माह का वेतन नहीं दिया गया। इसलिये सेवा मुक्ति अवैध व अनुचित है इसलिए प्रार्थी को पूरे वेतन एवं सुविधाओं सहित सेवा में बहाल किया जाए।

4. विपक्षी ने जवाब पेश किया और उसका अभिकथन है कि प्रार्थी की नियुक्ति बैंक ने रिक्त स्थान पर स्थायी कार्य पर 4-9-72 को नहीं हुई परन्तु उसकी नियुक्ति निश्चित अवधि के लिये की गई थी जो निश्चित अवधि के समाप्त होते ही समाप्त हो गई। अप्रार्थी का यह भी अभिकथन है कि प्रार्थी को अस्थायी कर्मचारी के रूप में रखा गया था। और निश्चित अवधि की नियुक्ति होने से समय समाप्त होने से सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई। विपक्षी का यह भी अभिकथन है कि उसकी सेवाओं में ब्रेक सेवा लगातार न होने के लिए नहीं दिया जाता था और प्रार्थी ने 1972 में 66 दिन, 1973 में 88 दिन व 1974 में 62 दिन कार्य किया और 20 वर्ष बाद यह विवाद उठाया है इसलिए क्लेम खारिज किया जाए। विपक्षी का यह भी अभिकथन है कि नव वर्ष 1972, 1973, 1974 में प्रार्थी साँ कालेज गंगानगर का एक नियमित छात्र था अपनी शिक्षा के दौरान व खाली समय में कुछ धनोपार्जन के लिए ही बैंक में अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए आता था और बैंक में कार्य की अधिकता होने पर उसे पूर्ण अस्थायी तौर पर एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति दी जाती थी। विपक्षी का यह भी अभिकथन है कि प्रार्थी ने अपनी विधि की अंतिम परीक्षा 1975 में उत्तीर्ण करने के बाद अपना पंजीयन बार काउंसिल आफ राजस्थान जोधपुर में बतौर एडवोकेट करवा दिया है। और गंगानगर में दिनांक 4-1-76 को बार एंजो-सिएशन श्रीगंगानगर का सदस्य होकर वकालत आरंभ कर दी थी और इस कारण वह स्वयं ही बैंक में अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने का इच्छुक नहीं रहा। इतना ही नहीं वर्ष 1985 में प्रार्थी ने विपक्षी बैंक में अभिभावक के तौर पर विपक्षी के ऋणियों को विधिक नोटिस भी जारी किये जिसके लिए समुचित महतताना विपक्षी बैंक द्वारा प्रार्थी को भुदा किया गया। और उसका कार्य संतोसजनक न होने के कारण विपक्षी बैंक ने प्रार्थी को कार्य देने से इंकार कर दिया। जिससे नाराज होकर प्रार्थी ने 20 वर्ष बाद यह विवाद उठाया है। इसलिये क्लेम खारिज किया जावे। विपक्षी का यह भी अभिकथन है कि प्रार्थी ने किसी भी वर्ष 240 दिन से अधिक कार्य नहीं किया। इसलिये प्रार्थी का क्लेम हर्जा-खर्चा सहित खारिज किया जाए।

5. प्रार्थी राजेन्द्र सिंह ने अपना क्लेम साबित करने के लिए अपना शपथ पत्र पेश किया है। व दस्तावेज पेश किया है।

विपक्षी के इसके खंडन में रामचरण, सविता के बयान करवाये हैं।

6. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री जयन्ती लाल साह का तर्क है कि प्रार्थी राजेन्द्र सिंह ने विपक्षी बैंक में 4-9-72 से 28-2-74 तक 257 दिन कार्य किया है। और उसे एक वर्ष में 240 दिन पूरा न करने देने के लिए बीच-बीच में हटाया गया है। जबकि काम स्थायी प्रकृति का था और प्रार्थी को रिक्त पद के विपरीत लगाया गया था इस प्रकार प्रार्थी का बार-बार हटाना अनुचित श्रम व्यवहार का द्योतक है प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि का यह भी तर्क है कि विपक्षी के पास कार्य था इसलिये उसने विनोद कुमार भल्ला, जसबीर सिंह भाटिया, जोगेन्द्र नाथ कौशिक, दिलबाग राज भाटिया व कई कर्मचारियों को इस दौरान कार्य पर रखा और क्लर्क के पद पर स्थायी व अस्थायी नियुक्ति दी। इसलिये प्रार्थी को बीच-बीच में हटाना अनुचित श्रम व्यवहार का द्योतक है। यह भी तर्क है कि 2(ओ ओ) (बीबी) अधिनियम के प्रावधान इसमें लागू नहीं होते क्योंकि यह प्रावधान बाद में आया है और सेवा मुक्ति 2(ओ ओ) अधिनियम की परिभाषा में आती है। इसलिए सेवा मुक्ति को अनुचित व अवैध घोषित की जाये। प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने इस तर्क के समर्थन में

1976 (33) Hindustan Steel Ltd. v. State of Orissa (S.C.) 257 Supreme Court, Writ Petition (5) Civil No. (S) 532 of 1987 Smt. Santosh Kumari & Ors. v/s Sts of Punjab & Ors. date 2-5-1988, Supreme Court, 1987 II LLNP. 685 Dinesh Kumar Himatlal Nimavat and State of Gujarat and another. High Court, of Gujarat, AIR 1986 Supreme Court 132 1985 Lab. I. C. 1733, R. D. Singh. Appellant V. Reserve Bank of India and others Respondents, AIR 1993 Supreme Court 802 M/s. Dehri Rohats Light Railway Company Limited. Appellant v. District Board. Bhojpur and others. Respondents.

पेश किया है।

8. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि का जवाब में तर्क है कि इस प्रार्थी ने 240 दिन काम नहीं किया और यह विवाद 10-11 वर्ष बाद 1985 के नोटिस के जरिए उठाया था और वह इस अर्से में चुपचाप रहा इसलिए इस देरी के कारण प्रार्थी को पुनः सेवा में लिये जाने पर पिछले वेतन पाने का अधिकारी नहीं। इसलिए क्लेम खारिज किया जाए। विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि ने इस तर्क के समर्थन में पंजाब हरियाणा 1996 (3) उच्च न्यायालय LLM Page 31 हंसराज बनाम सैन्ट्रल कोपरेटिव लि० वगैरह को व 1996(3) एलएलएम पेज 84 पंजाब उच्च न्यायालय बलवन्त सिंह बनाम श्रम न्यायालय भटिंडा वगैरह को पेश किया है।

9. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री जयन्ती लाल साह का जवाब में कहना है कि प्रार्थी ने विपक्षी को 76-77-78-79 में व 85 में सेवा में लिये जाने के नोटिस दिये हैं। जिससे स्पष्ट है कि वह अपनी सेवा में लिये जाने के

अधिकार की मांग कर रहा था। इसलिए वह चुपचाप नहीं बैठा और इस देरी के आधार पर प्रकरण को फेंका नहीं जाना चाहिए। और विपक्षी द्वारा जो निर्णय पेश किए गये हैं वह इसमें लागू नहीं होते और दादरसी की जाय।

10. मेरे विचार में विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि के तर्क में कोई सार प्रतीत नहीं होता। राजेन्द्र सिंह के शपथ पत्र के पैरा नं० 5 में कथन है कि उसने 22-1-76, 13-8-77, 4-2-78, 24-1-79 व दिनांक 28-11-85 को जनरल मैनेजर सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया बम्बई को पत्र लिखकर सेवा में बहाल करने की मांग की थी। यह पत्र क्रमशः Ex-12 से 16 है। बैंक ने इन पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया।

11. मेरे विचार में प्रार्थी के इस कथन को न मानने का कारण कोई नहीं है इसके विपक्षी के साक्ष्य रामचरण सबिता का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि Ex-12 से Ex-15 तक के पत्र राजेन्द्र सिंह ने बैंक को भेजे थे। विपक्षी ने जवाब के पैरा नं० 7 में स्वीकार किया है कि 28-11-85 को विपक्षी बैंक को प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के जरिए निवेदन किया था? इस प्रकार पक्षकारान की साक्ष्य से यह साबित होता है कि प्रार्थी सेवा मुक्ति के पश्चात् विपक्षी को सेवा में लिये जाने के लिए 76, 77, 78, 79 व 85 में प्रार्थना पत्र दे रहा था और दिए है। इस प्रकार प्रार्थी Ex-12 से 16 पत्रों के जरिए विपक्षी बैंक से बराबर इस बात की मांग कर रहा था कि उसे सेवा में लिया जाये। इस प्रकार विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि का यह तर्क कि विवाद 10-11 वर्ष बाद उठाया है और इस अर्से में प्रार्थी चुप रहा नहीं माना जा सकता। इस प्रकार प्रार्थी चुपचाप नहीं रहा परन्तु बैंक से सेवा में लिये जाने की मांग करता रहा। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी ने देरी से विवाद उठाया है। और इस आधार पर दादरसी से इंकार नहीं किया जा सकता 1996 (3) एल एल एम पेज 31 पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय में हसराम बनाम सैन्ट्रल कोपरेटिव लि. बगैरह में माननीय न्यायाधिपतियों ने 8 साल देरी के कारण दादरसी नहीं दी। इसी प्रकार 1996 (3) एल एल एम पेज 84 पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय, बलवन्त सिंह बनाम लेबर कोर्ट भंडिडा में विवाद पांच वर्ष बाद उठाया गया था इसलिये दादरसी नहीं दी गई परन्तु इस प्रकरण में ऐसे तथ्य नहीं है। इसलिये ये निर्णय तथ्यों के आधार पर विपक्षी को कोई मदद नहीं करते।

12. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि अग्रवाल का जवाब में कहना है कि इस प्रकरण में प्रार्थी को आवश्यकतानुसार काम दिया गया है। और उसने 240 दिन पूरे नहीं किये और धारा 25 (एच) अधिनियम का विवाद न्यायालय को प्रेषित नहीं किया गया और न ही अनुचित व्यवहार न्यायालय को प्रेषित नहीं किया गया इसलिये प्रार्थी का कोई प्रकरण साबित नहीं होता और प्रार्थी कोई दाद-

रसी पाने का अधिकारी नहीं। विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि ने इस तर्क के समर्थन में II एल एल जे 1994 पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय करनाल सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि. बनाम प्रजाइडिंग आफिसर औद्योगिक न्यायाधिकरण कम लेबर कोर्ट रोहतक बगैरह, 1981, II एल एल जे सुप्रीम कोर्ट फायर स्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इंडिया प्रा. लि. बनाम वर्कमैन पेज 218 व जे टी 1997 (4) सुप्रीम कोर्ट पेज 560 हिमांशु कुमार विद्यार्थी बनाम बगैरह राज्य सरकार बगैरह को पेश किया है।

13. मेरे विचार में विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि के तर्क में कोई सार प्रतीत नहीं होता। प्रथम तो यह विपक्षी की साक्ष्य रामचरण सबिता का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि उसने सैन्ट्रल बैंक की गंगानगर शाखा में काम नहीं किया। यह सही है कि राजेन्द्र सिंह ने गंगानगर शाखा में अस्थायी क्लर्क के तौर पर कार्य किया है। इसको राजेन्द्र सिंह के काम की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। अस्थायी कर्मचारियों की हाजिरी उपस्थिति रजिस्टर में होती है। इस प्रकार विपक्षी का साक्ष्य रामचरण सबिता संबंधित समय में संबंधित गंगानगर शाखा में कार्यरत नहीं था। इसलिये विपक्षी के साक्ष्य में कथनों से प्रार्थी के शपथ पत्र का खंडन नहीं होता। दूसरे विपक्षी की ओर से कोई उपस्थिति रजिस्टर पेश नहीं किया गया इसलिये भी प्रार्थी के साक्ष्य का खंडन नहीं होता। इसलिये प्रार्थी का शपथ पत्र अखंडित रह जाता है। अतः प्रार्थी राजेन्द्र सिंह के शपथ पत्र से यह साबित होता है कि उनको बैंक में 4-9-72 को नियुक्ति दी गई थी और वह जो कार्य करता था वह स्थायी था और उसने बैंक में 28-2-74 तक कार्य किया और कि उसे बीच-बीच में ब्रेक दिये जाते थे और नया कर्मचारी रख लेते थे और उसके पश्चात् विनोद कुमार भल्ला, जोगेश्वर नाथ कौशिक, जसबीर सिंह भाटिया, दिलबाग राज भाटिया व कई कर्मचारियों को स्थाई व अस्थायी नियुक्ति दी गई। इस प्रकार यह साबित होता है कि प्रार्थी को इसलिये ब्रेक दिये गये कि वह 240 दिन पूरे नहीं कर सके और नये कर्मचारी रखे गये। दूसरे प्रार्थी की सेवा मुक्ति के पश्चात् भी स्थायी कार्य होते हुए भी विनोद कुमार भल्ला, योगेश्वर नाथ कौशिक, जसबीर सिंह भाटिया, दिलबाग राज भाटिया को सेवा में रखा गया। इससे भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को 240 दिन पूरे न कर लेने के कारण हटाया गया जबकि अप्रार्थी के पास कार्य का जो यह दर्शाता है कि प्रार्थी को 240 दिन पूरे न करने के कारण अनुचित पत्र व्यवहार से सेवा से मुक्त किया गया। इसलिये प्रार्थी 4-9-72 से 28-2-74 तक बैंक में सेवा करने के कारण और उसे बैंक द्वारा अनुचित पत्र व्यवहार के कारण हटाने से पुनः सेवा में लिये जाने योग्य है। क्योंकि उसकी सेवा मुक्ति अनुचित व अवैध है। मेरे इस विचार का समर्थन एल एल एम 1987 II गुजरात उच्च न्यायालय पेज 685

दिनेश कुमार हिस्मतलाला बनाम राज्य सरकार गुजरात से होता है जिसमें माननीय न्यायाधिपति ने निम्नलिखित विनिश्चय किया है :—

Work charge employees artificial breaks in service.—Held is illegal, unfair unjust and oppressive—clear pronouncements of Court, in this regard should not be ignored by bureaucrats.—Practice by state of employing Person for 28 or 29 days every month by a separate order is without authority of law and unfair practice and should not be resorted to;

14. मैं इस विचार का समर्थन ए आई आर 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 132 एच० डी० सिंह बनाम रिजर्व बैंक बंगौरह से होता है जिससे माननीय न्यायाधिपति ने निम्नलिखित विनिश्चय किया है :—

Industrial Dispute Act (14 of 1947) S. 2 (2a), Sch. 5. Item 10—Unfair labour practice—Confidential circular of Reserve Bank directing officers by confidential circular that Tikka Mazdoors, Persons, helping examiners of notes/coins, shall not be engaged continuously but offered work on rotation basis and characterising Mazdoors as Badli Workers—Direction amounts to unfair labour practice.

15. II एल एल जे 1994 पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय पेज 1005 कनति सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक बनाम पी० ओ० औद्योगिक न्यायाधिकरण रोहतक बंगौरह में अनुचित श्रम व्यवहार का कोई मामला नहीं था इसी प्रकार जे० टी० 1997 (4) सुप्रीम कोर्ट पेज 560 में भी अनुचित श्रम व्यवहार का और मामला नहीं था। 1981 सुप्रीम कोर्ट II एल एल जे पेज 218 में माननीय न्यायाधियों ने तथ्यों के आधार पर यह विनिश्चय किया कि बाद में कुछ कर्मचारियों को सेवा में स्थायी तौर पर लिये जाने को अनुचित श्रम व्यवहार नहीं कहा जा सकता। इन तीनों निर्णयों में जो सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं में कोई विवाद नहीं परन्तु यह निर्णय तथ्यों के आधार पर विपक्षी को यह कोई मदद नहीं करते क्योंकि कि प्रार्थी यह साबित करने में समर्थ रहा है कि उसे अनुचित श्रम व्यवहार के कारण हटाया गया है। अतः अनुचित श्रम व्यवहार का मामला अधिसूचना से प्रकट होता है इसलिये अनुचित श्रम व्यवहार का मामला स्पष्ट तौर पर प्रेषित न करने से इस आधार पर प्रार्थी को वापसी से इंकार नहीं किया जा सकता है दूसरे प्रार्थी अपने क्लेश में व शपथ पत्र में अनुचित श्रम व्यवहार के तथ्यों को लेकर आता है इसलिये भी इस आधार पर निर्णय किया जा सकता है। अतः सेवा मुक्ति अनुचित व अवैध है और प्रार्थी पुनः सेवा में लिये जाने योग्य है।

16. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री जयन्ती लाल शाह का तर्क है कि प्रार्थी सेवा मुक्ति के पश्चात् किसी लाभप्रद नियोजन में नहीं रहा इसलिये उसको सेवा समाप्ति से आज तक पूरा वेतन लाभ परिलाभ सहित दिलवाया जाए। प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि की यह भी तर्क है

कि अधिक से अधिक प्रार्थी जो अपने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गंगा-राम जी से जो 1980 से 400-500/- रुपये माहवार लेता था उसको कम कर दिया जाये। प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने इस तर्क के समर्थन में 1991 (लेबर आई० सी० पेज 1414

Om Prakash Goel, Petitioner v. The Himachal Pradesh Tourism Development Corporation Ltd. Shimla and another Respondents, 9 1984 Lab. I-01446

सुप्रीम कोर्ट व 1984 लेबर I 1446 सुप्रीम कोर्ट एस० एम० सयैद, प्रार्थी बनाम बड़ौदा म्यूनिसीपल कारपोरेशन रेस्पोंडेंट को पेश किया है।

17. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि का जवाब में कहना है कि प्रार्थी 4-1-76 से वकालत का धन्धा करता है और उसमें 1985 में बैंक का भी विधिक कार्य किया और वह श्री गंगा राम से 400/- — 500/- रुपये माहवार लेता था इसलिये प्रार्थी को पिछला वेतन नहीं दिलवाया जाना चाहिए।

18. मेरे विचार में विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि के तर्क में कोई सार प्रतीत नहीं होता। एक अधिवक्ता एक क्लर्क के पद पर आना चाहता है जिससे स्पष्ट है कि वह वकालत में अपना गुजारा नहीं कर रहा और ठीक ढंग से कमा नहीं रहा। दूसरे केवल अधिवक्ता होने से प्रार्थी को पिछले वेतन से इंकार नहीं किया जा सकता। 1991 लेबर आई० सी० 1414 सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायाधियों ने निम्नलिखित विनिश्चय किया है।

Industrial Disputes Act (14 of 1947), Sch. 2, Item 3, 6. Basic wages—Gainful employment.—Employee practising as lawyer ever since his termination. No ground to refuse him backwages upto date of his enrolment as, lawyer. Backwages for a period from date of enrolment to date of reinstatement granted at rate of half the subsistence allowance with deduction of amount earned by him as lawyer.

19. 1984 लेबर आई० सी० पेज 1446 एस० एस० सयैद बनाम म्यूनिसीपल कारपोरेशन में माननीय न्यायाधियों ने निम्नलिखित विनिश्चय किया है :—

An dismissal order being found to be invalid and the direction for reinstatement having been given the workmen would be entitled to full Back wages, unless the same can be denied on some relevant grounds. The Denial of Back Wages for a portion of period for the reason that he was prosecuting remedy in a wrong forum would not be a relevant consideration for refusal of back wages. Further the employee would be entitled to deduct the amount which the employee was earning during the period he was under suspension from back wages payable to him S/C.A. No. 2223 of 1980 Dt. 3-10-80)Gugi Reversed).

रामचरण, सविता के शपथ पत्र से यह साबित होता है कि प्रार्थी ने अपना नाम अधिवक्ता के रूप में 4-1-76 को पंजीयन करवाया। राजेन्द्र सिंह के शपथ पत्र से यह साबित होता है कि उसने 1976 में सनत लेने के पश्चात् श्री गंगा राम से कार्य सीखना शुरू किया और वह 1990 तक श्री गंगाराम का जूनियर रहा और शुरू के तीन चार वर्षों के बाद उन्होंने उसे 400-500/- रुपये माहवार खर्चा दिया। इस प्रकार राजेन्द्र सिंह के शपथ पत्र के अनुसार उसको 79 से श्री गंगा राम 400-500/- रुपये महीना खर्चा देना शुरू किया। इस प्रकार प्रार्थी 1-1-75 से 31-12-78 तक पिछला पूरा वेतन व उसके पश्चात् 1979 से आज तक आधा वेतन जो कि यह सेवा में रहता, प्राप्त करता वह उसमें 500/- रुपये माहवार कटौती के बाद उपरोक्त निर्णय में प्रति पाबित सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा। बैंक में कितने रुपये का कार्य किया यह साक्ष्य में नहीं आया इसलिए इस आधार पर उपरोक्त पिछले वेतन से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी को सेवा मुक्ति अनुचित व अवैध होने से पुनः सेवा में लिये जाने का अधिकारी और उपरोक्त प्रकार से पिछला वेतन पाने का अधिकारी है।

अर्वाड

20. अतः विपक्षी व्यवस्थापक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया शाखा गंगानगर द्वारा प्रार्थी राजेन्द्र सिंह की सेवा 28-2-74 से जारी न रखना अनुचित व अवैध है इसलिये प्रार्थी पुनः सेवा में लिये जाने का अधिकारी है। प्रार्थी 1-1-75 से 31-12-78 तक पिछला पूरा वेतन पाने का अधिकारी होगा प्रार्थी जनवरी 79 से आज तक आधा वेतन जो वह सेवा में रहता, प्राप्त करने का अधिकारी होगा। परन्तु बैंक को इस आधे वेतन में 500/- रुपये माहवार काटने का अधिकार होगा और उसके पश्चात् वेतन देगा यह अर्वाड केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

21. यह अर्वाड खुले न्यायालय में आज दिनांक 29-10-97 को सुनाया गया।

एस० के० बंसल, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 18 मई, 1998

का०आ० 1139.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-12012/539/87-डी-III (ए) आर्द आर (बी-II)]
सनातन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th May, 1998

S.O. 1139.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government

hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Punjab and Sind Bank and their workman, which was received by the Central Government on 15-5-1998.

[No. L-12012/539/87-D.III (A)/IR (B-II)]
SANATAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर
केस नं. सी.आई.टी. 37/88

रेफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का
आदेश क्रमांक एल. 12012/539/87-डी-
2(ए) दिनांक 27-5-88

श्री किशन सिंह, 117, पो. उदयपुर, डी. कालांती, जोधपुर
--प्रार्थी

बनाम

प्रबंधक, पंजाब एंड सिंध बैंक लि. ब्रान्च चौपासनी
रोड, जोधपुर --प्र प्रार्थी

उपस्थित

चीठासीन अधिकारी : श्री एस. के. बंसल, आर.एच.
जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री प्रदीप सिंह शखावत
अप्रार्थी की ओर से : श्री पी. एस. रत्नू
दिनांक अर्वाड : 18-10-97

अर्वाड

इस प्रकरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना निर्णय के लिये प्रेषित की गई है :
“क्या पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंधन को जोधपुर ब्रान्च में श्री किशन सिंह सब स्टाफ को 1.4.84 से सेवायें समाप्त करने और इसके पश्चात् उन्हें विभिन्न अवधियों के लिये कल्पित नामों से कार्य करने देने तथा 1-5-86 से अंतिम रूप से उसकी सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?”

2. प्रार्थी ने स्टेटमेंट आफ क्लेम पेश किया और उसका कथन है कि उसको विपक्षी बैंक के यहाँ 6.9.82 को जपरामी के पद पर नियुक्त किया गया और उसने विपक्षी के यहाँ 6-9-82 से 30-4-86 तक कार्य किया और नौकरी के दौरान विपक्षी ने धनराज, भीमसिंह हुकमसिंह नामक व्यक्तियों के नाम लिखकर 1985 व, 1986 में वेतन दिया जबकि वास्तविक काम उसने किया था। प्रार्थी का यह भी कथन है कि उसको मौखिक कथन से 28-3-84 को नौकरी से पृथक कर दिया था जबकि वह कार्य करता रहा और स्थान करने की बजाय 30-4-86 को अकारण बिना किसी नोटिस, जांच किय, बिना छुट्टी का मुआवजा दिये उसे नौकरी से पृथक कर दिया इसलिये सेवा समाप्ति अवैध है। प्रार्थी का

यह भी कथन है कि उसकी वरिष्ठता को नजरअन्दाज करने हुए विपक्षी ने उसको हटाकर कनिष्ठ कर्मचारियों को नौकरी पर रखा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	नाम	पद	तारीख नियुक्तिगत	रिमार्क
1	मुरली	चपरासी	अप्रैल, 1984	प्रार्थी से जूनियर
2.	प्रताप सिंह	चपरासी	वर्ष 1986	ट्रांसफर होकर रिक्त पद पर जोधपुर आया है।
3.	मनमोहन सिंह	चपरासी	मई 1988	दैनिक बेजेज पर काम करता है।

अतः प्रार्थी का कथन है कि उसकी सेवा समाप्ति अवैध है और उसे मवेतन सेवा लिया जाये।

3. विपक्षी ने जवाब पेश किया और उनका कथन है कि रैफरेंस में यह निश्चित रूप से स्वतः ही निर्धारित कर दिया है कि प्रबन्धक पंशाब व सिंध बैंक ने विभिन्न काल्पनिक नामों से काम करने दिया गया है जब कि बैंक ने ऐसा कभी नहीं किया। इस प्रकार यह बिन्दु एक विवादित विषय है कि क्या किशन सिंह ने विभिन्न काल्पनिक नामों से कार्य किया और प्रबन्धक ने ऐसा करने दिया और इस प्रकार यह विवादित बिन्दु रैफर होना चाहिये था इसलिये रैफरेंस त्रुटिपूर्ण है और चलने योग्य नहीं है। यह भी अभिकथन है कि किशन सिंह ने काल्पनिक नामों से काम नहीं किया परन्तु जिसने काम किया उसी को वेतन दिया गया। विपक्षी का यह भी अभिकथन है कि प्रार्थी के कार्य को जब आवश्यकता होती थी तो वह स्वयं ही कार्य करता था इसलिए प्रार्थी की छंटनी धारा 2(००) (बीबी) अधिनियम के अन्तर्गत छंटनी की परिभाषा में नहीं आती और वह कोई दादरसी पाने का अधिकारी नहीं है। विपक्षी का यह भी कथन है प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप गलत है और मुरली तथा प्रताप सिंह स्थाई कर्मचारी हैं, उनका चयन प्रोपर चैनल से हुआ है जिसे प्रार्थी तुलना नहीं कर सकता। प्रताप सिंह स्थाई चपरासी के छुट्टी पर चले जाने से मनमोहन सिंह को रखा था इसलिये प्रार्थी का कोई क्लेम नहीं बनता और क्लेम खारिज किया जाये।

4. प्रार्थी ने अपना क्लेम साबित करने के लिये अपना, श्री धनराज व श्री हुकम सिंह के शपथपत्र पेश किये हैं व प्रदर्श डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-10 दस्तावेज पेश किये हैं। इसके खण्डन में विपक्षी की ओर से सर्वश्री सुखदेव सिंह व प्रितपाल सिंह के शपथपत्र पेश हुए हैं व प्रार्थी द्वारा तलब किये जाने पर बैंक की ओर से प्रदर्श एम-1 से एम-5 दस्तावेज पेश किये गये हैं। बहस सुनी गई, पक्षावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री प्रदीप सिंह का तर्क है कि प्रार्थी ने 1982 से 1986 तक विपक्षी के यहां कार्य किया है और 1985-86 में उससे कार्य तो लिया गया परन्तु उसे वेतन भीम सिंह व हुकम सिंह व श्री धनराज के नामों से दिया गया इसलिये अप्रार्थी द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार अपनाया गया है इसलिये 1-4-84 व 1-5-86 को समाप्त करना अवैध है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी ने 1-1-84 से 31-12-84 तक 240 दिन से अधिक कार्य किया है क्योंकि विपक्षी स्वयं मानता है कि उसने 226 दिन कार्य किया जो कि विपक्षी की ओर से स्टेटमेंट पेश किया गया है और डब्ल्यू-10 मार्च 1984 का इसमें कोई वर्णन नहीं है जिसमें प्रार्थी ने 31 दिन कार्य किया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा विपक्षी से पेश करवाये गये स्टेटमेंट व डब्ल्यू-10 के अनुसार वर्ष 1984 में उसने 257 दिन कार्य किया। परन्तु सेवा मुक्ति के समय उसे कोई छंटनी का मुआवजा या एक माह का वेतन अथवा वेतन नोटिस नहीं दिया गया इसलिये प्रार्थी पुनः सेवा में लिये जाने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि कनिष्ठ कर्मचारी मुरली व मनमोहन सिंह को सेवा में रखा है इसलिये धारा 25-4 जी की उल्लंघना में सेवा समाप्त की गई है इसलिये वह पुनः सेवा में लिये जाने योग्य है।

6. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि श्री बी.एस. रत्न का जवाब में कहना है कि हुकम सिंह व धनराज के कथनों से ऐसा कहीं साबित नहीं होता कि उन्होंने कार्य नहीं किया और उनके नाम से प्रार्थी को वेतन दिया गया इसलिये यह साबित नहीं होता कि प्रार्थी ने काल्पनिक नामों से कार्य किया। जवाब में यह भी उनका तर्क है कि मुरली व प्रताप सिंह स्थाई कर्मचारी हैं और प्रताप सिंह के छुट्टी पर चले जाने के कारण मनमोहन सिंह ने भी कार्य किया जिसकी सेवायें समाप्त की जा चुकी हैं इसलिये धारा 25-जी अधिनियम की उल्लंघना साबित नहीं होती और क्लेम खारिज किया जाये। श्री रत्न का यह भी तर्क है कि प्रार्थी ने 1982 में 63 दिन 1983 में 121 दिन व 1984 में 1-4-84 तक 43 दिन व 31-12-84 तक कुल 226 दिन कार्य किया है और किसी भी वर्ष 240 दिन कार्य नहीं किया इसलिये प्रार्थी कोई नोटिस, नोटिस पे अथवा छंटनी का मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं है इसलिये सेवा मुक्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जो बाद में अधिनियम कहलायेगा) के प्रावधानों के अन्तर्गत सही की गई है अतः क्लेम खारिज किया जाये।

7. मेरे विचार में प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि के इस तर्क में कि प्रार्थी ने 240 दिन से अधिक 1984 में कार्य किया है, में काफी सार प्रतीत होता है। प्रार्थी किशन सिंह का शपथपत्र के पैरा नं. 2 में कथन है कि :

2. प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा दिनांक 28-3-84 को मौखिक रूप से हटाने के बावजूद भी दिनांक 29-3-84 (माह मार्च 1984) से दिनांक 31-13-84 (माह

दिसम्बर 1984) तक अप्रार्थी प्रार्थी से नौकरी करता रहा। इस प्रकार प्रार्थी की सविनय में किसी प्रकार का ब्रेक नहीं हुआ और नौकरी निरन्तर चालू रही।

8. विपक्षी की ओर से जो आज विपक्षी का स्टेटमेंट पेश किया गया है उसमें विपक्षी के अनुसार प्रार्थी ने 18-1-84 से 31-12-84 तक 226 दिन कार्य किया। प्रार्थी के शपथपत्र से यह भी साबित होता है कि उसने क्लेम के साथ क्रमांक 13 से 22 दस्तावेज की 4 प्रतियां पेश की हैं जिनको विपक्षी के साक्षी-गण ने कहीं चुनौती नहीं दी है कि ये गलत हैं। प्रदर्श डब्ल्यू-10 मार्च 1984 को किशन सिंह की उपस्थिति है इस प्रकार मार्च 1984 में किशन सिंह ने 31 दिन कार्य किया और जो आज स्टेटमेंट पेश किया गया है उसमें मार्च 1984 में कोई उपस्थिति नहीं बताई गई है। इस प्रकार विपक्षी के आज के स्टेटमेंट जिसमें 18-1-84 से 31-12-84 तक 226 दिन कार्य करना बताया गया व डब्ल्यू-10 क्रमांक 22 के अनुसार प्रार्थी ने 31 दिन कार्य किया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा 18-1-84 से 31-12-84 तक 257 दिन कार्य करना साबित होता है। इसका खण्डन अप्रार्थी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों या उनकी मौखिक साक्ष्य से नहीं होता। अतः प्रार्थी द्वारा 240 दिन से अधिक 1984 में कार्य किया गया है। प्रार्थी से 1982-83 में भी कार्य लिया गया है और 1985-86 में भी कार्य लिया गया है इस प्रकार प्रार्थी से 1984 में 240 दिन से अधिक कार्य लेना साबित हुआ है। यह साबित नहीं होता कि प्रार्थी को कोई नोटिस, नोटिस पे या छंटनी मुआवजा सेवा समाप्ति के समय दिया गया हो। इसलिये उसकी सेवा धारा 25-एफ अधिनियम की उल्लंघना में समाप्त की गई है जो कि अवैध है। दूसरे प्रार्थी से इतने वर्ष काम लेने और उसकी सेवायें 1-4-84 से समाप्त करने व उसके पश्चात् 1984 में ही फिर से काम लेना और प्रार्थी का 1984 में कुल 257 दिन कार्य करना कर्ता है कि प्रार्थी बैंक में दिनांक 1-4-84 को सेवा मुक्ति करने की शर्त पूरी की गई। इस प्रकार यह बैंक का अनुचित श्रम व्यवहार है इसलिये भी प्रार्थी की सेवायें अवैध रूप से समाप्त की गई हैं और प्रार्थी पुनः सेवा में लिये जाने योग्य है।

9. मेरे विचार में प्रार्थी के सिद्धान्त प्रतिनिधि के इस तर्क में कि किशन सिंह से कनिष्ठ व्यक्तियों को कार्य पर रखा गया, में कोई सार प्रतीत नहीं होता। विपक्षी के साक्ष्य श्री सुखदेव सिंह का शपथपत्र के पैरा नं. 10 में कथन है कि :

10. यह कि प्रार्थी कमेमेंट ने जो नाम अपने स्टेटमेंट आफ क्लेम में लिखे हैं उनमें से मुरली एवं प्रताप सिंह थू प्रोपर चैनल चुने गये स्थाई कर्मचारी हैं एवं मनमोहन सिंह स्थाई अपरासी प्रताप जी सिंह के छुट्टी चले जाने पर अस्थाई तौर पर इस अवधि विशेष के लिये ही रखा गया था एवं प्रताप

सिंह के छुट्टी से लौट आने पर उसकी अस्थाई सेवा समाप्त हो गई।”

10. अतः सुखदेव सिंह के शपथपत्र से यह साबित होता है कि मुरली व प्रताप सिंह को स्थाई तौर पर प्रोपर चैनल के माध्यम से रखा गया था और मनमोहन सिंह को प्रताप सिंह के छुट्टी चले जाने पर अस्थाई तौर पर लगाया गया था और उसके लौट आने पर मनमोहन सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इस प्रकार मुरली व प्रताप सिंह स्थाई हैं जब कि प्रार्थी स्थाई कर्मचारी नहीं था इसलिए प्रार्थी उसी संवर्ग में नहीं है जिसमें मुरली व प्रताप सिंह हैं। इसलिए धारा 25-जी अधिनियम की उल्लंघना साबित नहीं होती। मनमोहन सिंह को हटा दिया गया है क्योंकि उसे विशेष परिस्थितियों में छुट्टी में रखा गया था इसलिए धारा 25-एच अधिनियम की उल्लंघना भी साबित नहीं होती। दूसरे प्रदर्श एम-1 से प्रदर्श एम-51 जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि हुकम सिंह ने 1-5-86 से पूर्व कोई कार्य किया इसलिए हुकम सिंह का यह कथन कि कार्य उसने नहीं किया परन्तु वेतन उसके नाम से दिया गया, अपने आप ही गलत हो जाता है। इसी प्रकार प्रदर्श एम-49, एम-46, एम-42, एम-40 व एम-30 से यह साबित होता है कि धनराज ने 1-4-84 से पूर्व भी वेतन उठाया है। इस प्रकार उसका कथन कि उसने कार्य नहीं किया परन्तु उसे वेतन देना दिखाया गया अपने आप गलत हो जाता है। इसलिए किशन सिंह का यह कथन कि हुकम सिंह व धनराज से 85-86 में कार्य करवाया गया, माने जाने योग्य नहीं। अतः प्रार्थी की सेवाएं दिनांक 1-5-86 को 240 दिन कार्य करवाने पर भी बिना नोटिस, नोटिस पे व छंटनी का मुआवजा दिये समाप्त की गई है जो अवैध व अनुचित है और प्रार्थी पुनः सेवा में लिये जाने का अधिकारी है।

11. यह सेवा समाप्ति 1-5-86 की है और उसके बाद भी प्रार्थी ने कार्य किया है और ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति 11 वर्ष तक बेकार बैठा रहे इसलिए प्रकरण की परिस्थितियों में प्रार्थी को पिछले वेतन में उसका 50 प्रतिशत दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है जो प्रार्थी जनवरी 1987 से पाने का अधिकारी है।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित अवार्ड पारित किया जाता है :

“पंजाब एवं सिंध बैंक के प्रबंधतंत्र द्वारा प्रार्थी किशन सिंह की सेवाएं दिनांक 1-5-86 से समाप्त किया जाना अनुचित व अवैध है अतः प्रार्थी पुनः सेवा में आने लिये जाने का अधिकारी है। पिछले वेतन के रूप में विपक्षी बैंक प्रार्थी को उसके वेतन का 50 प्रतिशत अदा करेगा।”

18. अवार्ड आज दिनांक 18-10-97 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। अवार्ड की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजी जावे।

नई दिल्ली, 18 मई, 1998

कां० अ० 1140.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नेशनल इंसुरेंस कंपनी लि० के प्रबन्धन के सम्बन्ध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-17012/33/94-आई०आर० (बी० II)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 18th May, 1998

S.O. 1140.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of National Insurance Co. Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 15-5-1998.

[No. L-17012/33/94-IR (B-II)]
SANATAN, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी०आई०टी० 2/95

रैफरेंस: केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश
श्रमंक एल० 17012/33/94 दिनांक 26-12-94
घनश्याम भाटी पुत्र श्री घीसूलाल भाटी, निवासी 274,
जनता कॉलोनी, पाली (राज०)

—प्रार्थी श्रमिक

बनाम

क्षेत्रीय प्रबन्धक, नेशनल इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड, 10,
नारायणसिंह सक्लिन, जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी: श्री एस० के० बंसल, आर०एच०जे०एस०
प्रार्थी की ओर से: कोई हाजिर नहीं।

अप्रार्थी की ओर से: श्री आर० के० जैन, एवं श्री अमिताभ
मजूमदार।

दिनांक अर्वाह: 1-1-1998

अर्वाह:

यह अधिसूचना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा
निम्नलिखित विवादित बिन्दु का निर्णय करने के लिए
प्रेषित की गई है:—

“Whether the Contention of Shri Ghyanshyam
Bhati, ex-peon that the management of
National Insurance Co. Ltd., Jaipur have

terminated his services w.e.f. 23-2-1986,
illegally and that they have not given him
preferential opportunity for employment on
terms of Section 25-H of the I. D. Act
is correct? If so, what relief is the said
workman entitled to?”

प्रार्थी ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश किया और उसका
कथन है कि उसकी विपक्षी संस्थान में पाली स्थित ब्रांच
में 13-1-85 को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हुई थी।
और उसने लगातार कार्य किया। परन्तु उसकी 24-2-86
से सेवा गैर-कानूनी तौर पर समाप्त कर दी और नौकरी
से हटाए जाने से पूर्व कोई कारण नहीं बताया और न ही
उसे एक माह का नोटिस या नोटिस के बदले एक माह
का वेतन का ही भुगतान किया। इस प्रकार प्रार्थी की
सेवामुक्ति धारा 25 एफ के प्रावधानों के विपरीत है।
प्रार्थी का यह भी कथन है कि उसने सेवामुक्ति का विवाद
8-11-86 को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर के
समक्ष उठाया तथा 23-1-87 को प्रोमीडिंग्स में विपक्षी ने
कबूल किया कि जब भी नई भर्ती होगी प्रार्थी को बरीयता
दी जाकर उसे नियुक्ति का प्रथम अवसर प्रदान किया
जावेगा। परन्तु उसे नौकरी का अवसर नहीं दिया गया
और उसे नियुक्ति नहीं दी जाकर मंजू देवी, श्रम प्रकाश व
राजेश को जोधपुर ब्रांच में तथा युवराज सिंह व डूंगर सिंह
बाँधरी को बालोतरा ब्रांच में तथा बहादुर सिंह, राजेश
तथा राजकुमार को जयपुर स्थित ब्रांच में नौकरी दे दी
इसलिए धारा 25 (एच) औद्योगिक विवाद अधिनियम जो
बाद में अधिनियम कहलायेगा की उल्लंघना की गई है।
प्रार्थी का यह भी कथन है कि जब उसकी नौकरी से हटाया
गया तब उससे जूनियर श्रमिक सवाई सिंह कार्यरत था
जिसे बाद में स्थाई चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति दे दी। इस
प्रकार विपक्षी ने धारा 25 एफ जो एवं नियम 77 औद्योगिक
विवाद अधिनियम, 1947 का उल्लंघन किया है। प्रार्थी
का यह भी कथन है कि उसकी सेवा समाप्ति धारा 25
एफ, जी, एच एवं नियम 77 में की गई है इसलिए उसको
संवैतन सेवा में लिया जावे।

विपक्षी ने जवाब पेश किया और उसका कथन है कि
प्रार्थी ने 26-6-85 से 24-2-86 तक 135 दिन कार्य
किया था इसलिए वह कोई लाभ पाने का अधिकारी नहीं
है। विपक्षी का यह भी अभिकथन है कि प्रार्थी को
26-6-85 को कम्पनी की पाली स्थित शाखा कार्यालय,
जो कि प्रथम मंजिल पर स्थित है, तक पानी लाने के लिए
वैनिक आधार पर रखा गया था तथा उसका भुगतान प्रार्थी
को साप्ताहिक आधार पर किया जाता था। कम्पनी का
आगे यह भी कथन है कि भाटी को पूर्णतः आर्किस्मिक तौर
पर एक निश्चित कार्य के लिए रखा गया था। चूंकि प्रार्थी
एवं अप्रार्थी के मध्य किसी प्रकार का कोई श्रमिक एवं
नियोजन का सम्बन्ध नहीं था अतः प्रार्थी को सेवा समाप्त
किये जाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए
क्लेम खारिज किया जावे।

प्रार्थी ने प्रतिउत्तर पेश किया और विपक्षी के कथनों से इन्कार किया। और क्लेम स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

प्रार्थी ने अपना क्लेम साबित करने के लिए अपना शपथपत्र पेश किया जिस पर विपक्षी ने प्रतिपरीक्षण किया। विपक्षी की ओर से श्याम सिंह व आर० बी० गर्ग के शपथपत्र पेश किये। परन्तु प्रार्थी का उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति के कारण कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ और विपक्षी ने अपनी साक्ष्य बन्द की।

बहुस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि श्री आर० के० जैन का तर्क है कि प्रार्थी ने 26-6-85 से 24-2-86 तक 135 दिन कार्य किया था। इसलिए धारा 25 एफ अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते। और क्लेम खारिज किया जाये। विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि पाली शाखा में किसी भी दैनिक वेतनभोगी की नियुक्ति नहीं की गई और दैनिक वेतनभोगी को सेवा में आने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए क्लेम खारिज किया जाये। विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि ने इस तर्क के समर्थन में 1997(2) एल०एल०एन० के 982 उच्चतम न्यायालय हिमांशु कुमार विद्यमर्थी बनाम राज्य सरकार के बिहार वरिष्ठ पेश किया है।

मेरे विचार में विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि के तर्कों में काफी सार प्रतीत होता है। घनश्याम भारती प्रार्थी का शपथपत्र में कथन में 13-1-85 से 23-2-86 तक लगातार कार्य किया माने जाने योग्य नहीं है। प्रथम तो ये कि उसका प्रतिपरीक्षण में कथन है कि एजि० डब्लू 1 में 26-8-85 से 20-2-86 जो बात लिखी गई है वह गलत लिखी गई है। प्रवर्ष डब्लू 1 में प्रार्थी ने पाली शाखा में 26-8-85 से 20-6-86 तक कार्य करना बताया है और अब वह 13-1-85 से कार्य करना बताता है जो उसके स्वयं के प्रवर्ष डब्लू 1, का शपथपत्र के विपरीत कथन है जो माने जाने योग्य नहीं है। दूसरे श्याम सिंह व आर० बी० गर्ग के शपथपत्रों को न मानने का कोई कारण नहीं। इन शपथपत्रों से व एजि० एम 1 से यह साबित होता है कि प्रार्थी ने विपक्षी के यहां 26-6-85 से 24-2-86 तक 135 दिन कार्य किया। इस प्रकार प्रार्थी का 240 दिन कार्य करना नहीं पाया जाता। अतः धारा 25 एफ की उल्लंघना साबित नहीं होती इसलिए प्रार्थी 25 एफ का लाभ पाने का अधिकारी नहीं।

घनश्याम भारती का अपने शपथपत्र में या स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में कहीं कथन नहीं है कि उसके बाद किसी को पाली शाखा में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगाया गया हो। इसलिए धारा 25 एफ अधिनियम की उल्लंघना साबित नहीं होती। इसलिए धारा 25 एफ के अन्तर्गत प्रार्थी कोई लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

धारा 25 जी के बारे में कोई अधिसूचना नहीं है। इसलिए उस पर विचार नहीं किया जा सकता। दूसरे घनश्याम भारती का अपने शपथपत्र में 25 जी के बारे में कोई कथन नहीं है इसलिए 25 जी की उल्लंघना साबित नहीं होती। अतः प्रार्थी का क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

अतः निम्नलिखित अर्वाइड पारित किया जाता है:—

अतः व्यवस्थापक, नेशनल इंडस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड द्वारा घनश्याम भारती, चपरासी की सेवायें 23-2-86 से समाप्त करना उचित व वैध है और धारा 25 एच का कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी घनश्याम कोई वादरसी पाने का अधिकारी नहीं है।

अर्वाइड प्रकाशनार्थ भारत सरकार के श्रम विभाग को भेजा जावे।

अर्वाइड खुले न्यायालय में आज दिनांक 1-1-98 को सुनाया गया।

एस० के० बंसल, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का०आ० 1141.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-12012/145/93/आई०आर० (बी०-11)]

समाप्त, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1141.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 18-5-1998.

[No. L-12012/145/93-IR (B-II)]

SANATAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU

MADRAS

Monday, the 19th day of January, 1998

PRESENT :

Thiru S. Ashok Kumar, M.Sc., B.L., Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 98 of 1993

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of Central Bank of India, Madras).

BETWEEN

The workmen represented by

The General Secretary,
C. B. of India Employees Union,
P.B. No. 1579,
11, II Fine Beach,
Madras-600001.

AND

The Zonal Manager,
Central Bank of India,
P.B. No. 503,
48/49, Montieth Road,
Madras-600008.

REFERENCE :

Order No. L-12012/145/93-IR (B-II), Ministry of Labour, dated 4-10-93, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday, the 7th day of January 1998, upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Tvl. Aiyar and Dolia, R. Arumugam and B. Harbabu, Advocates appearing for the petitioner-union and of Thiru C. T. Selvam, Advocate for Management, and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following

AWARD

This reference has been made for adjudication of the following issue :

"Whether the action of the management of C.B.I. in imposing the punishment of 4 increments cut with cumulative effect in respect of Shri M. Muniappan is justified ? If not, to what relief he is entitled to ?"

2. On service of notices, both the petitioner and the respondent appeared before this Tribunal, and filed their claim and counter statement respectively.

3. The main averments found in the claim statement filed by the petitioner-union are as follows :

The petitioner workman was an active member of the petitioner-union and was working as clerk at Theni Branch of the respondent bank. The charge against the petitioner was that he had submitted a false LTC Bill and claimed money and thus committed gross misconduct and was asked to show cause against the charge. A reply was sent by the workman on 23-4-86 and 5-7-86 denying the charges. Charge memo dated 22-11-86 was issued and enquiry was conducted. After the enquiry finding were given on 6-2-87 by the Enquiry Officer holding that the workman was guilty of the charges. The disciplinary authority by his notice dated 2-4-87 agreed with the findings of the Enquiry Officer, workman was asked to show cause as to why the punishment of dismissal without notice should not be ordered against him. A personal hearing was given on 6-4-87 and final order passed on 30-4-87 imposing the punishment of stoppage of 4 increments with cumulative effect. The cause of the workman was espoused by the petitioner-union and industrial dispute was raised before the Asstt. Labour Commissioner (Central) vide letter dated 24-11-92. On behalf of the respondent bank,

a reply was submitted before the conciliation Officer. The conciliation failed and conciliation failure report was sent to Government and Government have referred this issue for adjudication. The punishment of stoppage of 4 increments with cumulative effect is wholly illegal and disproportionate to the charges even if it is proved. The enquiry conducted against the workman was opposed to the principles of natural justice and was not in conformity with the accepted norms of the department enquiry. The findings of the Enquiry Officer are perverse and not based on the evidence placed before him. The Enquiry Officer was also biased against the workman. During the enquiry the management instead of proving the charge against the workman, that he had not undertaken any journey with documentary or oral evidence demanded the workman to produce evidence for the journey. The onus of proving the charge though lay with the management, the entire exercise of the management before and during the enquiry was to insist for more and more evidence from the workman to prove that he had undertaken the journey, which is completely against the norms of the departmental enquiry. The findings of the Enquiry Officer was biased and predetermined and it is totally perverse. The charges levelled against the workman has not been proved in the enquiry. Punishment imposed on the workman based on the perverse findings of Enquiry Officer is not commensurate with the charge since the bank has mensurate with the charge since the bank has The punishment given to the workman is highly disproportionate to the misconduct said to have been committed by him and severity of the punishment is such that the workman would be losing substantially in his entire service due to the cumulative effect of the punishment. The respondent also failed to consider workman's unblemished record of service while imposing the punishment. The punishment imposed is totally contrary to and in violation of the Sastry Award and other settlements. The charge levelled against the workman is false and vexatious. The enquiry conducted against the workman is against the principles of natural justice and findings given by the Enquiry Officer was perverse and one-sided. The punishment inflicted on the workman is highly disproportionate to the misconduct alleged. The petitioner prays to pass an award holding that the punishment of stoppage of 4 increments with cumulative effect given to the workman as wholly unjust and direct the respondent to restore the increment withheld and pay the arrears and other benefits.

4. The main averments found in the counter statement filed by the respondent are as follows :

The present dispute has been raised under Sec. 2(k) of the I.D. Act, and the subject matter of the dispute is the justification of the punishment of stoppage of 4 increments to workman M. Muniappan. The workmen of the respondent bank have not taken up the cause of the concerned workman Muniappan nor the petitioner-union is competent or has the authority to raise this dispute. In the absence of a valid industrial dispute, the order of reference is invalid, and no adjudication can be made on the basis of the said reference. The concerned workman was employed as a Clerk in Theni branch. On 1-3-85, the concerned workman applied for leave from 1-4-85 to 10-4-85. On 27-3-85, a leave application for leave travel concession was given by the concerned workman stating that he intended to visit Ooty, Mysore, Bangalore, Madras and Madurai. On the same day, another letter opting for 4 years leave fare concessions was given by the workman. After return from leave on 8-5-85 the concerned workman made a claim for Rs. 1328.80 which included a sum of Rs. 1300 paid

to one Bharath Travel Service. Since the receipt of Bharth Travel Service showed that the workman visited Tirupathi which was not mentioned in his application for leave travel concession, on 9-5-85, a memo was issued to the concerned workman to produce available evidence for his stay for each of the places he visited. A reply was given by the concerned workman on 23-5-85 attaching a declaration by Bharath Travel Service giving the break up details for the expenses and also enclosing certain bus tickets and also tickets for admission to a cultural show at Bangalore and ticket issued by the Tamilnadu Horticultural Society, Ootacamund. As there was some discrepancy in the evidence produced by the concerned workman on 23-7-85, a letter was addressed to the Bharath Travel Service, Madurai calling upon to furnish the exact places of visit of Tourist Coach CAM 2020 during the period 4-4-85 and 5-4-85 and the lodging address where the tourists were allowed to stay during the relevant period. A letter dt. 26-7-85 was sent by Bharath Travel Service stating that the tour party started from Madurai on 4-4-85 by Coach CAM 2020 to Coimbatore, that it returned on 10-5-85, and that they were not aware as to where the party stayed in the various places visited by them. On a scrutiny of the evidence produced by the concerned workman, it was found out that out of 4 tickets issued by APSRTC, two tickets were meant for children. The concerned workman was asked to substantiate his claim by submitting a list of passengers who participated in the tour organised by Bharath Travel Service. But the same was not produced by the concerned workman. As no satisfactory explanation was given, a memo dated 29-3-86 was issued to the concerned workman calling upon to submit a list of passengers obtained from Bharath Travel Service and also explain the discrepancy in tickets issued by the Andhra Pradesh State Road Transport Corporation. But no acceptable explanation was given by the workman. A charge sheet dated 22-11-1986 was issued to the concerned workman charging him with the misconduct that leave travel concession bill with false declaration was submitted in support of his claim. Domestic enquiry was conducted and two witnesses were examined in support of the charges and 28 exhibits were marked. 5 witnesses were examined on behalf of concerned workman and 10 exhibits were marked. Enquiry Officer gave his report on 6-2-1987, after considering the evidence holding that the charge against the concerned workman was proved. Based on the report of the Enquiry Officer a show cause notice dated 2-4-1987 was issued to the concerned workman proposing a punishment of dismissal from service and calling upon him to appear for a personal hearing on 6-4-1987. The personal hearing was adjourned to 16-4-1987, the concerned workman appeared before the Disciplinary Authority and admitted that he did not go on tour and he pleaded guilty of the charge. He pleaded for lenience in punishment. Request was made by the concerned workman to the disciplinary authority to pardon him and award any punishment other than dismissal or discharge, and appealed for mercy. Based on the appeal made by the concerned workman, considering his family circumstances and taking a lenient and sympathetic view, the Disciplinary authority passed orders reducing the punishment to one of stoppage of four increments. Punishment of stoppage of 4

increments awarded to the concerned workman is fully justified and the same should not be interfered with. Domestic enquiry against the concerned workman was conducted in conformity with the principles of natural justice and the enquiry is not in any manner vitiated. The findings of the Enquiry Officer are based on the evidence placed before him and the said findings cannot be assailed. The punishment awarded to the concerned workman is perfectly valid in law and the same cannot be said to be excessive or harsh. It is denied that the Enquiry Officer was biased against the concerned workman. The documentary evidence which were admittedly in the handwriting of the concerned workman clearly showed that there was discrepancy in the claim and it was upto the concerned workman to explain the discrepancy. As the concerned workman had pleaded guilty to the charge in the personal hearing on 16-4-1987, it is not permissible for the petitioner to say that the concerned workman was not guilty of the charge. In the show cause notice dated 2-4-1987 a punishment of dismissal was proposed and in defence to the representation made by the concerned workman, a lesser punishment of stoppage of 4 increments was awarded by the Disciplinary Authority. The averments made by the petitioner-union are wholly devoid of merit. The power of the Industrial Tribunal and the Labour Court to interfere with the punishment under Sec. 11A of the I.D. Act, can be exercised only where a punishment of dismissal is imposed, and the same will not be available where the punishment is not dismissal. The punishment is a matter which cannot be interfered with by this Tribunal u/s. 11A except in the case of dismissal or discharge. The respondent prays to dismiss the award holding that the dispute as not maintainable.

5. No witness was examined on both sides and no exhibit was marked on the sides of the petitioner-union. Ex. M.1 to M.52 were marked on behalf of the respondent by consent.

6. The Point for our consideration is : Whether the action of management of C.B.I. in imposing the punishment of 4 increments cut with cumulative effect in respect of Shri M. Muniappan is justified ? If not, to what relief he is entitled to ?

7. The Point : The petitioner has been inflicted with a punishment of cut of four increments with cumulative effect for an alleged misconduct of claiming false leave travel concession. Before this Tribunal, the fairness of the domestic enquiry and the findings of the Enquiry Officer are not challenged. The only point for our consideration is whether the punishment of cut of four increments with cumulative effect is justified or disproportionate to the misconduct alleged against the petitioner. The learned counsel for the petitioner submitted that the punishment of cut of four increments with cumulative effect will cause a loss around 2.5 lakhs to the petitioner throughout his service and prayed to remove the clause with cumulative effect. In a case which has to be decided under Sec. 11-A of the I.D. Act, 1947 this Tribunal will have no jurisdiction to interfere with the minor punishments such as warning, fine, withholding of increment, demotion, suspension etc. Under Sec. 11-A of the I.D. Act, 1947 this Tribunal can interfere with the workman is discharged or dismissed and a

lesser punishment can be awarded in view of discharge or dismissal. The petitioner has neither been discharged nor dismissed. Even in Ex. M.2, the Disciplinary Authority has gone into the family status of the petitioner and after holding a lenient and sympathetic view, has awarded punishment of stoppage of four increments with cumulative effect. Since this Court cannot interfere with this minor punishment u/s. 11-A of the I.D. Act, 1947 the petitioner's claim is liable to be dismissed.

In the result, an award is passed dismissing the claim of the petitioner. No costs.

Dated, this the 19th day of January, 1998.

S. ASHOK KUMAR, Industrial Tribunal
WITNESSES EXAMINED

For both sides : None.

DOCUMENTS MARKED

For Petitioner : Nil.

For Management :

Ex. M. 1/30-4-87 : Memo issued by Asst. Regl. Manager to petitioner workman inflicting punishment. (copy)

Ex. M-2/30-4-87 : Memo issued by Disciplinary Authority to workman awarding punishment of stoppage of 4 increments. (copy)

Ex. M-3/16-4-87 : Proceedings of the Disciplinary Authority.

Ex. M-4/16-4-87 : Written statement submitted by workman to the Disciplinary authority (copy).

Ex. M-5/2-4-87 : Show cause memo issued to petitioner-workman

Ex. M-6/6-2-87 : Findings of the Enquiry Officer.

Ex. M-7/27-1-87 : Written arguments submitted by the defence representative to the Enquiry Officer.

Ex. M-8/22-1-87 : Letter from Enquiry Officer to the defence representative enclosing a copy of the written brief Presenting Officer.

Ex. M-9/19-1-87 : Written arguments of the Presenting Officer.

Ex. M-10/ : Enquiry Proceedings.

Ex. M-11/ : DEx1 marked in domestic enquiry.

Ex. M-12/ : DEx2 marked in domestic enquiry.

Ex. M-13/ : DEx3 marked in domestic enquiry.

Ex. M-14/ : DEx4 marked in domestic enquiry.

Ex. M-15/ : DEx5 marked in domestic enquiry.

Ex. M-16/ : DEx6 marked in domestic enquiry.

Ex. M-17/ : DEx7 marked in domestic enquiry.

Ex. M-18/ : DEx8 marked in domestic enquiry.

Ex. M-19/ : DEx9 marked in domestic enquiry.

Ex. M-20/ : DEx10 marked in domestic enquiry.

Ex. M-21/ : MEx1 marked in domestic enquiry.

Ex. M-22/ : MEx2 marked in domestic enquiry.

Ex. M-23/ : MEx3 marked in domestic enquiry.

Ex. M-24/ : MEx4 marked in domestic enquiry.

Ex. M-25/ : MEx5 marked in domestic enquiry.

Ex. M-26/ : MEx6 marked in domestic enquiry.

Ex. M-27/ : MEx7 marked in domestic enquiry.

Ex. M-28/ : MEx8 marked in domestic enquiry.

Ex. M-29/ : MEx9 marked in domestic enquiry.

Ex. M-30/ : MEx10 marked in domestic enquiry.

Ex. M-31/ : MEx11 marked in domestic enquiry.

Ex. M-32/ : MEx12 marked in domestic enquiry.

Ex. M-33/ : MEx13 marked in domestic enquiry.

Ex. M-34/ : MEx14 marked in domestic enquiry.

Ex. M-35/ : MEx15 marked in domestic enquiry.

Ex. M-36/ : MEx16 marked in domestic enquiry.

Ex. M-37/ : MEx17 marked in domestic enquiry.

Ex. M-38/ : MEx18 marked in domestic enquiry.

Ex. M-39/ : MEx19 marked in domestic enquiry.

Ex. M-40/ : MEx20 marked in domestic enquiry.

Ex. M-41/ : MEx21 marked in domestic enquiry.

- Ex. M-42/ : MEx22 marked in domestic enquiry.
- Ex. M-43/ : MEx23 marked in domestic enquiry.
- Ex. M-44/ : MEx24 marked in domestic enquiry.
- Ex. M-45/ : MEx25 marked in domestic enquiry.
- Ex. M-46/ : MEx26 marked in domestic enquiry.
- Ex. M-47/ : MEx27 marked in domestic enquiry.
- Ex. M-48/ : MEx28 marked in domestic enquiry.
- Ex. M-49/6-12-86 : Notice issued by the Enquiry Officer alongwith postal department receipt sent to petitioner workman.
- Ex. M-50/9-12-86 : Acknowledgement card for having received Ex. M.49.
- Ex. M-51/21-11-86 : Letter of appointment of Enquiry Officer by the Disciplinary authority.
- Ex. M-52/22-11-86 : Copy of charge sheet issued to petitioner-workman.

नई दिल्ली, 19 मई, 1998

का०आ० 1142.—श्रौद्धोगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार विजया बैंक के प्रबन्धतन्त्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निम्नलिखित श्रौद्धोगिक विवाद में श्रम न्यायालय, अरनाकुलम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-12012/353/92-आई.आर. (बी.-II)]

सनातन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th May, 1998

S.O. 1142.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Labour Court, Ernakulam as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Vijaya Bank and their workman, which was received by the Central Government on 18-5-98.

[No. L-12012/353/92-IR(B-II)]
SANATAN; Desk Officer

ANNEXURE

IN THE CENTRAL GOVERNMENT LABOUR COURT, ERNAKULAM

(Labour Court, Ernakulam)

(Monday, the 22nd day of December, 1997)

PRESENT :

Shri Varghese T. Abraham, B.A., LL.M.,
Presiding Officer.

Industrial Dispute No. 4 of 1993 (C)

BETWEEN :

The Divisional Manager, Vijaya Bank (Divisional Office), Hotel Pankaj Buildings,
Trivandrum-1 (Kerala)

AND

The Joint Secretary, Vijaya Bank Workers Organisation, 283, Phycrafts Road, Opp: Bata, Triplicate, Madras-600005.

REPRESENTATIONS :

Sri C.P. Sudhakara Prasad,
Advocate,

Ernakulam, Kochi-18. ... For management

Shri C. S. Rajan,
Advocate, M/s. Associated
Lawyers, Kochi-11.

.. For Union

AWARD

The Government of India as per Order No. 12012/353/92-IR (B-II) dated 17-2-93 referred the following industrial dispute for adjudication :

“Whether the action of the management of Vijaya Bank in imposing the punishment of stoppages of 2 (two) increments permanently, which will have the effect of postponing future increments, on Sri E. M. Rebelloe, Clerk; suspending him with effect from 8-7-1986 and treating the period of suspension not spent on duty and transferring him from Thootha Branch to Meppadi Branch for the same charges is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?”

2. The misconduct alleging to have conducted by the workman is as follows :

- “(i) Throwing slips before the Branch Manager in the presence of customers and speaking to the branch Manager in an insulting manner, amount to wilful insubordination, which is an act of gross misconduct under sub-clause (e) of clause 19.5 of Chapter XIX of the Bipartite Settlement 1966.
- (ii) Reading Newspaper during office hours while on duty, neglecting one's duty to render prompt and courteous service to customers, causing inconvenience to them, disregarding the instructions of the Branch Manager, constitute acts of subversive of discipline which are acts prejudicial to the interest of the Bank, amounting to gross misconduct under sub-clause (j) of clause 19.5 of Chapter XIX of the Bipartite Settlement, 1966.
- (iii) Misappropriating the amount of Jewel Appraisers' Commission collected by him, which is an act prejudicial to the interest of the Bank, which constitutes gross misconduct under sub-clause (j) of clause 19.5 of Chapter XIX of the Bipartite Settlement, 1966.”

Dissatisfied with explanation, enquiry was held. MWI conducted domestic enquiry. Accepting the findings of the enquiry officer the management imposed the above punishments which is confirmed in the appeal by the appellate authority.

3. According to the workman the charges were false and unsustainable and they were inconsistent. He requested the Joint General Manager to furnish copies of documents which were necessary to frame the defence. But on 7-11-86 he was informed that his request cannot be considered. So he was unable to file a detailed statement of defence. The enquiry was held on 7-5-87. The workman fell sick on 6-5-87. He required complete rest and he wanted to consult a doctor. So he sent a letter on 6-5-87 to MWI requesting to adjourn the enquiry to any date after three days. He stated that he will furnish the necessary medical certificate. There were no genuine reasons or valid grounds to throw out the request. The enquiry was held *ex parte*. The

venue of enquiry was also changed without notice. The findings of the enquiry officer was based on surmise and conjectures. Findings are perverse and unsustainable. The enquiry officer violated the principles of natural justice and principles of fair play. There is no evidence to substantiate the charge. Charge was amended. The conclusion is irresistible that it was stated in the enquiry with respect to the charge that the workman reading newspaper without attending to Sri Musthaffa on 7-4-86 and Sri P. Y. George on 19-4-86. The charge was amended by the management and substituted another customer Sri K. Sudhakaran in the place of Musthaffa and George. Charges 1 and 2 do not constitute misconduct. They are only minor misconduct. The allegation that charges committed are prejudicial to the management is vague. The representations made by the workman against the proposed punishment are easily brushed aside and rejected by the disciplinary authority. Punishment of stoppage of two increments permanently will have the effect of postponing his future increments, and it is awarded mechanically. The order of the disciplinary authority is erroneous, arbitrary and illegal. The workman had worked in stations like Mahalingapur, Manjeri, Uttar Pradesh. There is no bad antecedent. The penalty is disproportionate to the misconduct alleged against the workman. He prayed for setting aside the order of punishment.

4. The defence : The enquiry is legal, valid and proper. Sufficient opportunity was given to the workman. The workman did not turn up after reasonable time on 7-5-87. MWI received a letter dated 6-5-87 from the workman wherein he made request that he was not in a position to attend the enquiry for three days, as he was not doing well. It is also mentioned that he will be proceeding to meet a doctor for treatment and medical certificate will be produced. He made a request that the enquiry proposed to be held on 7-5-87 be adjourned to 9-5-87. Eventhough the letter was addressed to the Bangalore office address of MWI it was delivered to him on the day of enquiry, at the place of enquiry. The adjournment sought on the ground of ill health is not supported by any medical certificate. The letter is dated 6-5-87 and had the workman been really sick, he could have consulted a doctor on 6-5-87 itself and could have produced a medical certificate on 7-5-1987, on which date the workman had sent the letter dated 6-5-1987, through one Muhammedkutty. If the workman had

given a medical certificate on 7-5-87, the Bank would have got an opportunity to test the genuineness of the statement made by the workman by conducting a medical examination on him through the Bank's doctor. He informed the enquiry officer that Sri K. Viswanatha Naik, General Secretary, VBWO will be his defence representative and Sri Narayan Kumar, Joint Organising Secretary from Calicut will be assisting him. But none of them were present at Thootha Branch on the date of enquiry. The adjournment sought for by the workman was a pre-planned one. Otherwise the representatives of the workman would have been present at the enquiry on 7-5-1987. So the adjournment was sought as a pretext. The enquiry officer found the charge numbers 1 and 2 are proved and charge No. 3 is partly proved. Hence, he was inflicted the punishment of stoppage of 2 increments permanently for charge No. 1; 2 increments with perspective effect on charge No. 2 and stoppage of one increment permanently for charge No. 3. The punishments were directed to run concurrently. In effect only 2 increments are stopped permanently. The punishment is not excessive. He committed a grave misconduct and disciplinary authority considered the representation made by him to the proposed punishment. There is no illegality. The charges are proved. It is prayed for answering the reference against the workman.

5. A replication is filed by the union reiterating the averments in the claim statements and refuting the contention in the written statement. Ext. M1 is the domestic enquiry file. MW1 is the officer who conducted enquiry and prepared Ext. M1.

6. Heard both sides.

7. The Points which emerge for consideration are :

- (i) Whether the domestic enquiry is legal, valid and proper ?
- (ii) Whether the punishment imposed on the workman is liable to be interfered and if so to what extent ?

8. Point No. 1 : MW1 is the domestic enquiry officer. He is the senior manager of the management bank. He conducted enquiry into the charges levelled against the workman. He gave notice of time, date and venue of enquiry. According to him,

despite two postings he did not turn up. He conducted exparte enquiry. He examined 4 witnesses on the side of management and marked 22 documents. After closing the evidence he sent the entire proceedings to the delinquent along with the copies of documents and requested to submit his representation if any. He sent it by registered post on 8-5-87. To that notice the delinquent sent a reply requesting to grant 15 days time and that was granted as per letter dated 15-6-87. Again the delinquent requested one months' time as per letter dated 20-6-87. To that he sent a letter dated 2-7-87 by registered post informing him that already 45 days have been taken and no further extension of time will be granted. So on the basis of available evidence, he sent a detailed enquiry report. After submitting his findings, the delinquent submitted his written statement dated 11-7-87 and it was received by him on 20-7-87. As he had already submitted his findings on 14-7-87, the statement was sent to the disciplinary authority. He gave sufficient opportunity to the delinquent.

9. The first ground of attack is that delinquent requested for adjournment of the enquiry proposed to be held on 7-5-87 as per letter dated 6-5-87. It is stated by him that he was sick and he wanted to meet a doctor. It is sworn by MW1, the first notice was on 2-1-87 fixing the enquiry on 2-3-87 at Thootha Branch. The second notice was given on 20-3-87 fixing the enquiry on 7-5-87 at the very same branch. It can be seen from the letter dated 6-5-87 that he was sick and he wanted to meet a doctor. If that be so he could have obtained the medical certificate on 6-5-87 itself and requested for adjournment. He sent a messenger along with the letter. This will indicate that the prayer for adjournment was not genuine. So the enquiry officer was right in rejecting the prayer for adjournment as it was not genuine.

10. The second ground of attack is that the venue of enquiry was changed. MW1 admitted that he conducted the enquiry in the premises of Mansual (Madrassa Hall) just opposite to the Thoota branch. The enquiry was proposed to be held at Thoota branch. Madrasa Hall situates just opposite to the branch office. It can be seen from the findings of MW1 that he informed the branch manager, in case the workman turns up, he should be informed about the place of enquiry. Another reason for slight change for the venue is that there was no adequate space to put the table, chair etc.

at Thoota Branch without disturbing the customers. Moreover, according to MW1, it was not proper to conduct the enquiry in the branch office in the presence of customers. So the change of venue in the instant case has not prejudiced the workman. Moreover, he sent a message on 6-5-87 and that was handed over to the enquiry officer on 7-5-87. In these circumstances the shift in the venue of enquiry will not affect the validity of domestic enquiry. MW1 rejected the prayer for adjournment since the adjournment was sought on medical ground without any supporting medical certificate. So the prayer was not genuine. Moreover the enquiry officer after examining the management witnesses and marking the documents sent the entire proceedings and copies of the documents for furnishing written statement if any. If the grievance of the workman was genuine he could have applied to the enquiry officer to make available the management witness for cross examination. Instead of doing that he sought for 15 days time at first and 30 days time at the second occasion. Altogether 45 days were given to the workman. Another extension for 30 days was refused. He sought time as per letter dated 5-6-87 after giving the proceedings etc. and he have 15 days time as per my letter dated 15-6-87. In the instant case MW1 has done acts which are necessarily fair, reasonable, just and equitable. The prayer for adjournment was rightly refused by MW1, since it was found not genuine. When the workman was informed about the time, date and venue of enquiry and thereafter he fails to turn up, the enquiry officer cannot be blamed. The ex-parte enquiry is valid provided the workman is given sufficient opportunity like intimation of time, place and date of enquiry in advance. All necessary acts which will enable the workman to defend the charges are given to him by MW1. He has not availed of that opportunity. The proceedings paper will show that MW1 has conducted the enquiry in a fair, just and equitable manner. In his report he has discussed the entire evidence available to him. He found the charges as proved excepting one charge as partly proved. The workman was given opportunity to make his submission about the proposed punishment. The management has rightly inflicted the punishment. Suffice to hold that the enquiry is legal, valid and proper. Point so found.

11. Point No. 2 : The case on hand the inflicted punishment falls short of dismissal, discharge or

termination of service of workman. So section 11-A is not attracted. The Labour Court cannot interfere with minor punishments. In other words, it can interfere only with the punishments dealt with in section 11-A of the Industrial Disputes Act. Moreover the punishment is not harsh, unjust or excessive. No interference is called for. Point so found.

In the result, reference is answered holding that the action of the management of Vijaya Bank in imposing the punishment as stated above is justifiable and so the workman is not entitled to get any relief under industrial law.

Ernakulam,

22-12-1997

VARGHESE T. ABRAHAM, Presiding Officer

Appendix

Witness examined on the side of Management :

MW1. Sri. K. Ramdas Shetty.

Exhibits marked on the side of Management :

Ext. M1. Domestic enquiry file containing proceedings, report and other connected papers.

नई दिल्ली, 15 मई, 1998

कां०आ० 1143 :- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै० बी०सी०सी०एल० के प्रवर्धित के संबंध निधो-जकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं० 2), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15-5-98 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-24012/145/87-डी० IV (बी)/आईआर(सी-I)]

अजय कुमार, अनुभाग अधिकारी

New Delhi, the 15th May, 1998

S.O. 1143.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Govt. Industrial Tribunal, (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in

relation to the management of M/s. B.C.C.L. and their workman, which was received by the Central Government on 15-5-1998.

[No. L-24012|145|87-D. IB(B) IR(C-I)]

AJAY KUMAR, Section Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT
DHANBAD

PRESENT

Shri B. B. Chatterjee,
Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under
Section 10(1)(d) of the I.D. Act,
1947.

REFERENCE NO. 60 OF 1988

PARTIES :

Employers in relation to the management of
Jeaigora Colliery of Bhowra Area No.
XI of M/s. B.C.C. Ltd. and their work-
men.

APPEARANCES :

On behalf of the employers : None.

On behalf of the workmen : None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad, the 30th April, 1998

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-24012(145)|87-D. IV(B), dated the 11th February, 1988.

SCHEDULE

"Whether the action of the Management of Jeaigora Colliery of Bhowra Area No. XI of M/s. B.C.C. Ltd., P.O. Bhowra, Distt. Dhanbad in not regularising Sri Ram Sundar Singh, Stowing Mazdoor as Stowing Fitter is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

2. Soon after the receipt of the order of reference notices were duly served upon the parties. But neither of the parties turned up nor took any steps. Then again notices were issued to them but in spite of the issuance of notices to them they neither turned up nor took any steps. It therefore leads me to an inference that presently there is no dispute existing between the parties. In the circumstances, I have no other alternative but to pass a 'No dispute' in this Reference.

B. B. CHATTERJEE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 मई, 1998

का. आ. 1144 :—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री रत्नाकर ए. बंगेरा, अनुभाग अधिकारी, जवा संसाधन मंत्रालय को उत्प्रवास संरक्षी-II, मुंबई के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या. एम-11011/1/98-उत्प्रवास]

वी. डी. नागर, अध्वर सचिव

New Delhi, the 20th May, 1998

S.O. 1144.—In exercise of the powers conferred by Section 3, Sub-Section (1) of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby appoints Shri Ratnakar A. Bangera, Section Officer, in the Ministry of Water Resources as Protector of Emigrants-II, Mumbai with effect from 17th March, 1998.

[No. S-11011/198-Emig.]

V. D. NAGAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मई, 1998

का०आ० 1145 :—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम-10, उपा नियम (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्रम मंत्रालय के मन्त्र कार्यालय श्रम ब्यूरो, चण्डीगढ़ को एनडू द्वारा अधि-सूचित करती है।

[फा० संख्या-ई-11011/1/93 रा.भा.नो.]

पी०एम० सिराजुद्दीन, निदेशक

New Delhi, the 22nd May, 1998

S.O. 1145.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies Labour Bureau, Chandigarh an attached office of Ministry of Labour.

[F. No. E-11011/1/93-R.B.N.]

P. M. SIRAJUDDIN, Director

नई दिल्ली, 26 मई, 1998

का०आ० 1146 :—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 3184 दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 द्वारा इंडिया गवर्नमेंट मिनट, नोएडा को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 3 दिसम्बर, 1997 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के

लिए 3 जून, 1998 के छह मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा० सं० एस०-11017/01/94-आई.आर.(पी.एल.)]

एच०सी० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 26th May, 1998

S.O. 1146.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of section 2 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 3184 dated 3rd December, 1997 the services in India Government Mint, Noida to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 3rd December, 1997;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 3rd June, 1998.

[No. S-11017/1/94-IR(PL)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1998

का०आ० 1147 :—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि इंडिया गवर्नमेंट मिनट, हैदराबाद में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 11 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (३) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या० एस-11017/1/96-प्रौ.त० (नी०बि०)]
एच०सी० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 26th May, 1998

S.O. 1147.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in the India Government Mint, Hyderabad which is covered by item 11 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/1/96-IR(PL)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1998

का०आ० 1148 :—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि इंडिया गवर्नमेंट मिन्ट, चेरापल्ली में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची प्रविष्टि 11 के अन्तर्गत निदिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (३) के उपखंड (6) द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल

प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/3/98-प्रौ०त० (नी०बि०)]

एच०सी० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 26th May, 1998

S.O. 1148.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in India Government Mint, Cherlapally (Ranga Reddy) which is covered by item 11 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/3/98-IR(PL)]

H. C. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 मई, 1998

का०आ० 1149 :—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 12 के अन्तर्गत निदिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (३) के उपखंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल

प्रभाव से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस-11017/8/97-प्रौ०त० (नी०वि०)]

एच०सी० गुप्ता, अवर सचिव

New Delhi, the 26th May, 1998

S.O. 1149.—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services in Security Printing Press, Hyderabad which is covered by item 12 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act,

1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

H. C. GUPTA, Under Secy.
[No. S-11017/8/97-IR(PL)]

